₹ 49/-

TOPPERS CLUB
IAS ACADEMY

Monthly
CURRENT AFFAIRS
By - Toppers Club

Mar-2026

Er Dev Pratap Singh
Director

Contact Us
+91 6388671098
dpsctc@gmail.com
www.topperclubiasacademy.in

IAS | IPS | PCS | IFS | IRS & OTHER COMPETITIVE EXAMS

अरावली में क्या हो रहा है?
पुनर्परिभाषा विवाद विस्तार से

विश्व समाचार
तेल, प्रतिबंध व बेला-1 समुद्री पीछा
ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं ?
ईरान: निर्वासित राजकुमार के बयान से विरोध भड़के
म्यांमार जुंटा द्वारा गृहयुद्ध में चुनाव

राजनीति व कानूनी जंग
I-PAC विवाद: ED छापे व बंगाल हंगामा
माह के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
मुख्य कानूनी व संवैधानिक घटनाक्रम

अर्थव्यवस्था व ऊर्जा
बुल्गारिया ने अपनाई यूरो मुद्रा
जापान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर चालू

डेल्सी रोड्रिगेज़

14 जून 2018 को राष्ट्रपति मादुरो ने रोड्रिगेज़ को वेनेज़ुएला की उपराष्ट्रपति नियुक्त किया। उन्होंने टारेक एल ऐसामी का स्थान लिया। इसके साथ ही वे बोलिवेरियन इंटेलिजेंस सर्विस (SEBIN)—जो वेनेज़ुएला की खुफिया एजेंसी है—की प्रमुख अधिकारी भी बनीं, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति कार्यालय के अधीन कार्य करती है।

Toppers Club IAS Acacdemy
All Copyright Reserved

Contact Info:
Phone No: +91 6388671098
Mail: dpsctc@gmail.com
Website: www.topperclubiasacademy.in

अस्वीकरण

यह पुस्तक विशेष रूप से शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। लेखक(ों) द्वारा यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है कि किसी भी मौजूदा कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन न हो। यदि किसी स्रोत का अनजाने में उल्लेख नहीं किया गया है या किसी प्रकार का अनचाहा उल्लंघन हुआ है, तो कृपया प्रकाशक को लिखित रूप में सूचित करें ताकि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जा सके।

हालाँकि सामग्री की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा की गई है, फिर भी अनजाने में कुछ त्रुटियाँ या चूक हो सकती हैं। किसी भी पाई गई विसंगति को आगामी संस्करणों में ठीक किया जाएगा। लेखक(ों), प्रकाशक और वितरक इस पुस्तक में दी गई जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कानूनी, तथ्यात्मक या महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोतों से परामर्श करें।

बाइंडिंग में दोष, प्रिंटिंग में त्रुटि या पृष्ठों की कमी जैसी समस्याओं के मामलों में प्रकाशक की ज़िम्मेदारी केवल उसी या समकक्ष संस्करण की दोषपूर्ण प्रति के प्रतिस्थापन तक ही सीमित है। प्रतिस्थापन के लिए अनुरोध खरीद की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इससे संबंधित सभी लागतें, जैसे कि शिपिंग, क्रेता द्वारा वहन की जाएंगी।

सर्वाधिकार सुरक्षित

इस प्रकाशन के किसी भी भाग को बिना प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी रूप में—चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोग्राफिक या अन्य कोई माध्यम हो—प्रतिलिपि, संग्रह या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। बिना अनुमति के उपयोग, पुनरुत्पादन या वितरण के परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

लेखक इस कृति की मूल सामग्री पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, सिवाय उन उद्धरणों के जहाँ उपयुक्त अनुमति के साथ स्रोत का उल्लेख किया गया है। यह प्रकाशन किसी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है, और इसमें कोई मानहानिकारक सामग्री सम्मिलित नहीं है।

प्रिय अभ्यर्थियों,

"तैयारी भावी नेताओं की मौन क्रिया है; आज पढ़ा हर पन्ना कल के निर्णयों को आकार देता है।"

सिविल सेवक बनने की यात्रा केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच, विषयों के बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता और बदलती दुनिया के प्रति गहरी समझ से तय होती है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए करंट अफेयर्स तैयारी की रीढ़ हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण—तीनों चरणों में गहराई से जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का निरंतर अध्ययन अभ्यर्थियों में विश्लेषणात्मक दृष्टि, बहुआयामी समझ और नीति-आधारित सोच विकसित करता है, जिसकी अपेक्षा सिविल सेवा परीक्षा करती है।

जैसा कि कहा गया है— "उत्कृष्टता कोई एक कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है।" करंट अफेयर्स का नियमित और अनुशासित अध्ययन जानकारी को अंतर्दृष्टि में बदलता है और विचारों को संतुलित तर्कों का रूप देता है। यह अभ्यास मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन को सशक्त बनाता है, प्रारंभिक परीक्षा में विकल्पों को छाँटने की क्षमता विकसित करता है और भावी प्रशासकों के लिए आवश्यक बौद्धिक परिपक्वता प्रदान करता है।

यह मासिक अंक जटिल समकालीन मुद्दों को स्पष्टता और व्यापक दृष्टिकोण के साथ समझाने के उद्देश्य से संकलित किया गया है। पर्यावरणीय शासन से जुड़े विषयों में अरावली पर्वतमाला की पुनर्परिभाषा से उत्पन्न विवाद का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो विकास, कानूनी व्याख्या और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन को उजागर करता है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति के क्षेत्र में बेला-1 समुद्री पीछा मामला तेल व्यापार, प्रतिबंधों और वैश्विक प्रवर्तन तंत्र के जटिल संबंधों को सामने लाता है, वहीं ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की रुचि को रणनीतिक संसाधनों और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझाया गया है।

वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता के परिप्रेक्ष्य में, निर्वासित राजकुमार की अपील से ईरान में भड़के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का विश्लेषण राज्य की वैधता, जन असंतोष और शासन की प्रतिक्रिया को समझने में सहायक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में पीएसएलवी-सी62 मिशन की विफलता पर चर्चा की गई है, जो इसरो के विश्वसनीय इतिहास में एक दुर्लभ झटका होने के साथ-साथ संस्थागत लचीलापन और सीख के महत्व को रेखांकित करती है। आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रमों के अंतर्गत आई-पैक विवाद को शामिल किया गया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी, राजनीतिक प्रभाव और पश्चिम बंगाल में चल रही कानूनी प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है।

यह अंक क्षेत्रीय और वैश्विक समझ को और व्यापक बनाते हुए यह स्पष्ट करता है कि म्यांमार की सैन्य जुंटा गृहयुद्ध के बीच चुनाव क्यों करवा रही है—जो सत्ता, वैधता और संघर्ष प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करता है। साथ ही, जापान द्वारा विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय ऊर्जा सुरक्षा, सुरक्षा चिंताओं और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन को दर्शाता है।

इस पत्रिका का प्रत्येक लेख तथ्यों से आगे बढ़कर आपको नीति-निर्माता की तरह सोचने और प्रशासक की तरह लिखने के लिए प्रेरित करता है। जिज्ञासा के साथ पढ़ें, अनुशासन के साथ चिंतन करें और उद्देश्य के साथ तैयारी करें। आज विकसित की गई आपकी आदतें ही कल राष्ट्र की सेवा में लिए जाने वाले आपके निर्णयों की दिशा तय करेंगी।

"पढ़ो। सोचो। ज्ञान के साथ राष्ट्र की सेवा करो।"

इस संस्करण में शामिल हैं

राजतन्त्र एवं शासन 5
- आई-पैक विवाद: ED की छापेमारी, राजनीतिक हंगामा और बंगाल में कानूनी लड़ाई
- रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI)
- लिव-इन रिलेशनशिप: महिलाओं को कानूनी सुरक्षा की ज़रूरत
- सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 संशोधन
- ऑनर किलिंग कानून
- निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025
- जन विश्वास (संशोधन) विधेयक
- समाचार संक्षिप्त में

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ 12
- म्यांमार गृहयुद्ध (2021–वर्तमान)
- ईरान में उथल-पुथल
- बेला-1 / मरीनरा मामला
- UAE में डेटा एम्बेसी
- ऑटोनॉमस टेरिटरी
- समाचार संक्षिप्त में

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार 25
- यूरोज़ोन
- दोरजीलुंग हाइड्रो प्रोजेक्ट
- LIC डीमर्जर
- SIDBI से MSME
- समाचार संक्षिप्त में

रक्षा एवं सुरक्षा 31
- डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड
- प्रलय मिसाइल
- पिनाका रॉकेट
- समाचार संक्षिप्त में
- माह का सैन्य अभ्यास

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 36
- अरावली पुनर्परिभाषा विवाद
- कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (राजस्थान)
- अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य
- भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म
- समाचार संक्षिप्त में

सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ 41
- मुख्यमंत्री सेहत योजना
- REPM योजना
- LIC की ग्रामीण और सेमी-अर्बन भारत में पहुँच

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 43
- PSLV-C62 मिशन
- काशिवाज़ाकी-कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट
- आर्टेमिस II मिशन
- PARAM रुद्र सुपरकंप्यूटर
- भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ
- समाचार संक्षिप्त में

संस्कृति एवं इतिहास 50
- महाराष्ट्र में पुरातात्विक खोज
- वंदे मातरम के 150 साल
- गणतंत्र दिवस पर SVAMITVA योजना
- भारत की सांस्कृतिक भावना और WAVES विज़न
- समाचार संक्षिप्त में

चर्चित व्यक्तित्व 56
- नियुक्तियाँ
- निधन

खेल-कूद 58
परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण दिन 60
पुस्तकें एवं लेखक 61

PROTECTED COPYRIGHT PROTECTED

बिजनेस न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमी न्यूज, पॉलिटिक्स न्यूज, इंडिया न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज एवं कई अन्य विषयों को कवर किया गया .....

समाचार साभार

बीबीसी, रॉयटर्स, अल जज़ीरा, पीआईबी, पीटीआई, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिज़नेस लाइन, इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल एवं अन्य सभी प्रमुख समाचार पत्र

राजतन्त्र एवं शासन

आई-पैक विवाद: ED की छापेमारी, राजनीतिक हंगामा और बंगाल में कानूनी लड़ाई

आई-पैक विवाद क्या है?

आई-पैक विवाद पश्चिम बंगाल में चल रहे एक बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद से जुड़ा है, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़ी राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) के ऑफिस और डायरेक्टर के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी पर केंद्रित है। यह विवाद एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल गया है, जिसमें रुकावट डालने, डेटा जब्त करने, कानूनी लड़ाइयों और TMC नेताओं के विरोध प्रदर्शन के आरोप शामिल हैं।

I-PAC कौन है?

- इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) एक राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है।
- इसने चुनाव रणनीति, IT, मीडिया और कैंपेन मैनेजमेंट में TMC के साथ मिलकर काम किया है।
- इसकी स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी, हालांकि अभी इसका संचालन प्रतीक जैन सहित डायरेक्टर कर रहे हैं।

ED ने I-PAC पर छापा क्यों मारा?

- प्रवर्तन निदेशालय ने 8 जनवरी 2026 को तलाशी अभियान शुरू किया।
- यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल में कथित कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थी।
- ED का आरोप है कि अवैध कोयला बिक्री से मिले अपराध की रकम हवाला चैनलों के ज़रिए भेजी गई, जिसमें कुछ फंड I-PAC से जुड़े ऑपरेशन्स से जुड़े थे।
- तलाशी I-PAC के कोलकाता ऑफिस और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर की गई।

राजनीतिक विवाद कैसे शुरू हुआ?

- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छापेमारी वाली जगह पर पहुंचीं और ED के अनुसार, उन्होंने दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक डेटा हटा दिए, जिससे एजेंसी ने दावा किया कि जांच में बाधा डाली गई।
- TMC और राज्य अधिकारियों ने गलत काम से इनकार किया है और छापेमारी की वैधता को चुनौती दी है।
- कोलकाता पुलिस ने ED कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें अवैध रूप से घुसने और सामान जब्त करने का आरोप लगाया गया।

कानूनी मामले

- कलकत्ता हाई कोर्ट छापेमारी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें जब्त किए गए डेटा और जांच के तरीके पर विवाद शामिल हैं।
- ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ रुकावट डालने और सबूतों से छेड़छाड़ के लिए CBI FIR दर्ज करने के निर्देश मांगे गए हैं।
- TMC ने डेटा की सुरक्षा और ED के अधिकार को चुनौती देने के लिए जवाबी याचिकाएं दायर की हैं।
- कोर्ट की कार्यवाही में रुकावटें आई हैं और कोर्ट के आदेश पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है।

यह क्यों मायने रखता है?

- यह विवाद केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच तनाव, राजनीतिक डेटा की गोपनीयता से जुड़े मुद्दे और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनावी माहौल में प्रवर्तन शक्तियों के इस्तेमाल पर चिंताओं को उजागर करता है।

रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI)

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने नई दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 लॉन्च किया है, ताकि नैतिक शासन और साझा जिम्मेदारी के आधार पर देशों का मूल्यांकन करने के लिए एक वैकल्पिक वैश्विक ढांचा प्रदान किया जा सके।

- आयोजक: वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (WIF)।
- यह इंडेक्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) मुंबई जैसे संस्थानों के तीन साल के रिसर्च का नतीजा है।

रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) क्या है?

RNI एक व्यापक मूल्यांकन उपकरण है जो देशों को नैतिक शासन, मानव कल्याण, पर्यावरणीय प्रबंधन और वैश्विक जिम्मेदारी के आधार पर मापता है - यह GDP या सैन्य शक्ति जैसे पारंपरिक मापों से परे है। यह पूरी तरह से आर्थिक या शक्ति-आधारित मापदंडों के बजाय स्थायी और न्यायसंगत विकास पर जोर देता है।

मुख्य रैंकिंग (शीर्ष और भारत की स्थिति – RNI 2026)

देश	RNI रैंक
सिंगापुर	1
स्विट्जरलैंड	2
डेनमार्क	3
स्वीडन	5
भारत	16

RNI क्यों महत्वपूर्ण है?

वैकल्पिक विकास मापदंड: यह केवल GDP पर ध्यान केंद्रित करने वाले नवउदारवादी विकास मॉडल को चुनौती देता है, जिसमें शासन और सामाजिक जिम्मेदारी को शामिल किया गया है। नैतिक शासन: यह पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवाधिकार, समानता और न्याय पर जोर देता है, जो सिविल सेवाओं के लिए शासन की गुणवत्ता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय प्रबंधन: यह SDGs (सतत विकास लक्ष्य) और पेरिस जलवायु समझौते जैसे वैश्विक ढांचों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुरूप है। विदेश नीति की समझ: यह शक्ति की राजनीति से परे वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है - नैतिक और सहकारी नेतृत्व।

अन्य वैश्विक सूचकांकों से तुलना

- मानव विकास सूचकांक (HDI): स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर केंद्रित है (UNDP)।
- वैश्विक शांति सूचकांक (GPI): सुरक्षा, संरक्षा और सैन्यीकरण के आधार पर शांति को मापता है।
- RNI का अनूठा दृष्टिकोण: यह नैतिक शासन और वैश्विक जिम्मेदारी को जोड़ता है, घरेलू नीति की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय योगदान के साथ मिलाता है।

भारत के लिए प्रासंगिकता

भारत की रैंक (16) सामाजिक नीतियों, शासन ढांचे में ताकत को दर्शाती है, लेकिन पर्यावरणीय स्थिरता या वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश भी दिखाती है। यह भारत के G20 विजन का समर्थन करता है जहां समावेशी विकास और स्थिरता पर जोर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय नीति संबंध

यह आर्थिक उपायों से हटकर समग्र मानव-केंद्रित प्रगति की ओर बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र 2030 सतत विकास एजेंडा के अनुरूप है।

लिव-इन रिलेशनशिप: महिलाओं को कानूनी सुरक्षा की ज़रूरत

चर्चा में क्यों?

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को "पत्नी" का कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। यह बात रिश्तों के टूटने पर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए कही गई।

मामले की पृष्ठभूमि

यह फैसला एक ऐसे आदमी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए आया, जिस पर शादी के झूठे वादे करके एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप था। महिला ने आरोप लगाया कि आदमी ने बार-बार शादी का वादा किया और साथ रहने के बाद मुकर गया।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोर्ट की चिंता

कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं शादी जैसी कानूनी सुरक्षा न होने के कारण कमजोर होती हैं। कई महिलाएं यह सोचकर लिव-इन रिलेशनशिप में आती हैं कि यह एक आधुनिक विकल्प है, लेकिन बाद में रिश्ता खत्म होने पर उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती।

सांस्कृतिक संदर्भ

जज ने लिव-इन रिलेशनशिप को भारत में एक सांस्कृतिक झटका बताया, लेकिन यह भी कहा कि अब ये काफी आम हो गए हैं। कोर्ट ने प्राचीन भारतीय परंपरा के गंधर्व विवाह का हवाला दिया, जो सहमति से बने प्रेम संबंधों की एक समानांतर अवधारणा है।

लागू किया गया कानूनी प्रावधान

कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 69 का इस्तेमाल किया, जो धोखे या शादी के झूठे वादों पर आधारित यौन संबंधों को अपराध मानती है। इसमें कहा गया कि जो पुरुष शादी का वादा करके बाद में मुकर जाते हैं, वे कानूनी नतीजों से बच नहीं सकते।

शोषण पर टिप्पणियाँ

कोर्ट ने पाया कि कुछ पुरुष शुरू में लिव-इन रिलेशनशिप में आकर खुद को आधुनिक दिखाते हैं, लेकिन जब चीजें गलत होती हैं तो वे महिला के चरित्र पर हमला करते हैं।

फैसले का महत्व

यह फैसला लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा में कमी को उजागर करता है। यह सुझाव देता है कि ऐसे रिश्तों को कानूनी तौर पर सहमति से हुई प्रेम विवाह की तरह देखा जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं असुरक्षित न रहें।

सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के तहत नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर यूजर फीस पेमेंट के पालन को मज़बूत करने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 को नोटिफाई किया है।

संशोधन के मुख्य प्रावधान

"अदा न की गई यूजर फीस" की परिभाषा:

यह संशोधन अदा न की गई यूजर फीस की एक औपचारिक परिभाषा पेश करता है — नेशनल हाईवे के इस्तेमाल के लिए देय टोल चार्ज, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम ने वाहन के गुज़रने को रिकॉर्ड किया है, लेकिन नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के अनुसार फीस नहीं मिली है।

NOC का सशर्त जारी होना:

वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर (अंतर-राज्यीय ट्रांसफर सहित) के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक सभी बकाया यूजर फीस क्लियर नहीं हो जाती।

फिटनेस और परमिट सेवाओं से लिंक:

अगर अदा न की गई यूजर फीस बकाया है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे कि सड़क पर चलने लायक होने का रिन्यूअल और कमर्शियल वाहनों के लिए नेशनल परमिट जारी करना रोक दिया जाएगा।

अपडेटेड फॉर्म 28:

फॉर्म 28, जिसका इस्तेमाल NOC के लिए अप्लाई करने के लिए किया जाता है, अब आवेदक से किसी भी लंबित बकाया टोल फीस और उन फीस की डिटेल्स घोषित करने की मांग करता है।

इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग पर फोकस:

इन बदलावों का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना और नेशनल हाईवे पर टोल चोरी को रोकना है।

कानूनी ढांचा:
मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 केंद्र सरकार को मोटर वाहनों और परिवहन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है; सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 इसी एक्ट के तहत बनाए गए थे। नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 नेशनल हाईवे के इस्तेमाल के लिए यूजर फीस के कलेक्शन को नियंत्रित करता है और टोल पेमेंट के लिए कानूनी आधार तय करता है।

डिजिटल टोलिंग संदर्भ:
भारत ने FASTag के साथ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) को बड़े पैमाने पर लागू किया है, जो बिना किसी रुकावट के टोल पेमेंट के लिए बैंक खातों या डिजिटल वॉलेट से जुड़ा एक प्रीपेड RFID टैग है। पिछले बदलावों (2025 से) ने टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नॉन-FASTag यूज़र्स पर ज़्यादा टोल फीस (नकद में दोगुना और UPI के ज़रिए 1.25 गुना तक) लगाकर जुर्माना लगाया था।

बैरियर-फ्री और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF):
संशोधित नियम मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग को सपोर्ट करते हैं, जो भीड़ कम करने और हाईवे पर आवाजाही को तेज़ करने के लिए RFID/GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिना बैरियर के टोलिंग को संभव बनाता है।

प्रशासनिक प्रभाव:
टोल बकाया को रजिस्ट्रेशन सेवाओं, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट से जोड़ने से नियमों का पालन मज़बूत होता है और यह सुनिश्चित होता है कि बिना चुकाए शुल्क से बचा नहीं जा सकता।

परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन:
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) NOC जारी करने, फिटनेस रिन्यूअल या नेशनल परमिट देने से पहले इन प्रावधानों को लागू करेंगे, जिससे वाहनों की रीसेल और कमर्शियल संचालन प्रभावित हो सकता है।

ऑनर किलिंग कानून

चर्चा में क्यों?
कर्नाटक सरकार ऑनर किलिंग को रोकने के लिए एक खास कानून बना रही है। यह कदम हुबली में 20 साल की मान्या पाटिल की हत्या के बाद उठाया गया है, जिसे कथित तौर पर उसके परिवार ने एक अनुसूचित जाति के आदमी से शादी करने के लिए मार डाला था। ऑनर किलिंग "पारिवारिक सम्मान" के नाम पर जाति या समुदाय आधारित हत्याएं होती हैं।

प्रस्तावित कानून का नाम क्या है
इस ड्राफ्ट कानून का नाम 'एवा नम्मावा एवा नम्मावा कानून, 2026' है। यह वाक्यांश 12वीं सदी के बसवन्ना के एक वचन से लिया गया है, जो भाईचारे और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है।

कानून का मकसद क्या है
इसका मकसद ऑनर किलिंग और उससे जुड़े जाति-आधारित अपराधों को सख्ती से सज़ा देना है। यह वयस्कों के अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की भी रक्षा करेगा, जिसके लिए परिवार या जाति की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होगी। यह कानून "सम्मान के नाम पर" किए गए कई तरह के कामों को कवर करेगा, जिसमें शारीरिक नुकसान, धमकियां, उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार, जोड़ों को जबरन अलग करना और डराना-धमकाना शामिल है।

कानूनी अधिकारों को मज़बूत किया गया
यह ड्राफ्ट कानून पुष्टि करता है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार शादी की पसंद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूरी तरह से लागू होते हैं।

प्रस्तावित सज़ा
- ऑनर किलिंग के लिए कम से कम पांच साल की जेल।
- सम्मान के नाम पर गंभीर चोट: 10 साल से उम्रकैद और ₹3 लाख तक का जुर्माना।
- साधारण चोट: तीन से पांच साल की जेल और ₹2 लाख तक का जुर्माना।
- अन्य सम्मान अपराध या अधिकारों का उल्लंघन करने वाले काम: दो से पांच साल की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना।

- सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

अतिरिक्त प्रावधान
यह कानून सरकार के लिए उन जोड़ों को सुरक्षा और बचाव के उपाय देना अनिवार्य कर देगा जिन्हें खतरा है। यह अंतर-जातीय संदर्भों में शादी के झूठे वादे से यौन संबंध बनाने के लिए एक नया अपराध भी पेश करता है।

यह कानून महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है
तथाकथित ऑनर किलिंग मौजूदा कानूनों के तहत तकनीकी रूप से अलग अपराध नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता के तहत उन्हें सामान्य "हत्या" माना जाता है। एक खास कानून का मकसद जाति-आधारित और सम्मान से जुड़े अपराधों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से उजागर करना और सज़ा देना है।

व्यापक संदर्भ
ऑनर किलिंग अक्सर जाति-विभाजित समाजों में होती है जब व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या समुदाय के बाहर पार्टनर चुनते हैं, और परिवार इसे "इज्जत" के लिए खतरा मानते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग को हत्या के बर्बर कृत्यों के रूप में निंदा की है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025

चर्चा में क्यों?
संसद ने पुराने कानूनों को खत्म करके और चुनिंदा मौजूदा अधिनियमों में छोटे-मोटे संशोधन करके भारत की कानूनी प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाने के लिए निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025 पारित किया है, जिससे विधायी उलझन कम होगी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।

मुख्य बातें
- यह अधिनियम 71 पुराने और बेकार कानूनों को खत्म करता है जो समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो चुके थे।
- ये कानून औपनिवेशिक काल और हाल के दशकों के बीच बनाए गए थे लेकिन अब उपयोग में नहीं थे।
- यह अधिनियम कुछ मौजूदा कानूनों में विसंगतियों को दूर करने और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन भी करता है।
- एक बचत खंड यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों को खत्म करने से मौजूदा अधिकारों, देनदारियों, दंडों या चल रही कानूनी कार्यवाही पर कोई प्रभाव न पड़े।

1. निरसन और संशोधन अधिनियमों का उद्देश्य
ऐसे अधिनियम समय-समय पर पारित किए जाते हैं:
- पुराने और ओवरलैपिंग कानूनों को हटाने के लिए
- कानून की किताबों को सरल बनाने के लिए
- शासन में आसानी और कानूनी स्पष्टता में सुधार के लिए

2. शासन के लिए महत्व
- नागरिकों, प्रशासकों और अदालतों के लिए कानूनी भ्रम कम करता है।
- अप्रयुक्त कानूनों को खत्म करके न्यायिक बोझ कम करने में मदद करता है।
- न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के सरकार के एजेंडे का समर्थन करता है।

3. संवैधानिक पहलू
- संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत संसद के पास कानूनों को खत्म करने या संशोधित करने का अधिकार है।
- बचत खंड के कारण निरसन से पहले से ही निरस्त कानूनों के तहत की गई कार्रवाई अमान्य नहीं होती है।

4. ऐतिहासिक संदर्भ
भारत ने कानूनी सुधारों के हिस्से के रूप में 2015, 2016, 2017, 2019 और 2023 में पहले भी इसी तरह के अधिनियम पारित किए हैं। पुराने कानूनों को खत्म करना कानूनी प्रणाली के युक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

5. व्यापार करने में आसानी से प्रासंगिकता
सरलीकृत कानूनी ढांचा नियामक पारदर्शिता में सुधार करता है।
व्यवसायों और संस्थानों पर अनुपालन बोझ कम करता है।

जन विश्वास (संशोधन) विधेयक

चर्चा में क्यों?
दिल्ली कैबिनेट ने छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और कंप्लायंस प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 को मंज़ूरी दे दी है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों के लिए यह आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह विधेयक आपराधिक आरोपों को सिविल दंड, प्रशासनिक जुर्माने और एक अपीलीय तंत्र से बदलकर अदालतों पर बोझ कम करेगा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों पर सख्त आपराधिक कार्रवाई जारी रहेगी, और उम्मीद है कि यह विधेयक दिल्ली विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में जुर्माने का स्वचालित संशोधन शामिल है - महंगाई और लागत के अनुरूप रखने के लिए हर तीन साल में दंड में 10% की वृद्धि की जाएगी, और इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों या नए प्रशासनिक पदों की आवश्यकता नहीं होगी।

जन विश्वास सुधार ढांचे के बारे में
जन विश्वास पहल एक कानूनी सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य कानूनों में छोटे और प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम ने केंद्रीय कानूनों में सैकड़ों छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसी तरह के सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

दंड के आनुपातिकता का सिद्धांत
यह विधेयक आनुपातिकता के कानूनी सिद्धांत को दर्शाता है, जहां दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होता है, जिससे मामूली उल्लंघनों के लिए आपराधिक अभियोजन से बचा जा सके।

सिविल दंड बनाम आपराधिक प्रतिबंध
सिविल दंड में जुर्माना, प्रशासनिक प्रतिबंध और अपील शामिल हैं, जो मामूली चूक के लिए गिरफ्तारी, कारावास या आपराधिक रिकॉर्ड से बचाते हैं। यह मुकदमेबाजी, अदालतों में लंबित मामलों और व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए परेशानी को कम करने में मदद करता है।

संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित कानून
यह विधेयक कई प्रमुख दिल्ली अधिनियमों में बदलाव का प्रस्ताव करता है जो निम्नलिखित को नियंत्रित करते हैं:
- दुकानें और प्रतिष्ठान
- औद्योगिक विकास
- बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण
- कृषि उत्पाद विपणन
- जल आपूर्ति और पेशेवर/संस्थागत नियम

व्यापार करने में आसानी और शासन
आपराधिक प्रतिबंधों को गंभीर अपराधों तक सीमित करके, सुधार का उद्देश्य एक विश्वास-आधारित नियामक वातावरण बनाना है जो अनुपालन को प्रोत्साहित करता है और असंगत दंड के डर को कम करता है। यह न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन दृष्टिकोण के अनुरूप है जो सरल नियामक ढांचे पर जोर देता है।

प्रशासनिक दक्षता
आपराधिक अभियोजन को प्रशासनिक तंत्र से बदलने से विवादों और दंडों का तेजी से समाधान होता है, न्यायपालिका पर बोझ कम होता है और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होता है।

कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं

इसे मौजूदा विभागों और संसाधनों द्वारा लागू किया जाएगा, जिसके लिए किसी अतिरिक्त वित्तीय आवंटन या नए कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता नहीं होगी।

समाचार संक्षिप्त में

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्कों के आदान-प्रदान के लिए भूटान के सुप्रीम कोर्ट के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने घोषणा की कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्कों के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए भूटान के सुप्रीम कोर्ट (भूटान का सर्वोच्च न्यायालय) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया है। समझौते के तहत, भूटान के दो लॉ क्लर्क तीन महीने की अवधि के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े रहेंगे, जहाँ वे जजों की सहायता करेंगे, कानूनी रिसर्च करेंगे और कोर्ट की कार्यवाही देखेंगे। भूटानी लॉ क्लर्कों को वही मानदेय (स्टाइपेंड) मिलेगा जो भारतीय लॉ क्लर्कों को मिलता है, और भारत में उनके रहने का यात्रा खर्च भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहन किया जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान, क्लर्कों को व्यापक न्यायिक अनुभव प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग अदालतों/बेंचों में नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। CJI सूर्यकांत ने आने वाले लॉ क्लर्कों को "युवा और होशियार" बताया और कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच न्यायिक सहयोग और संस्थागत संबंधों को मजबूत करना है।

न्यायिक सहयोग और लॉ क्लर्क एक्सचेंज

सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ क्लर्क जजों को कानूनी रिसर्च, राय का मसौदा तैयार करने, केस कानूनों की समीक्षा करने और केस सारांश तैयार करने में सहायता करता है - यह एक ऐसी भूमिका है जो कानूनी शिक्षा और न्यायिक कामकाज को बढ़ाती है। ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से देशों के बीच न्यायिक सहयोग साझा कानूनी संस्कृति, तुलनात्मक न्यायशास्त्र और युवा कानूनी पेशेवरों के बीच क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है। भूटान के साथ MoU भारत की न्यायिक कूटनीति और "पड़ोसी पहले" नीति के हिस्से के रूप में पड़ोसी देशों की कानूनी प्रणालियों के लिए समर्थन को दर्शाता है - जिसका उद्देश्य कानून, शासन और संस्थानों में सहयोग के माध्यम से संबंधों को मजबूत करना है।

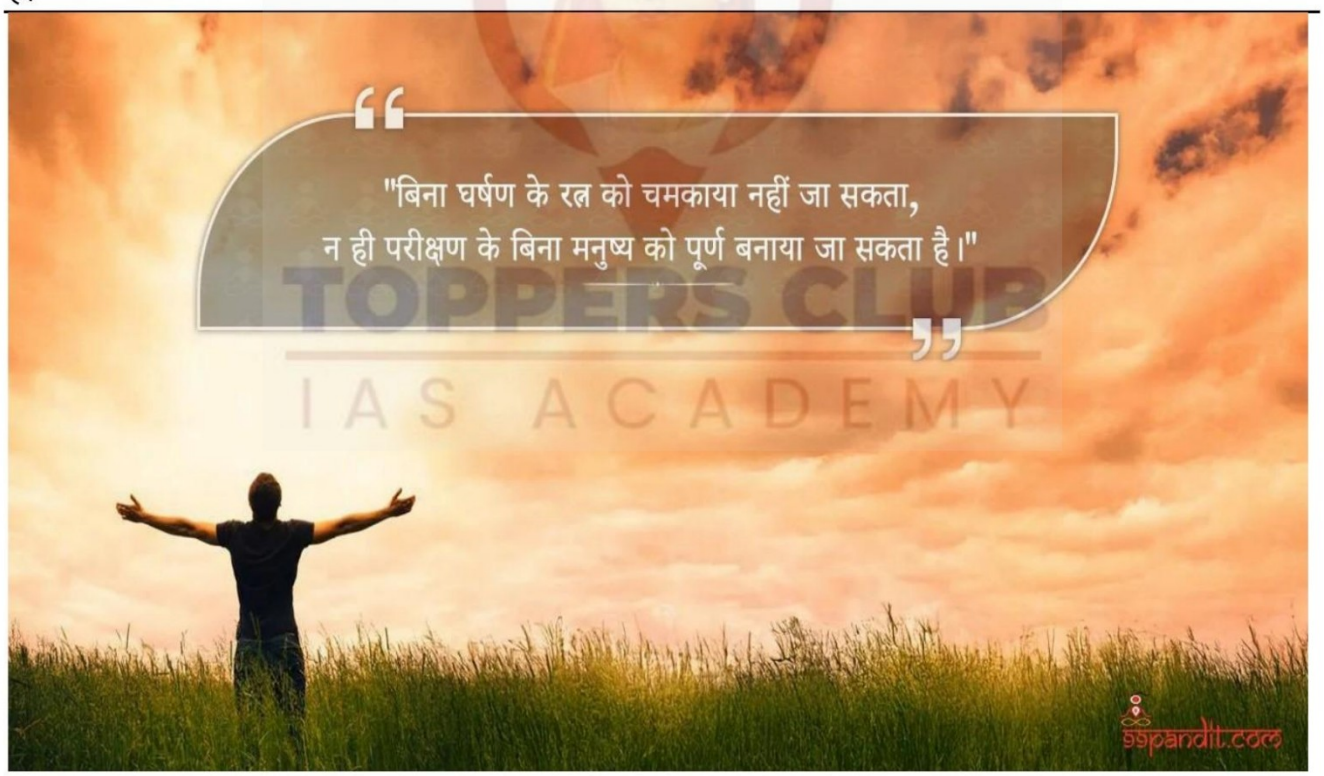

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ

म्यांमार गृहयुद्ध (2021–वर्तमान)

पृष्ठभूमि: म्यांमार की राजनीतिक उथल-पुथल

म्यांमार के मिलिट्री जुंटा ने फरवरी 2021 में तख्तापलट करके सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया, और आंग सान सू की के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटा दिया। इस तख्तापलट से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हिंसक कार्रवाई और लोकतंत्र समर्थक ताकतों और जातीय सशस्त्र समूहों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। लगातार संघर्ष के कारण देश के बड़े हिस्से जुंटा के नियंत्रण से बाहर हैं।

2025-26 के चुनाव: क्या हो रहा है

- आम चुनाव 28 दिसंबर 2025 को चरणबद्ध तरीके से शुरू हुए और 25 जनवरी 2026 तक खत्म होने वाले हैं।
- जुंटा का दावा है कि यह वोट आपातकाल की स्थिति - जो 2025 के मध्य में हटा ली गई थी - के बाद संवैधानिक व्यवस्था बहाल करेगा और नागरिक शासन की वापसी होगी।
- चुनाव कानून में बदलावों ने राजनीतिक परिदृश्य को काफी बदल दिया है, जिसमें पार्टी पंजीकरण और भागीदारी पर प्रतिबंध शामिल हैं जो विपक्षी समूहों के लिए नुकसानदायक हैं।

जुंटा युद्ध के बीच चुनाव क्यों करवा रहा है

सैन्य शासन को वैधता देना

- चुनाव कराने से जुंटा को व्यापक संघर्ष के बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आंतरिक और बाहरी वैधता का दिखावा मिलता है।
- आलोचक इस चुनाव को "फर्जी चुनाव" कहते हैं, जिसे प्रॉक्सी राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से सैन्य नियंत्रण को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कानूनी रूप से सत्ता को मजबूत करना

- जुंटा का नया चुनावी ढांचा सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP) के पक्ष में है।
- आंग सान सू की की पार्टी सहित विपक्षी ताकतें या तो भंग हो गई हैं या सार्थक रूप से भाग लेने में असमर्थ हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रणनीति

- सेना को उम्मीद है कि चुनाव अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को कम करेगा और राजनयिक अलगाव को आसान बनाएगा।
- चीन और रूस जैसे देशों ने इस प्रक्रिया का समर्थन या मान्यता दिखाई है।

आलोचना और चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी सरकारें दमन, विस्थापन और गृह युद्ध के कारण इस वोट को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए शर्तों की कमी वाला बताती हैं।
- सुरक्षा कारणों से देश के कई क्षेत्रों में लोग भाग नहीं ले सकते।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह और विपक्षी ताकतें इन चुनावों को वैधता बनाने का एक अभ्यास मानती हैं, न कि एक वास्तविक लोकतांत्रिक परिवर्तन।

यह क्यों मायने रखता है

- ये चुनाव, जो तीव्र संघर्ष और राजनीतिक दमन के बीच हो रहे हैं, म्यांमार के लंबे संकट में एक महत्वपूर्ण क्षण हैं। वे महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं से अस्वीकृति का सामना करते हुए सैन्य प्रभुत्व को एक औपचारिक राजनीतिक जनादेश में बदलने के जुंटा के प्रयास को दर्शाते हैं

ईरान में उथल-पुथल

चर्चा में क्यों?

निर्वासित क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी की सार्वजनिक अपील के बाद ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन कई शहरों में फैल गए हैं, जो राजनीतिक दमन और आर्थिक संकट को लेकर बढ़ती सार्वजनिक नाराज़गी को दर्शाता है।

विरोध प्रदर्शनों के मुख्य कारण

रज़ा पहलवी द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों का आह्वान

- गहराता आर्थिक संकट, महंगाई और मुद्रा का अवमूल्यन
- सत्तावादी शासन के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही शिकायतें
- राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी को लेकर जनता में निराशा

अशांति का भौगोलिक फैलाव

कई प्रमुख शहरों और प्रांतों में विरोध प्रदर्शनों की सूचना मिली है:

- तेहरान
- इस्फ़हान
- मशहद
- शिराज़
- बुशहर
- अन्य शहरी और अर्ध-शहरी केंद्र
- पैमाना अलग-अलग घटनाओं के बजाय देशव्यापी लामबंदी का संकेत देता है।

इंटरनेट और संचार ब्लैकआउट

अशांति के जवाब में, ईरानी अधिकारियों ने लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया।

ब्लैकआउट का विवरण

- अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सेस काफी हद तक बंद
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक
- मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाएं बाधित
- केवल राज्य-नियंत्रित घरेलू नेटवर्क तक सीमित पहुंच की अनुमति

शटडाउन का उद्देश्य

- प्रदर्शनकारियों के बीच समन्वय को रोकना
- बाहरी दुनिया में सूचना के प्रवाह को प्रतिबंधित करना
- मीडिया कवरेज और घटनाओं के दस्तावेज़ीकरण को सीमित करना
- सरकारी प्रतिक्रिया और कार्रवाई
- ईरानी सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए कदम उठाए हैं।

रिपोर्ट की गई कार्रवाई

- पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती
- प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग
- पूरे प्रांतों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की सूचना

मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ

- अधिकार समूहों ने बड़ी संख्या में हताहतों और गिरफ्तारियों की सूचना दी है
- संचार प्रतिबंधों के कारण सटीक आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं हैं

रेजा पहलवी की भूमिका

- ईरान के आखिरी शाह के बेटे, जो निर्वासन में रह रहे हैं
- शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और नागरिक प्रतिरोध का आह्वान किया
- नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर फिर से कब्ज़ा करने और अधिकारियों पर दबाव डालने का आग्रह किया
- ईरानी सरकार उन पर विदेशी समर्थित हस्तक्षेप का आरोप लगाती है

विरोध प्रदर्शन क्यों मायने रखते हैं
- ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यापक असंतोष को दर्शाते हैं
- विरोध को नियंत्रित करने के लिए राज्य की इंटरनेट बंद करने पर निर्भरता को उजागर करते हैं
- ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करते हैं

बेला-1 / मरीनरा मामला

बेला-1 (बाद में मरीनरा के नाम से जानी गई) क्या थी?
बेला-1 एक तेल टैंकर था जो वेनेजुएला के तेल निर्यात से जुड़ा था, और एक ऐसे नेटवर्क में काम कर रहा था जिसे अक्सर "शैडो फ्लीट" कहा जाता है - ऐसे जहाज़ जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधों वाले तेल को ले जाने के लिए नाम, झंडे और रजिस्ट्रेशन बार-बार बदलकर किया जाता है।

2002 में बनाया गया
- पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत वेनेजुएला के तेल शिपमेंट से जुड़ा था
- झंडा बदलना और नाम बदलना इसके ऑपरेटिंग पैटर्न का हिस्सा था

टैंकर अमेरिकी निगरानी में क्यों आया
- 2025 के आखिर में, अमेरिकी अधिकारियों ने प्रतिबंधों को लागू करने के हिस्से के रूप में कैरेबियन क्षेत्र में जहाज़ पर चढ़ने की कोशिश की।
- टैंकर ने जहाज़ पर चढ़ने के अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया
- इस इनकार के कारण अमेरिकी सेनाओं ने लगातार निगरानी शुरू कर दी

समुद्र में पहचान बदलना
भागने की कोशिश के दौरान, टैंकर ने असामान्य कदम उठाए:
- अपना नाम बेला-1 से बदलकर मरीनरा कर लिया
- रूसी झंडे के तहत रजिस्ट्रेशन का दावा किया
- जहाज़ के बाहरी हिस्से पर रूसी निशान दिखाए
- इन कामों का मकसद रूसी अधिकार क्षेत्र का सुझाव देकर कानूनी कार्रवाई को जटिल बनाना था। हालांकि, सक्रिय पीछा करने के दौरान झंडे में तेजी से बदलाव को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत अपने आप मान्यता नहीं मिलती है।

रूसी भागीदारी: क्या पुष्टि हुई है
- अटलांटिक महासागर में टैंकर की यात्रा के कुछ हिस्से के दौरान:
- रूस ने टैंकर पर नज़र रखने के लिए नौसैनिक संपत्ति तैनात की, जिसमें कथित तौर पर एक पनडुब्बी भी शामिल थी
- यह उपस्थिति देखने और प्रतीकात्मक थी, टकराव वाली नहीं
- अमेरिकी सेनाओं के साथ कोई सीधा टकराव नहीं हुआ

महत्वपूर्ण बातें:
- टैंकर को रूसी समुद्री सीमा में एस्कॉर्ट नहीं किया गया था
- पकड़े जाने के समय कोई रूसी युद्धपोत मौजूद नहीं था

ट्रैकिंग और ज़ब्ती
- टैंकर को लगभग दो हफ़्तों तक ट्रैक किया गया:
- अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाजों और विमानों द्वारा
- ब्रिटेन सहित सहयोगी देशों की खुफिया और निगरानी सहायता से
- जनवरी 2026 में, अमेरिकी सेना ने प्रतिबंधों के उल्लंघन से संबंधित एक संघीय अदालत के वारंट के तहत अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में टैंकर पर चढ़कर उसे ज़ब्त कर लिया।

जहाज की वर्तमान स्थिति
- जहाज अभी भी अमेरिकी हिरासत में है
- अमेरिका रूसी झंडा बदलने को वैध नहीं मानता है
- रूस ने राजनयिक विरोध किया लेकिन नियंत्रण वापस नहीं पा सका

यह मामला महत्वपूर्ण क्यों है
- यह दिखाता है कि प्रतिबंधों को लागू करना कैसे धीरे-धीरे खुले समुद्र तक फैल रहा है
- यह झंडा बदलने और प्रतीकात्मक नौसैनिक समर्थन की सीमाओं को दिखाता है
- यह ऊर्जा परिवहन मार्गों पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को उजागर करता है
- बेला-1 / मरीनरा मामला इस बात पर ज़ोर देता है कि तेल व्यापार, प्रतिबंध और बड़ी शक्तियों की राजनीति वैश्विक समुद्री क्षेत्रों में कैसे मिल रही है।

UAE में डेटा एम्बेसी

चर्चा में क्यों?
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) एक-दूसरे के देश में डेटा एम्बेसी स्थापित करने के विचार पर विचार कर रहे हैं। इस विचार पर UAE के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत के दौरान चर्चा हुई।

डेटा एम्बेसी क्या है?
डेटा एम्बेसी एक विशेष केंद्र होता है जहाँ कोई देश अपना महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा दूसरे देश में स्थित सर्वर पर स्टोर करता है। स्टोर किया गया डेटा अपने देश के नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र में रहता है, भले ही सर्वर भौतिक रूप से मेज़बान देश में हों। यह सेटअप साइबर हमलों, प्राकृतिक आपदाओं या भू-राजनीतिक गड़बड़ियों जैसी आपात स्थितियों में डिजिटल निरंतरता और संप्रभुता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

भारत क्यों इसमें रुचि रखता है
यह प्रस्ताव भारत और UAE के बीच उच्च स्तर के विश्वास को दर्शाता है। भारत सुरक्षा और बैकअप के लिए UAE में डेटा एम्बेसी में महत्वपूर्ण सरकारी और वित्तीय डेटा स्टोर कर सकता है। ये डेटा सेंटर भारत को अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या होने पर भी आवश्यक सेवाएं जारी रखने में मदद कर सकते हैं।

यह कैसे काम करता है
हालांकि इसे "एम्बेसी" कहा जाता है, लेकिन डेटा एम्बेसी पारंपरिक राजनयिक मिशन नहीं है। राजनयिकों और कार्यालयों के बजाय, इसमें सर्वर और सुरक्षित डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। वहाँ स्टोर किया गया डेटा केवल अपने देश और उसके अधिकृत अधिकारियों के लिए सुलभ होता है, और मेज़बान देश के अधिकारी बिना अनुमति के इसे एक्सेस या इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

अन्य देशों के उदाहरण
एस्टोनिया अपने डिजिटल संपत्तियों की रक्षा के लिए लक्ज़मबर्ग में डेटा एम्बेसी बनाने वाला पहला देश था। मोनाको ने भी बाद में लक्ज़मबर्ग में एक ई-एम्बेसी स्थापित की। अगर भारत का प्रस्ताव साकार होता है, तो यह अपनी तरह का पहला होगा।

किन बातों पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है
भारत और UAE को इस विचार को लागू करने के लिए अभी भी एक कानूनी और नियामक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है। अधिकारी स्वीकार करते हैं कि डेटा के मुद्दों के संप्रभुता पर प्रभाव पड़ते हैं, जिन्हें सावधानी से संबोधित किया जाना चाहिए।

यह क्यों महत्वपूर्ण है
एक डेटा एम्बेसी सीमाओं से परे महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा करके डिजिटल और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ा सकती है। यह प्रौद्योगिकी और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत-UAE सहयोग को गहरा करने को दर्शाता है। यह पहल डिजिटल संप्रभुता पर भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।

ऑटोनॉमस टेरिटरी

ऑटोनॉमस या विदेशी क्षेत्र क्या है?

- एक ऑटोनॉमस टेरिटरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी अपनी स्थानीय सरकार होती है और फैसले लेने की कुछ आज़ादी होती है, लेकिन फिर भी वह एक बड़े देश का हिस्सा होता है।
- एक विदेशी क्षेत्र किसी देश का हिस्सा होता है लेकिन भौगोलिक रूप से मुख्य भूमि से बहुत दूर स्थित होता है, अक्सर ऐतिहासिक या रणनीतिक कारणों से।

ये क्षेत्र क्यों मौजूद हैं?

इनमें से कई औपनिवेशिक इतिहास से निकले हैं, जब देशों ने दूर की ज़मीनों पर नियंत्रण स्थापित किया था। आज, वे अक्सर रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक कारणों से बने रहते हैं।

सबसे ज़्यादा विदेशी या ऑटोनॉमस क्षेत्रों वाले शीर्ष देश

1. यहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी या ऑटोनॉमस क्षेत्रों वाले देश दिए गए हैं:
2. यूनाइटेड किंगडम: दुनिया भर में 14 क्षेत्र।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका: मुख्य भूमि के बाहर 14 क्षेत्र।
4. फ्रांस: विदेशी विभागों सहित 13 क्षेत्र।
5. ऑस्ट्रेलिया: 7 क्षेत्र।
6. नीदरलैंड: कैरिबियन में 6 क्षेत्र।
7. नॉर्वे: 5 क्षेत्र।
8. न्यूज़ीलैंड: 4 क्षेत्र।
9. डेनमार्क: 2 (ग्रीनलैंड और फ़ेरो द्वीप समूह सहित)।
10. चीन: स्वायत्तता वाले 2 विशेष क्षेत्र।
11. पुर्तगाल: 2 स्वायत्त क्षेत्र।

इन क्षेत्रों में क्या अंतर है?

- कुछ पूरी तरह से स्व-शासित हैं, जो अपने कई आंतरिक फैसले खुद लेते हैं।
- अन्य रक्षा और विदेश मामलों के लिए मुख्य देश पर निर्भर रहते हैं।
- कुछ क्षेत्र निर्जन हैं और मुख्य रूप से अनुसंधान या रणनीतिक कारणों से उपयोग किए जाते हैं।

ऑटोनॉमस और विदेशी क्षेत्रों के बीच अंतर

- ऑटोनॉमस क्षेत्र: किसी देश के भीतर स्व-शासन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- विदेशी क्षेत्र: आमतौर पर मूल देश से भौगोलिक रूप से दूर होता है लेकिन फिर भी प्रशासनिक रूप से उसका हिस्सा होता है।
- उदाहरण के लिए, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है लेकिन अपने कई मामले खुद चलाता है और यूरोप से बहुत दूर स्थित है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

- विदेशी और ऑटोनॉमस क्षेत्र वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और रक्षा में भूमिका निभाते हैं।
- वे दिखाते हैं कि कैसे देशों के कुछ हिस्सों में स्व-शासन के अलग-अलग स्तर हो सकते हैं, जबकि वे अभी भी एक बड़े राष्ट्र से जुड़े हुए हैं।

समाचार संक्षिप्त में

कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस से हटाया

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अपने नए बने बोर्ड ऑफ पीस से हटा दिया है।

- यह फैसला अमेरिका और कनाडा के बीच राजनयिक असहमति के बाद आया है।

बोर्ड ऑफ पीस क्या है?

- बोर्ड ऑफ पीस स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में ट्रंप द्वारा घोषित एक पहल है।
- इसका मकसद दुनिया के नेताओं का एक ऐसा समूह बनाना है जो वैश्विक संघर्षों को सुलझाने और शांति को बढ़ावा देने पर काम करेगा।

कनाडा को क्यों हटाया गया?

- यह कदम WEF में ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुए विवाद (सार्वजनिक असहमति) के बाद उठाया गया।
- कार्नी ने हाल ही में वैश्विक नेतृत्व पर ट्रंप के बयानों की आलोचना की थी, और ट्रंप ने कनाडा का निमंत्रण वापस लेकर जवाब दिया।

कनाडा ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

- कनाडाई नेताओं ने जवाब में कहा कि कनाडा एक मजबूत, स्वतंत्र राष्ट्र है और अमेरिका पर निर्भर नहीं है।
- कार्नी की टिप्पणियों ने कनाडा की संप्रभुता और राष्ट्रीय ताकत पर जोर दिया।

नाटो का आर्टिकल 5

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सुझाव दिया कि अमेरिका को दक्षिणी सीमा पर अवैध इमिग्रेशन से निपटने के लिए नाटो के आर्टिकल 5 को लागू करने पर विचार करना चाहिए था।

आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो के एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, जिससे सामूहिक रक्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले कभी सीमा नियंत्रण या इमिग्रेशन के मुद्दों के लिए नहीं किया गया है।

यह सुझाव विवादास्पद क्यों है?

- आर्टिकल 5 पारंपरिक रूप से सशस्त्र सैन्य आक्रमण के लिए आरक्षित रहा है, न कि माइग्रेशन जैसे घरेलू मुद्दों के लिए।
- ट्रम्प का विचार सामान्य नाटो प्रथा और कानूनी व्याख्याओं से अलग है, जिससे सहयोगियों के बीच चिंता पैदा हो रही है।

ट्रम्प के बयान के पीछे का संदर्भ

- यह टिप्पणी ग्रीनलैंड और आर्कटिक सुरक्षा पर बातचीत के बाद ट्रम्प द्वारा कई यूरोपीय देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को रोकने के तुरंत बाद आई।
- ट्रम्प डेनमार्क के रणनीतिक आर्कटिक क्षेत्र ग्रीनलैंड पर अधिक अमेरिकी प्रभाव या नियंत्रण के लिए भी जोर दे रहे हैं।

आर्टिकल 5 क्या है और यह क्यों मायने रखता है

- आर्टिकल 5 नाटो का सामूहिक रक्षा खंड है, जिसका अर्थ है कि एक सदस्य को नुकसान सभी को नुकसान है।
- इसे पहले सिर्फ एक बार लागू किया गया है - 11 सितंबर के हमलों के बाद - और ऐतिहासिक रूप से यह सैन्य आक्रमण के बारे में रहा है।
- अवैध इमिग्रेशन पर आर्टिकल 5 लागू करना असामान्य है और नाटो की सामान्य व्याख्या द्वारा समर्थित नहीं है।

नाटो सहयोगियों की प्रतिक्रियाएँ

- नाटो अधिकारियों और यूरोपीय नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि आर्टिकल 5 सुरक्षा खतरों के लिए है, न कि घरेलू सीमा प्रवर्तन के लिए।
- कुछ सहयोगियों ने ट्रम्प की टिप्पणियों पर चिंता और भ्रम व्यक्त किया है, खासकर इसलिए क्योंकि ये ग्रीनलैंड की रणनीतिक भूमिका पर बहसों के बाद आई हैं।

ग्रीनलैंड मुद्दे से संबंध

- आर्टिकल 5 पर ट्रम्प की टिप्पणियाँ ग्रीनलैंड के संबंध में उनके व्यापक प्रयास के बीच आईं, जहाँ उन्होंने अधिक अमेरिकी पहुँच या प्रभाव की मांग की है।
- नाटो और यूरोपीय नेता आर्कटिक में एक सुरक्षा ढांचे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ग्रीनलैंड की भूमिका शामिल है, लेकिन इसकी संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं।

नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)

- गठन: 4 अप्रैल 1949
- प्रकार: सैन्य गठबंधन
- मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
- सदस्यता: 32 राज्य
- महासचिव: मार्क रुट्टे
- नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष: ग्यूसेप कैवो ड्रैगन

अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर WHO छोड़ दिया

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन से अपनी मेंबरशिप औपचारिक रूप से वापस ले ली है। इससे ग्लोबल हेल्थ बॉडी में अमेरिका की 78 साल की मेंबरशिप खत्म हो गई है।

अमेरिकी सरकार द्वारा बताया गया कारण

अमेरिकी नेताओं का कहना है कि WHO COVID-19 महामारी से निपटने में नाकाम रहा। उनका दावा है कि ऑर्गनाइजेशन ने समय पर सही जानकारी शेयर नहीं की और राजनीति से प्रभावित था। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस नाकामी से महामारी के दौरान अमेरिकी लोगों की जान और हितों को नुकसान पहुंचा।

विड्रॉल कैसे हुआ

यह विड्रॉल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साइन किए गए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए किया गया। नियमों के मुताबिक, अमेरिका ने पहले ही WHO को एक साल पहले छोड़ने के अपने इरादे के बारे में बता दिया था।

फंडिंग और भागीदारी का अंत

संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO के सभी प्रोग्राम की फंडिंग और स्टाफिंग बंद कर दी है। WHO के साथ अमेरिका की भागीदारी विड्रॉल प्रोसेस को फाइनल करने तक ही सीमित रहेगी।

WHO छोड़ने के बाद अमेरिका की योजनाएं

अमेरिका का कहना है कि अब वह WHO के ज़रिए नहीं, बल्कि सीधे दूसरे देशों और भरोसेमंद हेल्थ संस्थानों के साथ काम करेगा। उसका दावा है कि ये द्विपक्षीय पार्टनरशिप ग्लोबल हेल्थ सहयोग जारी रखेंगी।

प्रतीकात्मक विवाद और प्रतिक्रियाएं

विड्रॉल के बाद, कथित तौर पर WHO ने अपने हेडक्वार्टर में लगा अमेरिकी झंडा वापस नहीं किया। इस एग्जिट से ग्लोबल हेल्थ सहयोग और WHO की भविष्य की भूमिका के बारे में बड़े पैमाने पर बहस छिड़ गई है।

फैसले का महत्व

संयुक्त राज्य अमेरिका 1948 में WHO का फाउंडिंग मेंबर था और इसका सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्टर था। यह एग्जिट इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी और ग्लोबल हेल्थ संस्थानों के साथ अमेरिकी भागीदारी में एक बड़ा बदलाव है।

WHO

- गठन: 7 अप्रैल 1948
- प्रकार: संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी
- हेडक्वार्टर: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- महानिदेशक: टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस

भारत पुनः वेनेजुएला से तेल खरीदने को तैयार

चर्चा में क्यों?
संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने संकेत दिया है कि वह अमेरिका द्वारा नियंत्रित एक नए फ्रेमवर्क के तहत भारत को वेनेजुएला से फिर से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव एक व्यापक ऊर्जा और प्रतिबंध रणनीति का हिस्सा है, जो अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों में हाल के बदलावों के बाद आया है।

यह नया फ्रेमवर्क क्यों सुझाया जा रहा है
अमेरिकी प्रतिबंधों ने पहले वेनेजुएला के तेल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें भारत भी शामिल था, जो प्रतिबंधों से पहले वेनेजुएला के महत्वपूर्ण खरीदारों में से एक था। नई प्रणाली के तहत, अमेरिका अपने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बिक्री और भुगतान प्रक्रिया का प्रबंधन और देखरेख करेगा।

नियंत्रित फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा
इस फ्रेमवर्क में तेल की बिक्री और वित्तीय प्रवाह पर अमेरिका की कड़ी निगरानी शामिल होने की संभावना है।
अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने बताया है कि तेल निर्यात का विपणन अमेरिकी सरकार द्वारा किया जाएगा, और भुगतान वाशिंगटन द्वारा नियंत्रित या निगरानी वाले खातों के माध्यम से होगा।

इसका भारत के लिए क्या मतलब है
प्रतिबंधों से व्यापार कम होने से पहले भारत वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार था। फिर से पहुंच मिलने से भारत को अपने तेल आयात में विविधता लाने और अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है, जो काफी हद तक आयातित कच्चे तेल पर निर्भर करती हैं।
व्यापक संदर्भ
वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, जो इसे भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए कच्चे तेल का एक आकर्षक स्रोत बनाता है। भारत के रिफाइनर, जो वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल से परिचित हैं, व्यापार फिर से शुरू होने के बाद इसे संसाधित करने के लिए तैयार हैं।

अभी भी चर्चा में है
हालांकि अमेरिका ने अपनी इच्छा का संकेत दिया है, लेकिन व्यवस्था का विवरण - जिसमें मूल्य निर्धारण, मात्रा और फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा - अभी भी बातचीत के दौर में है।

यह क्यों मायने रखता है
यह बदलाव वैश्विक तेल व्यापार पैटर्न को प्रभावित कर सकता है और रूस जैसे विशिष्ट कच्चे तेल स्रोतों पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है। यह यह भी दिखाता है कि भू-राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा समझौतों को कैसे आकार दे रही हैं।

आर्कटिक में सैन्य संपत्तियों पर एक नज़र

ग्रीनलैंड सैन्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है
ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है, जो इसे रक्षा और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यहां अमेरिकी पिटुफिक स्पेस बेस जैसी सैन्य सुविधाएं हैं, जो अंतरिक्ष निगरानी, मिसाइल चेतावनी और उत्तरी अमेरिकी रक्षा के लिए शुरुआती पहचान प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आर्कटिक अमेरिका, रूस, चीन और नाटो सहयोगियों से जुड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है।

ग्रीनलैंड में मौजूदा सैन्य उपस्थिति
पिटुफिक स्पेस बेस (पहले थुले एयर बेस) अमेरिकी सेना का सबसे उत्तरी ठिकाना है, जो मिसाइल और अंतरिक्ष निगरानी अभियानों का समर्थन करता है। यह बेस NORAD (उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस रक्षा कमान) की शुरुआती चेतावनी और अंतरिक्ष नियंत्रण प्रणालियों में योगदान देता है। डेनमार्क भी आर्कटिक परिस्थितियों के अनुकूल सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है - संप्रभुता की रक्षा करने और नाटो रक्षा का समर्थन करने के लिए।

पूरे आर्कटिक में सैन्य संपत्ति

- आर्कटिक आठ देशों द्वारा साझा किया जाता है: रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड के माध्यम से), नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड।
- इस क्षेत्र में रूस की बड़ी सैन्य उपस्थिति है - ठिकानों को फिर से खोलना और आधुनिक बनाना, परमाणु-संबंधित सुविधाओं का संचालन करना और अपने उत्तरी बेड़े को बनाए रखना।
- अन्य आर्कटिक राज्यों के पास रक्षा बल, गश्ती क्षमताएं और उनकी भूगोल और सुरक्षा भूमिकाओं के अनुकूल प्रतिष्ठान हैं।

ग्रीनलैंड में हालिया सैन्य गतिविधियां

अमेरिका की रुचि और आर्कटिक सुरक्षा चिंताओं से जुड़े बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में सैनिकों की तैनाती को मजबूत किया है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस जैसे नाटो अभ्यास चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र की रक्षा करने और बल के उपयोग को रोकने की क्षमता प्रदर्शित करना है।

ग्रीनलैंड की सैन्य भूमिका पर अमेरिका का ध्यान क्यों है

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन से खतरों और द्वीप के रणनीतिक महत्व का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा में ग्रीनलैंड की भूमिका पर बार-बार जोर दिया है।
- ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने में भी फिर से दिलचस्पी दिखाई, हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने किसी भी बिक्री या संप्रभुता के हस्तांतरण को दृढ़ता से खारिज कर दिया है।
- अमेरिकी प्रस्तावों और चर्चाओं में नाटो सहयोगियों के तहत बेहतर सैन्य सहयोग और संभावित संशोधित ढांचे शामिल हैं, हालांकि औपचारिक विलय नहीं।

व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ

- ग्रीनलैंड की आर्कटिक स्थिति मिसाइल प्रक्षेपवक्र और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों की निगरानी के लिए मूल्यवान है, खासकर परमाणु निवारण और रणनीतिक रक्षा के संदर्भ में। जलवायु परिवर्तन ने नए शिपिंग रास्ते और संसाधनों तक पहुंच खोल दी है, जिससे इस क्षेत्र के रणनीतिक बुनियादी ढांचे और सैन्य महत्व में दिलचस्पी बढ़ गई है।

मुख्य बात

ग्रीनलैंड सैन्य रूप से महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि यह बड़ा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह कहाँ स्थित है - यह बड़ी शक्तियों के बीच है और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र पर नज़र रखता है, जहाँ रक्षा, निगरानी और भू-राजनीतिक प्रभाव मिलते हैं।

US टैरिफ का ज़्यादातर खर्च असल में अमेरिकी ही उठाते हैं

चर्चा में क्यों?

कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी की एक नई स्टडी से पता चलता है कि US टैरिफ का ज़्यादातर खर्च असल में अमेरिकी ही उठाते हैं - विदेशी एक्सपोर्टर नहीं। टैरिफ का लगभग 96% बोझ अमेरिकी इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स पर पड़ता है, जबकि विदेशी सेलर्स सिर्फ़ लगभग 4% ही उठाते हैं। यह कुछ अमेरिकी नेताओं के इस दावे के उलट है कि टैरिफ का भुगतान मुख्य रूप से दूसरे देश करेंगे।

टैरिफ क्या हैं?

टैरिफ इंपोर्टेड सामान पर इंपोर्ट करने वाले देश द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है। ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का मकसद घरेलू इंडस्ट्रीज़ को बचाना और ट्रेड डेफिसिट को कम करना था। टैरिफ से सरकार के लिए रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद होती है, लेकिन यह स्टडी दिखाती है कि वे US के अंदर कंज्यूमर्स और बिज़नेस पर टैक्स की तरह काम करते हैं।

ज़्यादातर खर्च कैसे आगे बढ़ाया जाता है

भले ही इंपोर्टर्स कस्टम्स को टैरिफ का भुगतान करते हैं, लेकिन बिज़नेस अक्सर सामान की कीमतें बढ़ाकर इन एक्स्ट्रा खर्चों को कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। नतीजतन, अमेरिकी परिवारों को इंपोर्टेड चीज़ों और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स से बने सामान के लिए ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ती हैं।

कस्टम्स रेवेन्यू बनाम असली बोझ

स्टडी में बताया गया है कि 2025 में, टैरिफ से US कस्टम्स रेवेन्यू लगभग $200 बिलियन बढ़ गया, जो इकट्ठा किए गए टैरिफ की बड़ी मात्रा को दिखाता है। लेकिन यह रेवेन्यू असल में घरेलू कंज्यूमर्स और इंपोर्टर्स से आता है, न कि विदेशी प्रोड्यूसर्स से।

दावा बनाम हकीकत
कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि टैरिफ विदेशी एक्सपोर्टर्स को भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं और अमेरिकी वर्कर्स की रक्षा करते हैं। स्टडी के नतीजे बताते हैं कि यह सच नहीं है - अमेरिकी ही लगभग सारा खर्च उठाते हैं।

व्यापक आर्थिक प्रभाव (संदर्भ)
अन्य रिसर्च और रिपोर्ट्स ने भी चेतावनी दी है कि ट्रम्प का टैरिफ तरीका कंज्यूमर कीमतें बढ़ा सकता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है और आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है।

यह क्यों मायने रखता है
यह समझना कि टैरिफ का खर्च असल में कौन उठाता है, महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंज्यूमर कीमतों, बिज़नेस खर्चों और आर्थिक नीति पर होने वाली बहसों को प्रभावित करता है। अगर टैरिफ ज़्यादातर अमेरिकियों के लिए खर्च बढ़ाते हैं, तो यह दावा कि वे घरेलू हितों की रक्षा करते हैं, सवालिया निशान के घेरे में आ जाता है।

ट्रम्प के कामों से चीन को बढ़ावा

चर्चा में क्यों?
हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प का लक्ष्य "अमेरिका को फिर से महान बनाना" है, लेकिन उनकी कई नीतियों का अनजाने में ऐसा असर हो रहा है कि चीन की वैश्विक स्थिति मजबूत हो रही है। वैश्विक जनमत और हाल के रुझान बताते हैं कि चीन का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि कई देशों में अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है।

ऑफिस में ट्रम्प का पहला साल
2025 में सत्ता में लौटने के बाद से, ट्रम्प ने बड़े कदम उठाए हैं:
- सैकड़ों कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए।
- व्यापार युद्ध शुरू किया और टैरिफ लगाए।
- अमेरिका को प्रमुख वैश्विक समझौतों और संस्थानों से बाहर निकाला।
- इन कदमों से आर्थिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बदलाव आया है।

चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है
कमजोर होने के बजाय, वैश्विक टैरिफ दबाव के बावजूद चीन का व्यापार अधिशेष रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। चीन की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रही, जिससे सरकारी लक्ष्य पूरे हुए। अमेरिका का प्रभाव कम होने के बावजूद बीजिंग सफलतापूर्वक वैश्विक व्यापार नेटवर्क में एकीकृत हो गया है।

वैश्विक नेता व्यापार संबंधों को रीसेट कर रहे हैं
कई देशों के नेता व्यापार संबंधों को रीसेट करने या गहरा करने के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए:
- कनाडा ने बीजिंग के साथ नई साझेदारियों की घोषणा की।
- दक्षिण कोरिया के नेता ने व्यापार वार्ता के लिए चीन का दौरा किया।
- यूके और जर्मनी ने भी उच्च-स्तरीय यात्राओं की योजना बनाई।

वैश्विक व्यापार में अमेरिका की भूमिका बदल रही है
अमेरिका को वैश्विक व्यापार नेता के रूप में काम करने के लिए कम इच्छुक देखा जा रहा है। व्यापार ढांचे में पारंपरिक अमेरिकी प्रभाव कम होता दिख रहा है, जबकि चीन अधिक केंद्रीय भूमिकाओं में कदम रख रहा है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव

वैश्विक व्यापार प्रवाह एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में अधिक एकीकरण दिखाते हैं। व्यापार की दूरियां और संबंध अमेरिका-केंद्रित मार्गों से परे व्यापक हो रहे हैं।

जनता की धारणा और प्रभाव
एक वैश्विक सर्वेक्षण में पाया गया कि अब कई लोग उम्मीद करते हैं कि अगले दशक में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। कई देशों में अमेरिकी नेतृत्व पर भरोसा कम हुआ है, जिसमें कुछ पारंपरिक सहयोगी भी शामिल हैं।

भारत पर प्रभाव
भारत ने आंशिक रूप से अमेरिकी टैरिफ दबावों के जवाब में चीन के साथ अपने जुड़ाव को समायोजित किया है। हाल ही में चीन को भारतीय निर्यात बढ़ा है, जबकि अमेरिकी निर्यात कम हुआ है, जो आर्थिक पुनर्गठन को दर्शाता है।

कुल मिलाकर निष्कर्ष
ट्रम्प की नीतियों ने वैश्विक व्यापार संबंधों को रीसेट कर दिया है। इससे यह धारणा बनी है कि चीन आर्थिक और राजनयिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वैश्विक व्यापार नेता के रूप में अमेरिका की भूमिका को चुनौती मिल रही है, और कई देश अपनी पार्टनरशिप में विविधता ला रहे हैं।

नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को

चर्चा में क्यों?
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो, जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलीं। उन्होंने वेनेजुएला की आज़ादी के लिए उनके समर्थन के प्रति आभार जताने के प्रतीक के तौर पर अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को दिया।

ट्रंप की प्रतिक्रिया
ट्रंप ने मेडल स्वीकार किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यह "आपसी सम्मान का एक शानदार जेस्चर" था। एक फ्रेम वाले नोट में लिखा था कि यह मेडल ट्रंप को "शांति को बढ़ावा देने, कूटनीति को आगे बढ़ाने और स्वतंत्रता की रक्षा करने में उनके नेतृत्व" की पहचान के तौर पर दिया गया था।

क्या नोबेल शांति पुरस्कार ट्रांसफर किया जा सकता है?
नहीं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने साफ किया कि नोबेल शांति पुरस्कार को ट्रांसफर, शेयर या रद्द नहीं किया जा सकता। नोबेल लॉरिएट का टाइटल मचाडो के साथ स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, भले ही फिजिकल मेडल किसी और को दिया जाए या दिखाया जाए।

मचाडो ने ऐसा क्यों किया
मचाडो के इस कदम को अमेरिकी सरकार से अपील करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने में मदद की थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह जेस्चर उन्हें राजनीतिक समर्थन हासिल करने और वेनेजुएला के भविष्य के नेतृत्व में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा।

ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक नोट्स
लेख में बताया गया है कि इतिहास में, नोबेल मेडल विजेताओं द्वारा दूसरों को दिए गए हैं या सौंपे गए हैं, लेकिन इससे आधिकारिक पुरस्कार या लॉरिएट का स्टेटस नहीं बदलता है।

मुख्य स्पष्टीकरण
नोबेल शांति पुरस्कार आधिकारिक तौर पर मचाडो का ही है, और सिर्फ मेडल मिलने से ट्रंप नोबेल लॉरिएट नहीं बन जाते।

ट्रम्प ने गाजा के लिए नई संस्थाओं का ऐलान किया

चर्चा में क्यों?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल और हमास के बीच लंबे संघर्ष के बाद अपनी गाजा शांति योजना के तहत दो नई संस्थाएं बनाई हैं। इन संस्थाओं का मकसद गाजा में शासन चलाने और पुनर्निर्माण और स्थिरता में मदद करना है।

1. गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति (NCAG)
यह एक फिलिस्तीनी समिति है जिसे गाजा में रोज़मर्रा की सार्वजनिक सेवाओं और प्रशासन को चलाने के लिए चुना गया है।
इसका नेतृत्व डॉ. अली शाअथ कर रहे हैं, जो शासन के पदों पर अनुभव रखने वाले एक फिलिस्तीनी हैं। NCAG के काम में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा बहाल करना और एक स्थिर समाज का निर्माण करना शामिल है।

2. गाजा कार्यकारी बोर्ड
यह बोर्ड गाजा में शांति और स्थिरता के लक्ष्यों के साथ शासन का समर्थन करने और सेवाएं देने के लिए बनाया गया था। इसमें अलग-अलग देशों और पृष्ठभूमि के 11 सदस्य हैं। मुख्य सदस्यों में ट्रम्प के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, पूर्व यूके पीएम टोनी ब्लेयर, यूएई मंत्री रीम अल-हाशिमी और एक इजरायली व्यवसायी याकिर गाबे शामिल हैं। यह बोर्ड NCAG की देखरेख करता है और पुनर्निर्माण और सेवा वितरण में सहायता करता है।

हमास ने कैसी प्रतिक्रिया दी है
हमास ने अभी तक इन नई संस्थाओं के गठन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शांति योजना के शुरुआती चरणों में, हमास ने कहा था कि उसने कुछ तत्वों को स्वीकार किया है, जैसे कुछ शक्ति छोड़ना और बंधकों को रिहा करना, लेकिन वह फिलिस्तीनियों के बीच और अधिक परामर्श चाहता था।

इजरायल की प्रतिक्रिया
इजरायल ने नई संस्थाओं का कड़ा विरोध किया है। इजरायल के धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा को ऐसी समितियों की ज़रूरत नहीं है और इसके बजाय हमास से मुक्त किया जाना चाहिए। इजरायली सरकार ने यह भी कहा कि कुछ नियुक्तियां इजरायल के समन्वय के बिना की गईं और उसकी नीतियों के अनुरूप नहीं थीं। यह एक बड़ी चुनौती दिखाता है: इजरायल शासन परिवर्तन पर सहमत होने से पहले हमास को खत्म करने पर जोर देता है।

यह क्यों मायने रखता है
ट्रम्प की शांति योजना का मकसद सालों के युद्ध के बाद गाजा में शासन और पुनर्निर्माण स्थापित करना है। नई संस्थाओं का मकसद फिलिस्तीनी नेतृत्व वाले प्रशासन को अंतरराष्ट्रीय निगरानी के साथ संतुलित करना है। हमास और इजरायल की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं इस बात पर तनाव दिखाती हैं कि गाजा पर कैसे शासन किया जाना चाहिए और स्थायी शांति के लिए कौन सी शर्तें ज़रूरी हैं।

बोर्ड ऑफ़ पीस बनाम यूनाइटेड नेशंस

बोर्ड ऑफ़ पीस क्या है?
बोर्ड ऑफ़ पीस एक नई इंटरनेशनल बॉडी है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज़ किया है। इसका मकसद इज़राइल-हमास संघर्ष के बाद, खासकर गाजा में शांति प्रयासों, शासन और पुनर्निर्माण की देखरेख में मदद करना है।

यह कैसे शुरू हुआ?
ट्रंप ने 2025 के युद्ध और संघर्ष विराम के बाद एक व्यापक गाजा शांति योजना के हिस्से के रूप में इस विचार की घोषणा की। यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद ने इस योजना का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे इसे शुरुआती इंटरनेशनल समर्थन मिला।

बोर्ड का मकसद क्या है?
बोर्ड का लक्ष्य गाजा में शासन, सुरक्षा और पुनर्निर्माण सहित संघर्ष से शांति की ओर बदलाव का मार्गदर्शन करना है। उम्मीद है कि यह ट्रांज़िशनल फिलिस्तीनी प्रशासन की देखरेख करेगा, जिसमें रोज़मर्रा की सेवाओं को चलाने के लिए एक टेक्नोक्रेटिक बॉडी शामिल होगी। इसकी उग्रवादी समूहों को निहत्था करने और शांति सेना का समर्थन करने में भी भूमिका हो सकती है।

इसमें कौन शामिल है?

उम्मीद है कि ट्रंप खुद बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। कई विश्व नेताओं और अधिकारियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें भारत जैसे देशों को भी निमंत्रण मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 60 देशों और हस्तियों को आमंत्रित किया गया है, जो व्यापक इंटरनेशनल पहुंच को दर्शाता है।

सदस्यता और फंडिंग मॉडल

शुरुआती ड्राफ्ट में, इस पहल में सुझाव दिया गया था कि स्थायी सदस्यता की लागत लगभग $1 बिलियन हो सकती है, हालांकि व्हाइट हाउस ने बाद में कहा कि कोई अनिवार्य शुल्क ज़रूरी नहीं है। जो देश भुगतान नहीं करते हैं, वे भी सीमित अवधि के लिए, आमतौर पर तीन साल के लिए शामिल हो सकते हैं।

यह विवादास्पद क्यों है?

कुछ देश और अधिकारी इसमें शामिल होने को लेकर असहज या सतर्क हैं क्योंकि बोर्ड का जनादेश गाजा से परे जाता हुआ लगता है और यह मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम के बाहर एक समानांतर शांति तंत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आलोचकों का कहना है कि बोर्ड यूनाइटेड नेशंस को कमजोर या दरकिनार कर सकता है, जिससे वैधता और वैश्विक शासन पर सवाल उठते हैं। फ्रांस और कनाडा जैसे देशों ने हिचकिचाहट व्यक्त की है, जो सहयोगियों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दिखा रहा है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

बोर्ड ऑफ़ पीस इंटरनेशनल शांति निर्माण के एक नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थानों के बजाय चुनिंदा देशों के एक साथ आने पर केंद्रित है। इसका विकास कैसे होता है, यह गाजा के भविष्य के शासन और पुनर्निर्माण को प्रभावित करेगा और वैश्विक संघर्ष समाधान ढांचे को आकार दे सकता है।

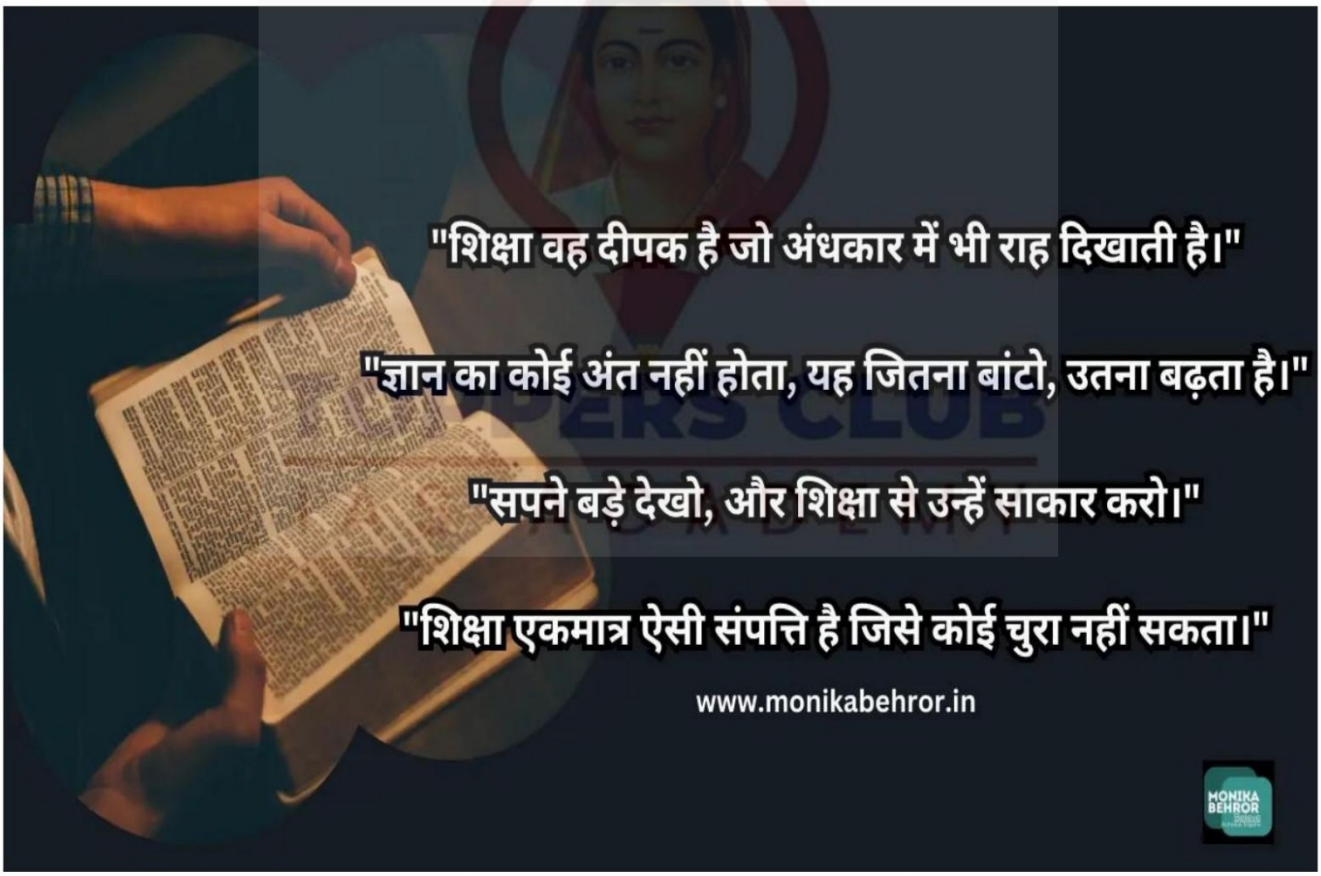

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

यूरोज़ोन

चर्चा में क्यों?

बुल्गारिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपना लिया है, जिससे बल्गेरियाई लेव की जगह ले ली गई है और यह यूरोज़ोन का 21वां सदस्य बन गया है। यह कदम 2007 में EU में शामिल होने के लगभग दो दशक बाद यूरोपीय संघ (EU) के साथ बुल्गारिया के गहरे आर्थिक और मौद्रिक एकीकरण को दर्शाता है।

- परिवर्तन अवधि: जनवरी 2026 में लेव और यूरो दोनों स्वीकार किए जाएंगे; 1 फरवरी 2026 से यूरो एकमात्र कानूनी मुद्रा बन जाएगा
- निश्चित रूपांतरण दर: €1 = 1.95583 बल्गेरियाई लेव
- दोहरी मूल्य निर्धारण नियम: उपभोक्ताओं को स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2026 तक कीमतें दोनों मुद्राओं में प्रदर्शित की जाएंगी

यूरोज़ोन क्या है?

यूरोज़ोन में EU सदस्य देश शामिल हैं जिन्होंने यूरो (€) को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। सभी यूरोज़ोन देशों के लिए मौद्रि नीति यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा प्रबंधित की जाती है। सदस्यता के लिए मुद्रास्फीति, सार्वजनिक वित्त, विनिमय दर स्थिरता और ब्याज दरों पर अभिसरण मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

मास्ट्रिच अभिसरण मानदंड

यूरो अपनाने के लिए, एक देश को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

- मूल्य स्थिरता: सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले EU सदस्यों के बराबर मुद्रास्फीति
- राजकोषीय अनुशासन: बजट घाटा ≤ GDP का 3%; सरकारी ऋण ≤ GDP का 60%
- विनिमय दर स्थिरता: कम से कम दो वर्षों के लिए विनिमय दर तंत्र (ERM II) में भागीदारी
- दीर्घकालिक ब्याज दरें: स्थिर यूरोज़ोन देशों के समान

ऐतिहासिक संदर्भ

बुल्गारिया 2007 में EU में शामिल हुआ। यूरो को EU में शामिल होने के 19 साल बाद अपनाया गया है, जो दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों और नीति संरेखण को दर्शाता है।

संक्रमण उपाय

- समानांतर प्रचलन: जनवरी 2026 में लेव और यूरो दोनों स्वीकार किए जाएंगे
- मुफ्त विनिमय: नागरिक बिना किसी शुल्क के बैंकों में लेव को यूरो में बदल सकते थे
- उपभोक्ता संरक्षण: अनुचित मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए दोहरी मूल्य निर्धारण और निगरानी

दोरजीलुंग हाइड्रो प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

वर्ल्ड बैंक ने दोरजीलुंग हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए USD 815 मिलियन के लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग पैकेज को मंज़ूरी दे दी है। यह फैसला वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बोर्ड ने लिया।

दोरजीलुंग प्रोजेक्ट क्या है?

- यह एक 1,125 मेगावाट (MW) का हाइड्रोपावर प्लांट है जिसे भूटान में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है।
- यह प्रोजेक्ट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन (DGPC) की 60% और भारत की टाटा पावर की 40% हिस्सेदारी है।

फंडिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा?

फाइनेंसिंग पैकेज में शामिल हैं:
- इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA) से USD 150 मिलियन का ग्रांट और USD 150 मिलियन का क्रेडिट।
- इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) से DGPC को USD 15 मिलियन का लोन।
- प्रोजेक्ट कंपनी को IBRD से USD 200 मिलियन का एनक्लेव लोन और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) से USD 300 मिलियन का लोन।
- अतिरिक्त फंड अन्य मार्केट पार्टिसिपेंट्स से जुटाए जाएंगे।

प्रोजेक्ट से क्या उत्पादन होगा?
- पूरा होने के बाद, प्लांट से हर साल 4,500 गीगावाट-घंटे (GWh) से ज़्यादा साफ बिजली पैदा होने की उम्मीद है।
- इस बिजली का लगभग 80% हिस्सा भारत को सप्लाई किया जाएगा, जिससे साफ ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

भूटान
- राजधानी: थिम्फू
- मुद्राएँ: भूटानी न्गुल्ट्रम, भारतीय रुपया
- आधिकारिक भाषा: ज़ोंगखा
- राजा: जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक

LIC डीमर्जर

चर्चा में क्यों?
कुछ एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स ने LIC को ज़्यादा "एफ़िशिएंट" बनाने के लिए इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया है। यह आइडिया है कि बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन को तोड़ने से वे बेहतर परफॉर्म करती हैं।

भारत में LIC खास क्यों है
- LIC रेगुलर प्राइवेट कंपनियों की तरह नहीं बनी थी — यह इसलिए बनी क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ फेल हो रही थीं और लोगों को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं था। LIC का 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया और यह लॉन्ग-टर्म बचत और सुरक्षा के लिए एक भरोसेमंद ऑर्गनाइज़ेशन बन गई।
- इसके ब्रांड, पहुँच और सुरक्षा के वादे (इसकी मशहूर टैगलाइन) ने इसे भारत में सबसे भरोसेमंद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बना दिया।

डीमर्जर के खिलाफ मुख्य तर्क

a. भरोसा और लॉन्ग-टर्म सुरक्षा
- इंश्योरेंस भरोसे के बारे में है — लोग लॉन्ग-टर्म सपोर्ट की उम्मीद में पॉलिसी खरीदते हैं।
- LIC को बांटने से यह भरोसा कमज़ोर हो सकता है क्योंकि पॉलिसीहोल्डर्स को चिंता हो सकती है कि उनके लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा।

b. LIC की कई भूमिकाएँ हैं

LIC सिर्फ़ एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर नहीं है — यह इसके अलावा:
- लाखों परिवारों से लॉन्ग-टर्म बचत जुटाती है।
- लॉन्ग-टर्म सरकारी बॉन्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने में मदद करती है।
- सामाजिक उद्देश्यों (जैसे ग्रामीण बीमा) को कमर्शियल कामों के साथ बैलेंस करती है।
- इसे बांटने से इन सभी कामों को अच्छी तरह से करने की इसकी क्षमता कमज़ोर हो सकती है।

c. ग्लोबल उदाहरण जोखिम दिखाते हैं
- यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को तोड़ने से गवर्नेंस और भरोसे की समस्याएँ हुईं।
- डीम्यूचुअलाइज़ेशन के बाद जब कुछ इंश्योरेंस कंपनियों को मार्केट के दबाव का सामना करना पड़ा, तो वे ढह गईं।

भारत का मौजूदा संदर्भ मायने रखता है
- भारत में अभी भी कई लोगों के लिए सीमित पेंशन कवरेज और सोशल सिक्योरिटी है।
- LIC रिटायरमेंट इनकम और लॉन्ग-टर्म सुरक्षा के लिए एक बैकअप संस्था के रूप में काम करती है।

- मज़बूत विकल्प मौजूद होने से पहले LIC को कमज़ोर करने से जोखिम परिवारों पर आ सकता है।

मार्केट शेयर पूरी कहानी नहीं है

- LIC का लीडिंग मार्केट शेयर का मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि यह गलत तरीके से हावी है क्योंकि यह छोटे टिकट और ग्रामीण ग्राहकों को भी सेवा देती है।
- प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ शहरी और ज़्यादा इनकम वाले ग्राहकों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, इसलिए उनकी सीधे तुलना करना आसान नहीं है।

सुधारों को स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए, न कि बांटने पर

LIC को तोड़ने के बजाय, एक्सपर्ट्स ऐसे सुधारों का सुझाव देते हैं:

- सामाजिक बनाम कमर्शियल लक्ष्यों का स्पष्ट अलगाव।
- मज़बूत गवर्नेंस और एनालिटिक्स का बेहतर इस्तेमाल।
- बेहतर कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट, और परफॉर्मेंस की बेहतर उम्मीदें।

भारत के बड़े आर्थिक लक्ष्यों में LIC की भूमिका

- LIC की बड़ी बैलेंस शीट बाज़ारों को स्थिर करने और लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने में मदद करती है।
- इसे अभी तोड़ने से यह क्षमता कमज़ोर हो सकती है, जबकि भारत "2047 तक सभी के लिए बीमा" जैसे लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

SIDBI से MSME

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) में ₹5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम का मकसद SIDBI के कैपिटल बेस को मज़बूत करना और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को क्रेडिट फ्लो को काफी बढ़ाना है।

इक्विटी कैपिटल को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ (DFS) द्वारा चरणों में निवेश किया जाएगा:

- FY 2025–26 में ₹3,000 करोड़ (31 मार्च 2025 तक बुक वैल्यू पर)।
- FY 2026–27 और FY 2027–28 में प्रत्येक में ₹1,000 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बुक वैल्यू के आधार पर)।

क्रेडिट पहुंच का अपेक्षित विस्तार

निवेश के बाद, SIDBI से वित्तीय सहायता पाने वाले MSMEs की संख्या 76.26 लाख (FY25 के अंत तक) से बढ़कर लगभग 1.02 करोड़ (FY28 के अंत तक) होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 25.74 लाख नए MSME लाभार्थी जुड़ेंगे।

रोजगार पर प्रभाव

MSME मंत्रालय के आंकड़ों (30 सितंबर 2025 तक) के आधार पर, लगभग 6.90 करोड़ MSMEs में लगभग 30.16 करोड़ लोग काम करते हैं, यानी प्रति एंटरप्राइज औसतन 4.37 व्यक्ति। इस मीट्रिक का उपयोग करके, विस्तारित सहायता से FY28 के अंत तक लगभग 1.12 करोड़ नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं।

पूंजी पर्याप्तता और उधार क्षमता

SIDBI की रिस्क-वेटेड एसेट्स (RWA) में विस्तारित उधार, नए डिजिटल क्रेडिट उत्पादों और स्टार्ट-अप के लिए वेंचर डेट के कारण वृद्धि होने की उम्मीद है - जिससे मज़बूत पूंजी समर्थन की आवश्यकता बढ़ जाएगी। इक्विटी निवेश SIDBI को तनावपूर्ण स्थितियों में भी नियामक मानदंडों से ऊपर एक स्वस्थ कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) बनाए रखने में मदद करेगा।

क्रेडिट सृजन और ब्याज दरें

अतिरिक्त पूंजी SIDBI को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर धन जुटाने में सक्षम बनाएगी, जिससे MSMEs को किफायती क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा।

SIDBI के बारे में

SIDBI भारत में MSME क्षेत्र के प्रचार, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। 1990 में संसद के एक एक्ट के तहत स्थापित, SIDBI MSMEs को क्रेडिट, रीफाइनेंस और डेवलपमेंटल सर्विस के साथ सपोर्ट करता है।

- मुख्यालय: लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- चेयरमैन और MD: मनोज मित्तल

भारत में MSMEs का महत्व

MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं:
वे GDP, एक्सपोर्ट और रोज़गार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
वे बड़े उद्योगों के लिए सहायक इकाइयों के रूप में काम करते हैं और क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन को बढ़ाते हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, MSMEs करोड़ों लोगों को रोज़गार देते हैं और भारत के औद्योगिक उत्पादन और एक्सपोर्ट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

पूंजी पर्याप्तता अवधारणाएँ

कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेश्यो (CRAR) किसी वित्तीय संस्थान की संभावित नुकसान को झेलने और सॉल्वेंट बने रहने की क्षमता का एक प्रमुख संकेतक है। क्रेडिट रेटिंग की रक्षा करने और बैंकों/वित्तीय संस्थानों को उचित लागत पर फंड जुटाने में सक्षम बनाने के लिए एक स्वस्थ CRAR बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

औपचारिक क्रेडिट पर सरकार का फोकस

यह निवेश इन प्रयासों का हिस्सा है:

- MSMEs के लिए क्रेडिट तक पहुंच में सुधार करना
- छोटे उद्यमों के औपचारिककरण को बढ़ावा देना
- डिजिटल और बिना गारंटी वाले लोन उत्पादों को सपोर्ट करना
- स्टार्ट-अप के लिए वेंचर डेट सुविधाओं को सक्षम बनाना

समाचार संक्षिप्त में

भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

चर्चा में क्यों?

2025 में भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति के "गोल्डीलॉक्स पल" का अनुभव करते हुए दिखाया गया है, जो एक मजबूत विस्तार पथ को दर्शाता है। लगभग 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नॉमिनल जीडीपी के साथ, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2030 तक भारत का जीडीपी 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे यह जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2025 में आर्थिक गति को मजबूत घरेलू मांग, व्यावसायिक निवेश, निर्यात वृद्धि और कम होती मुद्रास्फीति से समर्थन मिला, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन को दर्शाता है।

आर्थिक विकास संकेतक

2025 में भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि मजबूत बनी रही, तिमाही विकास दर लगातार 7% से ऊपर रही, जो सभी क्षेत्रों में निरंतर विस्तार का संकेत देती है। विकास व्यापक आधार वाला रहा है, जो सेवाओं, उद्योग और उपभोग से प्रेरित है, जो मिलकर समग्र आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हैं।

मुद्रास्फीति और मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता

2025 में मुद्रास्फीति दरें मध्यम या कम रहीं, जिससे "गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था" में योगदान मिला - ऐसा विकास जो न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा, जो स्थायी विस्तार का समर्थन करता है।
नियंत्रित मुद्रास्फीति क्रय शक्ति में सुधार करती है और स्थिर मूल्य निर्धारण वातावरण बनाए रखकर निवेश को प्रोत्साहित करती है।

रोजगार और श्रम संकेतक

2025 के अंत में बेरोजगारी दर में गिरावट आई, जिससे रोजगार सृजन और श्रम बाजार में भागीदारी में सुधार दिखा। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आमतौर पर उच्च श्रम बल भागीदारी, रोजगार के अवसर और आय सृजन की ओर ले जाती है, खासकर युवाओं के बीच।

निर्यात और बाहरी क्षेत्र
माल और सेवाओं के निर्यात में लगातार सुधार हुआ है, जिससे मजबूत व्यापार प्रदर्शन और विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने में मदद मिली है। एक लचीला बाहरी क्षेत्र आर्थिक स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।

वैश्विक आर्थिक रैंकिंग
भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में इसकी बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाता है। निरंतर विस्तार से भारत 2030 तक जर्मनी से आगे निकलकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

ADNOC गैस - HPCL डील साइन

चर्चा में क्यों?
अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस (ADNOC गैस) ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के साथ 2.5 बिलियन डॉलर से 3 बिलियन डॉलर के बीच का 10-साल का लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। यह समझौता UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान हुआ, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो भारत-UAE के बीच बढ़ते ऊर्जा सहयोग को दिखाता है।

अवधि और मात्रा
यह डील 2028 से शुरू होकर 10 साल की अवधि के लिए है। समझौते के अनुसार, ADNOC गैस HPCL को सालाना 0.5 मिलियन टन (mtpa) LNG की सप्लाई करेगी।

भारत-UAE रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना
भारत UAE का सबसे बड़ा LNG ग्राहक बन गया है, जो ऊर्जा व्यापार की गतिशीलता में बदलाव और पारंपरिक तेल आयात से परे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर प्रकाश डालता है।

ADNOC गैस और UAE की एनर्जी डिप्लोमेसी
ADNOC गैस UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) की एक सब्सिडियरी कंपनी है, जो LNG एक्सपोर्ट सहित नेचुरल गैस वैल्यू चेन पर फोकस करती है। UAE भू-राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए तेल के अलावा एनर्जी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, खासकर भारत जैसे एशिया के तेजी से बढ़ते बाजारों के साथ।

भारत-जर्मनी टेलीकॉम सहयोग समझौता

चर्चा में क्यों?
भारत और जर्मनी ने टेलीकम्युनिकेशन सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र (JDI) पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय डिजिटल सहयोग में एक महत्वपूर्ण विकास है।

भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी
भारत और जर्मनी 2000 से एक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। जर्मनी भारत के प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक भागीदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत में 2,000 से अधिक जर्मन कंपनियाँ काम करती हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंधों को दर्शाती हैं।

टेलीकम्युनिकेशन और ICT: नीतिगत प्रासंगिकता
टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास और डिजिटल इंडिया जैसे शासन सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है। ICT सहयोग 5G/6G प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल समावेशन में नवाचार का समर्थन करता है - जो वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। JDI जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे नियामक मानकों को संरेखित करने, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाने में मदद करते हैं।

भारत-इज़राइल ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

भारत और इज़राइल ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

क्या हुआ?

भारत और इज़राइल ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

यह क्यों मायने रखता है

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास में भारत और इज़राइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को मान्यता देता है। खाद्य सुरक्षा, आजीविका और आर्थिक विकास के लिए मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने और स्थायी समुद्री संसाधन प्रथाओं का विस्तार करने के भारत के चल रहे एजेंडे का समर्थन करता है।

नेपाल और भारत कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत

चर्चा में क्यों?

नेपाल और भारत कृषि सहयोग को गहरा करने और मौजूदा समझौतों को ठोस नतीजों में बदलने के लिए अगले तीन महीनों के भीतर मिलकर एक दो-सालाना कार्य योजना बनाने और लागू करने पर सहमत हुए हैं। यह फैसला काठमांडू में नेपाल-भारत संयुक्त कृषि कार्य समूह की 9वीं बैठक के दौरान लिया गया।

भारत-नेपाल संबंध:

भारत और नेपाल 1950 की शांति और मैत्री संधि, सांस्कृतिक संबंधों और खुली सीमा आवाजाही के आधार पर एक अद्वितीय द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। नेपाल भारत की दक्षिण एशियाई नीति के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, और सहयोग व्यापार, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और कृषि तक फैला हुआ है। भारत 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का पालन करता है, जिसमें नेपाल सहित पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी जाती है।

कृषि सहयोग:

- कृषि भारत और नेपाल दोनों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है और खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
- ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए भारत का प्रमुख निकाय है।
- NARC (नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद) नेपाल का अग्रणी कृषि अनुसंधान संगठन है।
- संयुक्त सहयोग जलवायु-लचीली फसलों, बेहतर बीजों, आधुनिक खेती तकनीकों और पशुधन सुधारों को विकसित करने में मदद कर सकता है।
- डिजिटल कृषि, जैसे सटीक खेती प्रौद्योगिकियां, उत्पादकता और स्थिरता में काफी वृद्धि कर सकती हैं।

भू-राजनीतिक संदर्भ:

- भारत और नेपाल SAARC और BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय मंचों में सहयोग करते हैं, जिससे कृषि सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता है।
- सीमा पार सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और साझा विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देता है।

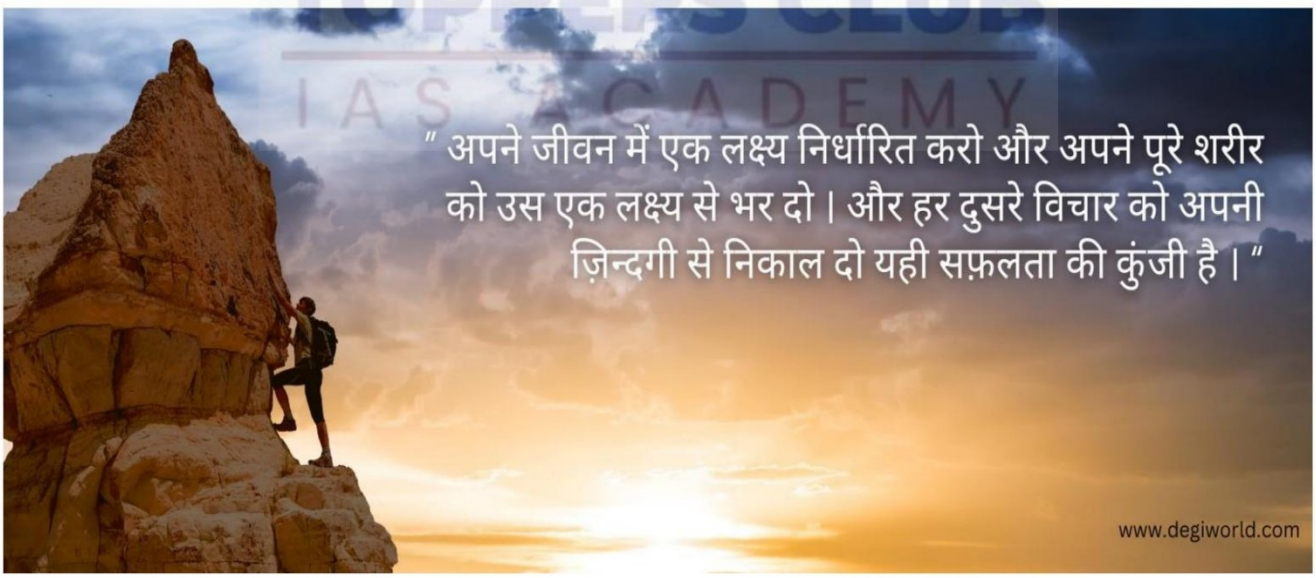

रक्षा एवं सुरक्षा

डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड

चर्चा में क्यों?

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को हासिल करने का नया प्रयास 2026 की शुरुआत में एक बड़ा भू-राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। ग्रीनलैंड - एक विशाल आर्कटिक द्वीप और डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र - वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र में स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ट्रंप की इस बात पर ज़ोर कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की "बहुत बुरी तरह" ज़रूरत है, ने बहस और राजनयिक विरोध को जन्म दिया है, खासकर ग्रीनलैंड और डेनिश नेताओं की ओर से।

ग्रीनलैंड कहाँ है और स्थान क्यों मायने रखता है

ग्रीनलैंड का महत्व काफी हद तक इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा है:

- यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है, जो आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक तक पहुँच को नियंत्रित करता है।
- इसका इलाका महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और GIUK गैप (ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूनाइटेड किंगडम) पर नज़र रखता है, जो एक महत्वपूर्ण नौसैनिक और पनडुब्बी निगरानी गलियारा है।
- यह आर्कटिक उड़ान मार्गों और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री बर्फ पिघलने से खुलने वाले संभावित नए शिपिंग मार्गों पर स्थित है।
- आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित होने के कारण, यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और मिसाइल रक्षा के लिए रणनीतिक लाभ प्रदान करता है।
- यह भूगोल ग्रीनलैंड को न केवल रक्षा के लिए, बल्कि आर्कटिक में वैश्विक प्रभाव के लिए भी मूल्यवान बनाता है, जो नए मार्गों और संसाधनों तक पहुँच के उभरने के साथ तेजी से एक विवादित क्षेत्र बनता जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य रणनीतिक हित

ट्रंप के तर्क का एक मुख्य हिस्सा राष्ट्रीय सुरक्षा के इर्द-गिर्द घूमता है:

- संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से ही उत्तरी ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस (पूर्व में थुले एयर बेस) संचालित करता है, जो मिसाइल चेतावनी प्रणालियों, मिसाइल रक्षा और अंतरिक्ष निगरानी का समर्थन करता है।
- ट्रंप ने दावा किया है कि ग्रीनलैंड का मालिक होने से अमेरिका को प्रारंभिक चेतावनी रडार स्थापना और रक्षा बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की अनुमति मिलेगी, खासकर रूस और चीन से संभावित खतरों की निगरानी के लिए।
- उन्होंने दावा किया है कि आर्कटिक में रणनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड आवश्यक है।
- हालांकि, विशेषज्ञ ध्यान देते हैं कि जबकि यह द्वीप रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ग्रीनलैंड के पास रूसी या चीनी सैन्य उपस्थिति सीमित है - और ट्रंप की बयानबाजी कथित खतरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है।

आर्थिक और संसाधन क्षमता

माना जाता है कि ग्रीनलैंड में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, जो इसे आर्थिक रूप से आकर्षक बनाते हैं:

- दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के बड़े भंडार, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और सैन्य हार्डवेयर जैसी टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की संभावित मात्रा का भी अनुमान लगाया गया है, हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ के नीचे है और इसके लिए महंगा निष्कर्षण आवश्यक है।
- कुछ विश्लेषकों द्वारा विदेशी दुर्लभ पृथ्वी आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से चीन पर निर्भरता कम करना रणनीतिक रूप से मूल्यवान माना जाता है।
- हालांकि संसाधन निष्कर्षण तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील बना हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी और रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सामग्रियों का दीर्घकालिक वादा ग्रीनलैंड की अपील को बढ़ाता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और संप्रभुता के मुद्दे

- ग्रीनलैंड के नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनने के किसी भी विचार को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, और डेनमार्क, नाटो और यूरोपीय संघ से जुड़े रहने के अपने विकल्प पर जोर दिया है।

- नाटो सदस्य डेनमार्क भी किसी भी जबरन अधिग्रहण का विरोध करता है, और चेतावनी देता है कि ऐसा कोई भी कार्य गठबंधन में तनाव पैदा कर सकता है या उसे खत्म भी कर सकता है।
- ग्रीनलैंड स्वयं व्यापक स्व-शासन का प्रयोग करता है, और संप्रभुता में किसी भी बदलाव के लिए ग्रीनलैंडवासियों और डेनमार्क की सहमति की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष: रणनीति, बिक्री नहीं

ग्रीनलैंड के लिए ट्रम्प का दबाव अधिग्रहण की किसी भी औपचारिक कानूनी या राजनयिक मार्ग के बजाय भू-राजनीतिक रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं और आर्थिक हितों का मिश्रण दर्शाता है। जबकि ग्रीनलैंड आर्कटिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है, इसका भविष्य - चाहे डेनमार्क के भीतर एक मजबूत स्व-शासित क्षेत्र के रूप में हो या व्यापक अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक ढांचे का हिस्सा हो - अंतरराष्ट्रीय कानून, कूटनीति और इसके अपने लोगों की पसंद से निर्धारित होगा।

प्रलय मिसाइल

चर्चा में क्यों?

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के हिस्से के रूप में ओडिशा तट से एक ही लॉन्चर से लगातार दो स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइलों का साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया। दोनों मिसाइलों ने अपने तय रास्ते का सटीक रूप से पालन किया और मिशन के सभी उद्देश्यों को हासिल किया, जिससे मिसाइल सिस्टम की उच्च सटीकता, विश्वसनीयता और ऑपरेशनल तैयारी का प्रदर्शन हुआ।

प्रलय मिसाइल के बारे में

- श्रेणी: क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल
- प्रणोदन: सॉलिड प्रोपेलेंट
- रेंज: लगभग 150–500 किमी (पेलोड पर निर्भर)
- लॉन्च प्लेटफॉर्म: रोड-मोबाइल लॉन्चर
- वॉरहेड क्षमता: विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है
- गाइडेंस सिस्टम: उच्च सटीकता के लिए उन्नत नेविगेशन और गाइडेंस

पिनाका रॉकेट

चर्चा में क्यों?

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से 120-किमी रेंज की पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR-120) का पहला फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किया, जो स्वदेशी तोपखाने की क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि है।

विकास और शामिल संस्थान:

- आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ARDE) द्वारा विकसित।
- हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (HEMRL), डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL) और रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) द्वारा समर्थित।
- कई DRDO प्रयोगशालाओं के बीच सफल सहयोग को दर्शाता है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- पिनाका DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) सिस्टम है।
- यह कुछ ही सेकंड में रॉकेट के कई गोले दाग सकता है, जिससे दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है।
- पिनाका Mk-I की रेंज लगभग 40 किमी है।
- पिनाका Mk-II रेंज को बढ़ाकर लगभग 90 किमी कर देता है।
- गाइडेड पिनाका वेरिएंट नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके सटीकता में सुधार करते हैं।
- पिनाका को पहली बार 1990 के दशक के आखिर में भारतीय सेना में शामिल किया गया था।
- इसका इस्तेमाल कारगिल युद्ध (1999) के दौरान ऑपरेशनल रूप से किया गया था।
- यह सिस्टम हाई-मोबिलिटी वाहनों पर लगा होता है, जिससे तेजी से तैनाती और शूट-एंड-स्कूट क्षमता मिलती है।

समाचार संक्षिप्त में

CQB कार्बाइन और हेवीवेट टॉरपीडो

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन और हेवीवेट टॉरपीडो की खरीद के लिए 4,666 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। 2,770 करोड़ रुपये की कीमत के 4.25 लाख से ज़्यादा CQB कार्बाइन और एक्सेसरीज़ भारतीय निजी कंपनियों द्वारा भारतीय सेना और भारतीय नौसेना को सप्लाई किए जाएंगे। प्रोजेक्ट-75 के तहत भारतीय नौसेना की कलवरी-क्लास पनडुब्बियों के लिए 48 हेवीवेट टॉरपीडो और संबंधित उपकरणों के लिए 1,896 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट पुराने सिस्टम की जगह लेंगे और स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देंगे, जिससे रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता मज़बूत होगी।

क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन

CQB कार्बाइन कॉम्पैक्ट, हल्के हथियार हैं जिन्हें शहरी युद्ध, आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी जैसे करीबी मुकाबले के ऑपरेशन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये उच्च गतिशीलता और तेज़ मारक क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे करीबी मुकाबले में इन्फैंट्री की प्रभावशीलता में सुधार होता है। इनकी खरीद में भारतीय निजी रक्षा कंपनियाँ शामिल हैं, जो घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाने की सरकार की पहल का समर्थन करती हैं।

हेवीवेट टॉरपीडो

हेवीवेट टॉरपीडो उन्नत पानी के नीचे के हथियार हैं जिनका उपयोग पनडुब्बियाँ दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए करती हैं, जिससे नौसेना की आक्रामक क्षमता बढ़ती है। इन टॉरपीडो को प्रोजेक्ट-75 के तहत कलवरी-क्लास पनडुब्बियों पर तैनात किया जाएगा। डिलीवरी अप्रैल 2028 में शुरू होने और 2030 की शुरुआत तक पूरी होने वाली है, जिससे भारत के पनडुब्बी बेड़े को मज़बूती मिलेगी।

राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा और प्रोफेशनलिज़्म के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारत में पुलिस बलों के लिए सबसे बड़े और दुर्लभ सम्मानों में से एक है, जो विशिष्ट और लंबे समय तक की सेवा की पहचान के रूप में दिया जाता है।

यह पुरस्कार किस बात का प्रतीक है

- इस पुरस्कार को "निशान" भी कहा जाता है।
- यह पुलिस बल की बहादुरी, अनुशासन और समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह प्रतीक चिन्ह गर्व के निशान के तौर पर पुलिस वर्दी की बाईं आस्तीन पर पहना जाता है।

ऐतिहासिक महत्व

भारत की आज़ादी के बाद से, केवल 14 राज्य पुलिस बलों को यह सम्मान मिला था। इस पुरस्कार के साथ, सिक्किम 15वां राज्य पुलिस बल बन गया है जिसे सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, असम और त्रिपुरा के बाद सिक्किम इसे पाने वाला तीसरा राज्य है।

यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर कैसे दिया जाता है

यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद गृह मंत्रालय द्वारा तय किया गया और सूचित किया गया। एक कलर प्रेजेंटेशन परेड में बाद में सिक्किम पुलिस को औपचारिक रूप से झंडा और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाएगा।

यह क्यों मायने रखता है

राष्ट्रपति पुलिस कलर्स हर साल नहीं दिए जाते हैं और यह केवल उन बलों को मिलते हैं जिन्होंने कई सालों तक अनुकरणीय और लगातार सेवा दी हो। यह पुरस्कार सिक्किम पुलिस की पेशेवर ईमानदारी, साहस, अनुशासन और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है।

सामूहिक पहचान
सिक्किम पुलिस के वर्तमान और सेवानिवृत्त दोनों कर्मियों को इस उपलब्धि का हिस्सा माना जाता है। यह पुरस्कार वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों तक, पूरे बल के प्रयासों को दर्शाता है।

भारत में वीरता पुरस्कार

प्रस्तावना
वीरता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से हैं, जो सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिखाए गए असाधारण शौर्य, साहस और आत्म-बलिदान को पहचानने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार उन लोगों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को दर्शाते हैं जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर घोषित किए जाने वाले वीरता पुरस्कार देशभक्ति को प्रेरित करते हैं और कर्तव्य और सम्मान के मूल्यों को बनाए रखते हैं।

वीरता पुरस्कार क्या हैं?
वीरता पुरस्कार युद्ध और शांति काल के अभियानों के दौरान किए गए वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिए जाते हैं। शांति काल में, ये पुरस्कार आतंकवाद विरोधी अभियानों, बचाव अभियानों, आपदा प्रतिक्रिया और अन्य उच्च जोखिम वाली ड्यूटी में दिखाए गए साहस को पहचानते हैं।

तीन मुख्य शांति काल के वीरता पुरस्कार हैं:
1. अशोक चक्र – सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार
2. कीर्ति चक्र – दूसरा सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार
3. शौर्य चक्र – तीसरा सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार

ये पुरस्कार कर्तव्य से परे असाधारण साहस और समर्पण को स्वीकार करते हैं।

वीरता पुरस्कारों का महत्व
वीरता पुरस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका है:
- सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए गए शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करना
- सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ाना
- युवाओं को साहस और अनुशासन के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करना
- राष्ट्रीय गौरव और वर्दीधारी सेवाओं के प्रति सम्मान को मजबूत करना
- वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वीरता के कार्यों को राष्ट्र द्वारा याद किया जाए और उनका जश्न मनाया जाए।

गणतंत्र दिवस 2026 पर वीरता पुरस्कार
गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को 70 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी।
पुरस्कारों का विवरण
- 1 अशोक चक्र
- 3 कीर्ति चक्र
- 13 शौर्य चक्र

कई पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए, जो सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हैं।

इस वर्ष के उल्लेखनीय पुरस्कार विजेता
अशोक चक्र:
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (भारतीय वायु सेना) को असाधारण साहस और विशिष्ट सेवा के लिए।

कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं:
- मेजर अर्शदीप सिंह
- नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा
- ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर

शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं:

लेफ्टिनेंट कर्नल घटागे आदित्य श्रीकुमार और अन्य बहादुर कर्मी जिन्होंने अभियानों के दौरान उल्लेखनीय वीरता दिखाई। ये पुरस्कार विजेता साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के उच्चतम मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

निष्कर्ष

वीरता पुरस्कार भारत के साहस और बलिदान के प्रति सम्मान के शक्तिशाली प्रतीक हैं। बहादुर व्यक्तियों को सम्मानित करके, राष्ट्र न केवल उनके शौर्य को स्वीकार करता है, बल्कि देशभक्ति, निस्वार्थता और सेवा के मूल्यों को भी मजबूत करता है। गणतंत्र दिवस 2026 के वीरता पुरस्कार विजेता साहस के चमकते उदाहरण हैं, जो नागरिकों को याद दिलाते हैं कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा उन असाधारण व्यक्तियों द्वारा सुरक्षित है जो सम्मान और निडरता के साथ सेवा करते हैं।

माह का सैन्य अभ्यास

डेजर्ट साइक्लोन-II

भारत-UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास "डेजर्ट साइक्लोन-II" का दूसरा संस्करण लगभग दो हफ़्ते की गहन ट्रेनिंग के बाद अबू धाबी के अल-हमरा ट्रेनिंग सिटी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभ्यास में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा सहयोग को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया गया।

शहरी और उप-पारंपरिक अभियानों पर फोकस

शहरी युद्ध प्रशिक्षण में घनी आबादी वाले निर्मित क्षेत्रों में अभियानों का सिमुलेशन किया जाता है। उप-पारंपरिक अभियानों में शांति स्थापना, आतंकवाद विरोधी और स्थिरता मिशन शामिल हैं। इस तरह की ट्रेनिंग आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करती है।

मुख्य प्रशिक्षण घटक

- क्लासरूम ट्रेनिंग: मिशन योजना, सामरिक चर्चा और रणनीति निर्माण।
- फील्ड ड्रिल: बिल्डिंग क्लीयरेंस, गश्त और शहरी हमले के अभ्यास।
- हताहतों को निकालना और प्राथमिक उपचार: युद्ध के मैदान में जीवित रहने की क्षमता बढ़ाता है।
- विशेष अभियान: हेलीकॉप्टर से होने वाले ऑपरेशन, हवाई हमले के अभ्यास और प्लाटून-स्तर के संयुक्त अभ्यास।

अन्य भारत-UAE अभ्यास:

1. डेजर्ट ईगल

- प्रकार: द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास
- फोकस: हवाई युद्ध, अवरोधन और सामरिक अभियान
- उद्देश्य: वायु सेना की इंटरऑपरेबिलिटी और रणनीतिक हवाई रक्षा समन्वय को बढ़ाना
- आवृत्ति: आवधिक, भारत और UAE के बीच बारी-बारी से

2. नसीम अल-बहर / समुद्री अभ्यास

- प्रकार: नौसैनिक अभ्यास (कभी-कभी इंडो-UAE नौसैनिक अभ्यास भी कहा जाता है)
- फोकस: समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी अभियान, खोज और बचाव, और तटीय रक्षा
- उद्देश्य: समुद्री सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को मज़बूत करना
- महत्व: हिंद महासागर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करता है

3. डेजर्ट नाइट / डेजर्ट शील्ड (नियोजित / वैचारिक)

- प्रकार: संयुक्त सेना अभ्यास (भूमि सेना)
- फोकस: आतंकवाद विरोधी, मशीनीकृत अभियान और रेगिस्तानी युद्ध
- उद्देश्य: रेगिस्तानी/शुष्क वातावरण में युद्ध की तैयारी को बढ़ाना
- स्थिति: सीमित संस्करण, अक्सर विशिष्ट सेना सहयोग ढांचे के तहत

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

अरावली पुनर्परिभाषा विवाद

अरावली पुनर्परिभाषा विवाद क्या है?

अरावली पहाड़ियाँ — दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक, जो दिल्ली से हरियाणा और राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई है — भारत में एक गरमागरम पर्यावरणीय और कानूनी विवाद के केंद्र में हैं। यह विवाद 2025 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सरकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर अरावली श्रृंखला की एक नई परिभाषा को स्वीकार करने के बाद शुरू हुआ। आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सुरक्षा को कमजोर करता है और पहले से सुरक्षित क्षेत्रों में खनन और विकास को बढ़ावा दे सकता है।

नई परिभाषा: क्या बदला?

नई स्वीकृत मानदंडों के तहत:

- किसी पहाड़ी को कानूनी रूप से अरावली श्रृंखला का हिस्सा माने जाने के लिए उसे अपने आसपास के ज़मीन के स्तर से कम से कम 100 मीटर ऊपर उठना चाहिए।
- एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में ऐसी दो या दो से ज़्यादा पहाड़ियाँ मिलकर एक अरावली श्रृंखला बनाती हैं।
- इसने पहले के और ज़्यादा जटिल मानदंडों की जगह ले ली है, जिनमें ढलान, ऊँचाई और निकटता जैसे कई मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता था।

यह क्यों मायने रखता है: पर्यावरणीय चिंताएँ

आलोचक — जिनमें पर्यावरणविद्, वैज्ञानिक, कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता शामिल हैं — तर्क देते हैं कि नई परिभाषा:

- पारंपरिक अरावली पहाड़ियों के 90% से ज़्यादा हिस्से को बाहर कर देती है, जो 100 मीटर से कम ऊँची हैं लेकिन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- इन क्षेत्रों को खनन, निर्माण और भूमि परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- उत्तर-पश्चिम भारत में, खासकर दिल्ली-एनसीआर के आसपास, भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता, हवा की गुणवत्ता और मरुस्थलीकरण के प्रतिरोध को खतरा है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के अनुसार, केवल लगभग 8.7% पहाड़ियाँ ही नए ऊँचाई मानदंड को पूरा करती हैं, जो दर्शाता है कि श्रृंखला का बड़ा हिस्सा अपनी संरक्षित स्थिति खो सकता है।

राजनीतिक और सार्वजनिक विरोध

पुनर्परिभाषा ने राजनीतिक हस्तियों और राज्य के नेताओं से कड़ी आलोचना बटोरी है:
कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यह कदम अरावली को खनन और रियल एस्टेट हितों द्वारा शोषण के लिए खोल देगा। वे इस परिभाषा को "जानलेवा रूप से दोषपूर्ण" बताते हैं और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हैं।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बदलाव को अवैध खनन के लिए "रेड कार्पेट" बताया और लंबे समय तक पारिस्थितिक नुकसान की चेतावनी दी।

सरकार का रुख

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस परिभाषा का बचाव करते हुए कहा है:

- यह सिर्फ़ माइनिंग पर लागू होता है, रियल एस्टेट जैसी दूसरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर नहीं।
- जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फ़ाइनल नहीं हो जाता, तब तक अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज़ पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।
- इस परिभाषा का मकसद सुरक्षा कानूनों में स्पष्टता और उन्हें लागू करने की क्षमता लाना था।
- केंद्र सरकार इस बात पर भी ज़ोर दे रही है कि अरावली लैंडस्केप का लगभग 90% हिस्सा सुरक्षित रहेगा, और उन दावों का खंडन कर रही है कि सुरक्षा उपायों को वापस ले लिया गया है।

न्यायिक प्रतिक्रिया और चल रही कानूनी समीक्षा

बढ़ती चिंताओं के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या नई परिभाषा अनजाने में निचली पहाड़ियों को छोड़कर पारिस्थितिक सुरक्षा में कमियां पैदा करती है - जिनके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि वे इस रेंज के पर्यावरणीय कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अरावली क्यों महत्वपूर्ण हैं

अरावली पहाड़ियाँ कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिकाएँ निभाती हैं:

- भूजल पुनर्भरण: उनका पथरीला इलाका बारिश के पानी को एक्वीफर में रिसने में मदद करता है।
- हवा की गुणवत्ता: वे धूल भरी आंधी और प्रदूषकों के फैलाव के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में काम करते हैं।
- जैव विविधता: अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करते हैं।
- जलवायु स्थिरता: स्थानीय मौसम को विनियमित करने और मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं।

निष्कर्ष

अरावली की नई परिभाषा का विवाद पर्यावरण संरक्षण और विकास के दबावों के बीच टकराव को उजागर करता है। जबकि सरकार एक स्पष्ट कानूनी ढांचे के लिए तर्क दे रही है, आलोचक चेतावनी देते हैं कि संरक्षित क्षेत्र को छोटा करने से अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। सार्वजनिक आक्रोश और न्यायिक जांच तेज होने के साथ, अरावली पर बहस 2025-26 के भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बनी हुई है।

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (राजस्थान)

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर अरावली पर्वत श्रृंखला (राजस्थान) में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 0 से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) घोषित किया है। इस फैसले का मकसद आसपास के इलाके में इंसानी गतिविधियों को रेगुलेट करके नाज़ुक अरावली इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना है।

घोषणा की मुख्य बातें

संरक्षित क्षेत्र और दायरा

नया ESZ अभयारण्य की सीमा के आसपास लगभग 243 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। ESZ में राजस्थान के उदयपुर, पाली और राजसमंद जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं। नए अधिसूचित ESZ के दायरे में लगभग 94 गाँव आते हैं।

बायोडायवर्सिटी का महत्व

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पेड़-पौधों और जीवों से भरपूर है और यहाँ ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं:

- तेंदुआ
- धारीदार लकड़बग्घा
- जंगली बिल्ली
- भारतीय पैंगोलिन
- नीलगाय
- चिंकारा
- पेंटेड फ्रैंकोलिन (पक्षी प्रजाति)

ESZ के अंदर प्रतिबंध

ESZ नोटिफिकेशन के तहत, कई पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों पर या तो रोक लगा दी गई है या उन्हें रेगुलेट किया गया है:

- खनन, पत्थर की खदानों और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार पर प्रतिबंध।
- नए होटल, रिसॉर्ट और ईंट भट्टों के निर्माण पर रोक।
- जंगलों, कृषि भूमि, पार्कों, पक्षी क्षेत्रों को व्यावसायिक या आवासीय उपयोग में बदलने पर प्रतिबंध।
- हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं और नई पवनचक्की लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

समुदाय-केंद्रित विकास पहल

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि ESZ इन चीज़ों को भी बढ़ावा देगा:

- जैविक खेती और एग्रोफॉरेस्ट्री जैसी पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ प्रथाएँ।
- स्थानीय समुदायों के लिए टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

नियामक निगरानी
सरकार द्वारा नियुक्त एक ESZ निगरानी समिति ESZ दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों के अनुपालन की देखरेख करेगी।

अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य

चर्चा में क्यों?
केरल सरकार ने इसके पारिस्थितिक महत्व को उजागर करने और तितलियों की जैव विविधता की रक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर अरालम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य कर दिया है। यह फैसला राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश पर आधारित था, और नाम बदलने की अधिसूचना 26 दिसंबर, 2025 को जारी की गई थी। यह अभयारण्य अब अपने अद्वितीय तितली आवास की स्थिति को दर्शाता है और केंद्रित संरक्षण और जागरूकता गतिविधियों का समर्थन करता है।

स्थान और पारिस्थितिक महत्व
यह अभयारण्य केरल के कन्नूर जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित है, जो यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत मानदंडों के तहत मान्यता प्राप्त एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। मूल रूप से 1984 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित, यह लगभग 55 वर्ग किमी के उष्णकटिबंधीय और अर्ध-सदाबहार वनों को कवर करता है।

तितली विविधता और प्रवासन
अरालम में 266 से अधिक प्रजातियों की तितलियाँ पाई जाती हैं, जो केरल में दर्ज तितली प्रजातियों का 80% से अधिक है। यहाँ पाई जाने वाली कुछ प्रजातियाँ पश्चिमी घाट की स्थानिक हैं और कुछ लुप्तप्राय हैं, जो अभयारण्य के संरक्षण मूल्य को बढ़ाती हैं।

व्यापक संदर्भ
1. पश्चिमी घाट — वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट
पश्चिमी घाट दुनिया के आठ "सबसे गर्म" जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जिसमें पौधों और जानवरों में स्थानिक प्रजातियों का असाधारण रूप से उच्च स्तर है। अरालम जैसे आवासों की रक्षा करना जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं में योगदान देता है। (सामान्य पारिस्थितिकी संदर्भ)
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
अरालम जैसे अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित हैं, जो वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, और भारत में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन को नियंत्रित करता है।

भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म

चर्चा में क्यों?
भारत सरकार ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह के माध्यम से तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के कंदुकुर मंडल में देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया। इस सुविधा को स्मार्टग्रीन एक्वाकल्चर (SGA) ने लगभग $6 मिलियन (लगभग ₹50–54 करोड़) के शुरुआती निवेश से विकसित किया है। यह भारत का पहला इंटीग्रेटेड इनलैंड ट्राउट फार्म है जहाँ गर्म, इनलैंड क्षेत्र में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ठंडे पानी की रेनबो ट्राउट मछली उगाई जाएगी। यह फार्म रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे नियंत्रित पानी, तापमान और बायोसिक्योरिटी सिस्टम के साथ साल भर ट्राउट का उत्पादन संभव होता है। इस सुविधा की नियोजित उत्पादन क्षमता सालाना 1,200 मीट्रिक टन है और इसमें एक हैचरी, ग्रो-आउट टैंक, प्रोसेसिंग प्लांट और कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 200 नौकरियाँ (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) पैदा होने की उम्मीद है।

एक्वाकल्चर और RAS टेक्नोलॉजी
एक्वाकल्चर का मतलब मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय जीवों की खेती है, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) एक एडवांस्ड क्लोज्ड-लूप फार्मिंग टेक्नोलॉजी है जहाँ मछली टैंक से पानी को लगातार फिल्टर, ट्रीट और रीसायकल किया जाता है, जिससे गर्म जलवायु में भी संवेदनशील या ठंडे पानी की प्रजातियों के लिए आदर्श

स्थिति बनी रहती है। RAS टेक्नोलॉजी पारंपरिक खुले पानी या तालाब प्रणालियों की तुलना में पानी के उपयोग को कम करती है, पर्यावरणीय उत्सर्जन को कम करती है, और बायोसिक्योरिटी और विकास की स्थितियों में सुधार करती है।

भारत में रेनबो ट्राउट और मत्स्य पालन

रेनबो ट्राउट (Oncorhynchus mykiss) प्रशांत महासागर की सहायक नदियों में पाई जाने वाली ठंडे पानी की मछली है और यह एक मूल्यवान उच्च-प्रोटीन, पौष्टिक खाद्य मछली है। ऐतिहासिक रूप से भारत में, प्राकृतिक ठंडे पानी की उपलब्धता के कारण ट्राउट फार्मिंग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे हिमालयी राज्यों तक ही सीमित थी। भारत दुनिया में सबसे बड़े मछली उत्पादकों में से एक है, जिसमें एक्वाकल्चर कुल मछली उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देता है। एक्वाकल्चर क्षेत्र ग्रामीण और तटीय समुदायों में लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है और पोषण, आय सृजन और निर्यात आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकारी मत्स्य पालन पहल

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) मछली उत्पादन बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, निर्यात बढ़ाने और मछली किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक प्रमुख योजना है।
- केंद्र सरकार उत्पादन में विविधता लाने और मत्स्य पालन क्षेत्र के स्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित एक्वाकल्चर, स्किल ट्रेनिंग और स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देती है।

समाचार संक्षिप्त में

गुजरात फिर से 'टाइगर स्टेट' घोषित

चर्चा में क्यों?

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने तीन दशकों से ज़्यादा समय के बाद गुजरात को आधिकारिक तौर पर 'टाइगर-मौजूद राज्य' के रूप में मान्यता दी है, क्योंकि दाहोद ज़िले के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में एक बाघ की लगातार मौजूदगी के पक्के सबूत मिले हैं। इस शामिल होने से गुजरात ऑल-इंडिया टाइगर एस्टीमेशन (AITE) 2026 के लिए भारत के टाइगर मैप पर वापस आ गया है।

पृष्ठभूमि और महत्व

- ऐतिहासिक विलुप्ति: 1990 के दशक की शुरुआत तक आवास के नुकसान, शिकार में कमी और मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण गुजरात से बाघ गायब हो गए थे।
- 2019 में एक आने-जाने वाले बाघ को देखा गया था, लेकिन यह थोड़े समय के लिए था, जो मजबूत आवास सहायता की आवश्यकता को उजागर करता है।
- वर्तमान स्थायी बाघ का लंबे समय तक रहना अनुकूल आवास और पारिस्थितिक स्थितियों को इंगित करता है, जो क्षेत्र के लिए वन्यजीव संरक्षण परिणामों में एक सकारात्मक बदलाव है।
- नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत 2005 में स्थापित, यह बाघ संरक्षण की देखरेख करता है और राज्यों को कानूनी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।
- ऑल-इंडिया टाइगर एस्टीमेशन (AITE): पूरे भारत में बाघों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए हर चार साल में कैमरा ट्रैप, पदचिह्न और सांख्यिकीय मॉडलिंग का उपयोग करके आयोजित किया जाता है।
- टाइगर रिज़र्व: प्रोजेक्ट टाइगर (1973) के तहत महत्वपूर्ण बाघ आवासों की रक्षा के लिए केंद्रित संरक्षण योजना के माध्यम से नामित; रतनमहल भविष्य में एक टाइगर रिज़र्व बन सकता है। बड़ी बिल्लियों की इकोलॉजी: बाघ, शेर और तेंदुए अलग-अलग इकोलॉजिकल जगहों पर रहते हैं - बाघ घने जंगलों को पसंद करते हैं, शेर घास के मैदानों में फलते-फूलते हैं, और तेंदुए अलग-अलग तरह के इलाकों में खुद को ढाल लेते हैं।

SKOCH अवार्ड

चर्चा में क्यों?

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) को "रिसोर्सिंग विकसित भारत" थीम वाले 104वें SKOCH समिट में अपने सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन (CBS) के लिए SKOCH अवार्ड-2025 से सम्मानित किया गया है।

सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन (CBS) क्या है?

- परिभाषा: CBS एक स्वदेशी आपदा और आपातकालीन अलर्ट प्लेटफॉर्म है जिसे C-DOT ने सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए मोबाइल फोन पर आपातकालीन अलर्ट तेज़ी से फैलाने के लिए विकसित किया है।
- कार्य: यह प्राकृतिक आपदाओं (जैसे चक्रवात, बाढ़, सुनामी) और आपात स्थितियों के लिए अलर्ट को निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में मोबाइल फोन पर नेटवर्क को ओवरलोड किए बिना प्रसारित करके लगभग रीयल-टाइम में चेतावनी देने में सक्षम बनाता है।
- एकीकरण: यह भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), और अन्य जैसी प्रमुख आपदा अलर्ट एजेंसियों को मोबाइल ऑपरेटरों, NDMA और SDMA के साथ समन्वित अलर्ट प्रसार के लिए जोड़ता है।

SKOCH अवार्ड के बारे में

SKOCH अवार्ड शासन और विकास में उत्कृष्टता को मान्यता देता है और यह उन व्यक्तियों, संस्थानों, परियोजनाओं और नवाचारों को दिया जाता है जो प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यह बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और शासन परिणामों में योगदान देने वाली परिवर्तनकारी पहलों पर प्रकाश डालता है।

CBS प्लेटफॉर्म का महत्व

- भू-लक्षित अलर्ट: आपात स्थितियों से प्रभावित विशिष्ट क्षेत्रों में अलर्ट प्रसारित करता है, जिससे प्रासंगिकता बढ़ती है और अनावश्यक घबराहट कम होती है।
- बहुभाषी समर्थन: कई भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संदेश देश भर में विभिन्न भाषाई समूहों द्वारा समझे जाएं।
- नेटवर्क दक्षता: SMS के विपरीत, सेल ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जाम किए बिना एक साथ लाखों लोगों को संदेश भेज सकता है, जो आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण है।
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी: भारत के दूरसंचार R&D केंद्र द्वारा विकसित, महत्वपूर्ण संचार प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करता है।

टायलर पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डॉ. टोबी कियर्स को अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क - खासकर माइकोराइज़ल फंगस - की कार्बन साइक्लिंग, बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम हेल्थ में भूमिका को उजागर करने वाले अपने अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार फॉर एनवायरनमेंटल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। उनके रिसर्च ने यह पता लगाने में मदद की है कि ये नेटवर्क सालाना 13 बिलियन टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सोखते हैं, जो जलवायु नियंत्रण और मिट्टी की इकोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ. कियर्स इस पुरस्कार के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला विजेता हैं, जिसमें US $250,000 का पुरस्कार मिलता है और इसे अक्सर "पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है।

माइकोराइज़ल फंगल नेटवर्क के बारे में

माइकोराइज़े फंगस और पौधों की जड़ों के बीच सिम्बायोटिक संबंध हैं जो पौधों से कार्बन के बदले पोषक तत्वों (जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन) के अवशोषण को बढ़ाते हैं, जिससे पौधों के स्वास्थ्य और मिट्टी के इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क बनते हैं। ये नेटवर्क कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में प्रमुख प्राकृतिक प्रणालियों के रूप में उभर रहे हैं - ग्रीनहाउस गैसों को पकड़ते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। माइकोराइज़ल फंगस मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्व साइक्लिंग और पानी बनाए रखने में योगदान देते हैं, जिससे वे स्थायी कृषि और इकोसिस्टम लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

टायलर पुरस्कार फॉर एनवायरनमेंटल अचीवमेंट

1973 में स्थापित और यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया (USC) द्वारा प्रशासित टायलर पुरस्कार, उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने पर्यावरण विज्ञान और स्थिरता में परिवर्तनकारी योगदान दिया है। अक्सर "पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार" के रूप में वर्णित, यह जेन गुडॉल, माइकल मान और ग्रेटा डेली सहित वैश्विक पर्यावरण नेताओं को प्रदान किया गया है। विजेताओं को वैज्ञानिक उत्कृष्टता, वैश्विक प्रभाव और पर्यावरण संरक्षण और नीति में कार्रवाई योग्य योगदान के लिए चुना जाता है।

सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ

मुख्यमंत्री सेहत योजना

मुख्यमंत्री सेहत योजना क्या है?
- पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना नाम की एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है।
- यह हर परिवार को हर साल ₹10 लाख तक का मुफ्त कैशलेस मेडिकल इलाज देती है।

यह योजना किसने शुरू की?
- यह कार्यक्रम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरू किया।
- आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लॉन्च इवेंट में मौजूद थे।

किसे फायदा होगा?
- पंजाब राज्य के सभी 65 लाख परिवार इसके लिए योग्य हैं।
- इसमें पूरे राज्य के लगभग तीन करोड़ लोग शामिल हैं।
- आधार कार्ड और वोटर ID वाला कोई भी पंजाब निवासी इस योजना में शामिल हो सकता है।

इस योजना में क्या शामिल है?
- यह योजना बीमारियों और चोटों के लिए मुफ्त और कैशलेस अस्पताल इलाज को कवर करती है।
- इसमें 2,500 से ज़्यादा मेडिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं।

मरीज इलाज कहाँ करवा सकते हैं?
- इलाज पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों और पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगा।
- अब तक लगभग 850 अस्पतालों को शामिल किया गया है, और भी जोड़े जाएंगे।

कोई आय सीमा या शर्तें नहीं
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है — राज्य में सभी को कवरेज मिलता है।
- यह इसे भारत के सबसे समावेशी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक बनाता है।

यह क्यों मायने रखता है
- यह नई योजना यह सुनिश्चित करती है कि ज़्यादा मेडिकल बिल परिवारों पर बोझ न बनें।
- इसे पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थकेयर की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- यह मौजूदा क्लीनिकों और सेवाओं को बेहतर बनाकर, बड़े स्वास्थ्य सुधारों से भी जुड़ा है।

पंजाब
- राजधानी: चंडीगढ़
- राज्यपाल: गुलाब चंद कटारिया
- मुख्यमंत्री: भगवंत मान (AAP)
- उच्च न्यायालय: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

REPM योजना

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने उच्च-मूल्य वाले दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकों के लिए भारत का पहला एकीकृत घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए सिंटर्ड दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बकों (REPM) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला में शुरू से अंत तक क्षमताओं का विकास करना है - दुर्लभ-पृथ्वी ऑक्साइड से लेकर तैयार स्थायी चुम्बकों तक - जिससे रणनीतिक सामग्रियों में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। भारत के पास आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल,

झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तटीय समुद्र तट की रेत, लाल रेत और आंतरिक जलोढ़ जमाव में महत्वपूर्ण दुर्लभ-पृथ्वी खनिज भंडार हैं। REPM योजना के तहत, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और विनिर्माण का समर्थन करने के लिए ₹7,000 करोड़ से अधिक का वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस योजना का लक्ष्य सिंटर्ड दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बकों की 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना है, जो इलेक्ट्रिक वाहन (EV), नवीकरणीय ऊर्जा (पवन टर्बाइन), इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा सहित उच्च-विकास और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं। यह पहल भारत की अंतर्राष्ट्रीय खनिज कूटनीति का भी पूरक है, जिसमें खान मंत्रालय ने आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ज़ाम्बिया जैसे खनिज-समृद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग समझौतों में प्रवेश किया है।

दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REEs):
- लैंथेनाइड्स, स्कैंडियम और यट्रियम सहित 17 तत्वों का एक समूह।
- उच्च-प्रदर्शन वाले चुम्बकों, बैटरियों, अर्धचालकों और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक।
- सिंटर्ड REPM (जैसे नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन चुम्बक) उच्च चुंबकीय शक्ति और तापीय स्थिरता प्रदान करते हैं।

LIC की ग्रामीण और सेमी-अर्बन भारत में पहुँच

चर्चा में क्यों?
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (LIC) ने सहज इंश्योरेंस सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है ताकि पूरे ग्रामीण और सेमी-अर्बन भारत में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की पहुंच बढ़ाई जा सके, जहां पारंपरिक रूप से जागरूकता और कवरेज कम रहा है।

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (LIC):
भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरर और एक सरकारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी, जो देश की वित्तीय सुरक्षा संरचना के लिए महत्वपूर्ण है।
- स्थापना: 1 सितंबर 1956
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
- CEO और MD: आर. दोरईस्वामी
- MD: रत्नाकर पटनायक
- MD: दिनेश पंत

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI):
यह एक वैधानिक निकाय है जो इंश्योरेंस कंपनियों और कॉर्पोरेट एजेंटों को रेगुलेट और लाइसेंस देता है, जिससे सही तरीकों और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है।
- गठन: 1999
- मुख्यालय: हैदराबाद
- चेयरपर्सन: अजय सेठ

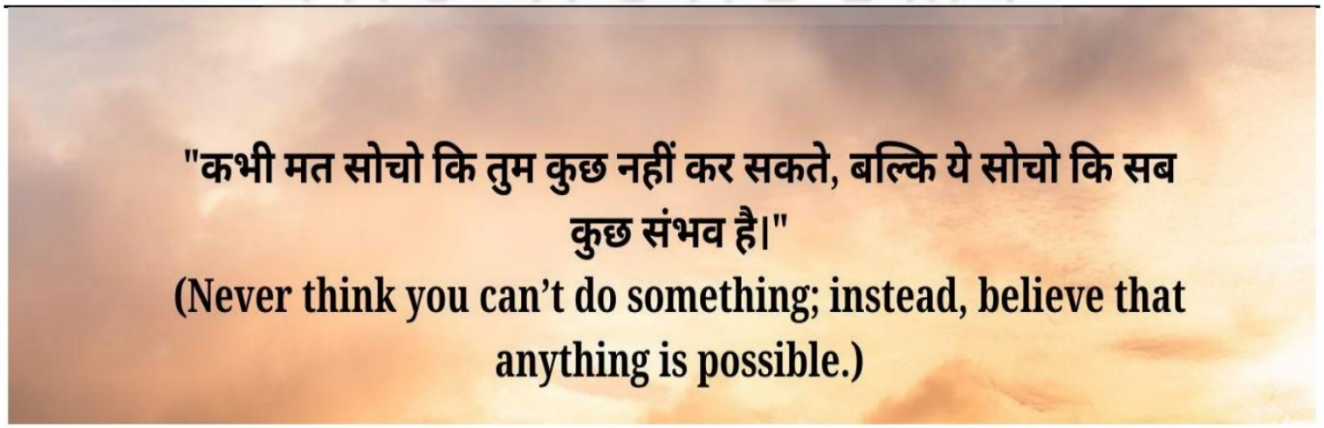

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

PSLV-C62 मिशन

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2026 को, भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C62, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 और भारतीय स्टार्टअप और इंटरनेशनल पार्टनर के 15 को-पैसेंजर सैटेलाइट को लेकर लॉन्च हुआ। ISRO के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल के तौर पर जाने जाने वाले PSLV से एक और सफल मिशन की उम्मीद थी। लेकिन, एक अप्रत्याशित गड़बड़ी ने इस लॉन्च को हाल के सालों में भारत की सबसे ज़्यादा जांच की जाने वाली स्पेस नाकामियों में से एक बना दिया।

मिशन का ओवरव्यू

- लॉन्च की तारीख: 12 जनवरी, 2026
- लॉन्च व्हीकल: PSLV-XL वेरिएंट
- मुख्य पेलोड: EOS-N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट
- को-पैसेंजर: भारत और विदेश के 15 छोटे सैटेलाइट
- टारगेट ऑर्बिट: ~650 km पर सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट
- यह मिशन कमर्शियल स्पेस लॉन्च में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक था, खासकर प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप और ग्लोबल सहयोग को सपोर्ट करने के लिए सरकार के प्रयासों के तहत।

लॉन्च के दौरान क्या गलत हुआ

- लॉन्च के शुरुआती चरण सामान्य रूप से चले।
- पहले और दूसरे स्टेज ने उम्मीद के मुताबिक काम किया।
- पेलोड फेयरिंग सेपरेशन सफल रहा।
- गड़बड़ी तीसरे स्टेज (PS3) के जलने के दौरान हुई।
- ISRO के अनुसार, सॉलिड-फ्यूल तीसरे स्टेज के ऑपरेशन के आखिर में असामान्य रोल रेट और चैंबर प्रेशर में गिरावट का पता चला। इससे रॉकेट के रास्ते में बदलाव हुआ, जिससे चौथे स्टेज का सही इग्निशन नहीं हो पाया और मिशन फेल हो गया।

पेलोड पर असर

- EOS-N1, एक मुख्य अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, खो गया।
- 15 को-पैसेंजर सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाए।
- एक खास बात यह थी कि स्पेन का केस्ट्रेल इनिशियल डेमोंस्ट्रेटर (KID) सैटेलाइट, जो कुछ समय के लिए अलग हुआ और दोबारा एंट्री से पहले लगभग तीन मिनट तक डेटा भेजा, जिससे सिस्टम की आंशिक कार्यक्षमता का पता चला।

PSLV की विफलता क्यों मायने रखती है

- PSLV का सफलता का एक लंबा रिकॉर्ड है, 1993 से अब तक कुछ ही विफलताएँ हुई हैं।
- यह घटना मई 2025 में PSLV-C61 के दौरान इसी तरह की तीसरी स्टेज की समस्या के बाद हुई है, जिससे PS3 स्टेज में संभावित सिस्टम संबंधी समस्याओं पर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- जाँच के तहत संभावित कारणों में शामिल हैं:
- सॉलिड प्रोपेलेंट में मैन्युफैक्चरिंग दोष
- थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल में गड़बड़ी
- क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग में कमियाँ
- ISRO ने टेलीमेट्री, रडार डेटा और सिमुलेशन का उपयोग करके जाँच के लिए एक एनोमली रिज़ॉल्यूशन कमेटी का गठन किया है।

भारत के अंतरिक्ष इकोसिस्टम पर व्यापक प्रभाव

- सैकड़ों करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है, हालाँकि इसका ज़्यादातर बीमा किया गया है।
- अंतरिक्ष-आधारित सत्यापन पर निर्भर भारतीय स्टार्टअप्स के लिए देरी।
- भारत की कमर्शियल लॉन्च विश्वसनीयता पर अल्पकालिक प्रभाव।

- अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों और बीमाकर्ताओं द्वारा बढ़ी हुई जाँच।
- हालाँकि, यह विफलता महत्वपूर्ण डेटा भी प्रदान करती है जो भविष्य के मिशनों को मजबूत कर सकता है और सिस्टम की मजबूती में सुधार कर सकता है।

ISRO के लिए आगे का रास्ता

- बेहतर क्वालिटी जाँच के बाद PSLV-C63 की उम्मीद है।
- ISRO गगनयान, SSLV विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे प्रमुख मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- ऐतिहासिक रूप से, ISRO ने असफलताओं के बाद मजबूत रिकवरी का प्रदर्शन किया है, विफलताओं को सीखने के मील के पत्थर में बदला है।

ऑनलाइन फैल रहे मुख्य साज़िश के दावे
"विदेशी शक्तियों द्वारा जानबूझकर तोड़फोड़"

दावा:

- कुछ यूट्यूबर्स का आरोप है कि दुश्मन देशों ने PSLV-C62 में तोड़फोड़ की ताकि:
- भारत की कमर्शियल लॉन्च की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाया जा सके
- ग्लोबल स्पेस मार्केट में आने वाले भारतीय स्टार्टअप्स को कमज़ोर किया जा सके

हकीकत की जाँच:

- लेयर्ड चेक्स के कारण रॉकेट में तोड़फोड़ करना बहुत मुश्किल है
- साइबर घुसपैठ या फिजिकल छेड़छाड़ का कोई सबूत सामने नहीं आया है
- ISRO के सिस्टम एयर-गैप्ड हैं और उनकी बार-बार जाँच की जाती है
- यह थ्योरी जियोपॉलिटिक्स पर आधारित है लेकिन इसमें टेक्निकल सबूत की कमी है।

"छिपे हुए मिलिट्री पेलोड की थ्योरी"
दावा:

- EOS-N1 को एक क्लासिफाइड मिलिट्री सर्विलांस सैटेलाइट माना जा रहा है, और यह विफलता या तो:
- एक गुप्त टेस्ट को छिपाने के लिए थी
- या डेटा कैप्चर को रोकने के लिए जानबूझकर किया गया विनाश था

हकीकत की जाँच:

- अर्थ-ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट्स आमतौर पर दोहरे नागरिक-सैन्य भूमिका निभाते हैं
- कोई विश्वसनीय सबूत जानबूझकर मिशन को खत्म करने का संकेत नहीं देता है
- एक असफल लॉन्च संपत्ति को नष्ट करता है, रहस्यों की रक्षा नहीं करता है
- यह थ्योरी यह नहीं समझती कि मिलिट्री स्पेस ऑपरेशन असल में कैसे काम करते हैं।

"प्राइवेट स्पेस लॉबी द्वारा तोड़फोड़"
दावा:

- कथित तौर पर ISRO ने विफलता होने दी—या उस पर दबाव डाला गया—ताकि:
- प्राइवेट लॉन्च फर्मों को बढ़ावा दिया जा सके
- भारतीय अंतरिक्ष के तेज़ी से प्राइवेटाइज़ेशन को सही ठहराया जा सके

हकीकत की जाँच:

- ISRO और प्राइवेट फर्म एक-दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं
- PSLV भारी और सटीक पेलोड के लिए ज़रूरी है
- एक विफलता ISRO की मोलभाव करने की शक्ति को कमज़ोर करती है—यह उसकी मदद नहीं करती
- यह टेक्निकल हकीकत से ज़्यादा एक राजनीतिक कहानी है।

"मैन्युफैक्चरिंग में लापरवाही को छिपाना"

दावा:
- कथित तौर पर ISRO छिपा रहा है:
- खराब क्वालिटी कंट्रोल
- आउटसोर्सिंग की विफलताएँ

सप्लाई-चेन में शॉर्टकट
हकीकत की जाँच:
- यह आंशिक रूप से संभव है लेकिन साज़िश नहीं है:
- सॉलिड स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग में खराबी एक जाना-पहचाना जोखिम है
- ISRO ने तीसरे स्टेज में गड़बड़ियों को स्वीकार किया है
- जाँच रिपोर्ट अक्सर देरी से आती हैं, छिपाई नहीं जातीं
- यह एक इंजीनियरिंग समस्या है, कोई गुप्त साज़िश नहीं।

निष्कर्ष
PSLV-C62 की विफलता यह याद दिलाती है कि स्पेसफ्लाइट बहुत कम मार्जिन पर काम करती है। हालाँकि यह झटका बड़ा है, लेकिन इससे भारत की लंबी अवधि की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को पटरी से उतरने की संभावना नहीं है। इसके बजाय, यह पारदर्शिता, कठोर परीक्षण और लगातार सुधार के महत्व को मज़बूत करता है—ये वे सिद्धांत हैं जिन्होंने श्रीहरिकोटा से सितारों तक ISRO की यात्रा को लंबे समय से परिभाषित किया है।

काशिवाज़ाकी-कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट

चर्चा में क्यों?
जापान ने क्षमता के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशन, काशिवाज़ाकी-कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक न्यूक्लियर रिएक्टर को फिर से चालू कर दिया है। रिएक्टर को टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स (TEPCO) ने फिर से चालू किया। यह 2011 के फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर आपदा के बाद TEPCO द्वारा पहला रिएक्टर रीस्टार्ट है। यह प्लांट जापान सागर के तट पर निगाटा प्रीफेक्चर में स्थित है। यह रीस्टार्ट ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन कटौती के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा की ओर जापान के नए प्रयास को दिखाता है।

काशिवाज़ाकी-कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में
- दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में मान्यता प्राप्त।
- इसमें 7 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं।
- कुल स्थापित क्षमता: लगभग 8,200 मेगावाट (8.2 GW)।
- जापान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी TEPCO द्वारा संचालित।
- 2011 की फुकुशिमा आपदा के बाद सुरक्षा और नियामक समीक्षाओं के लिए बंद कर दिया गया था।

पृष्ठभूमि: फुकुशिमा न्यूक्लियर आपदा (2011)
- यह 11 मार्च 2011 को एक बड़े भूकंप और सुनामी के कारण हुआ था।
- इससे फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोर मेल्टडाउन हुआ।
- इसे चेरनोबिल (1986) के बाद सबसे खराब न्यूक्लियर दुर्घटना माना जाता है।
- आपदा के बाद, जापान में सभी न्यूक्लियर रिएक्टरों को सुरक्षा जांच के लिए बंद कर दिया गया था।
- इसके परिणामस्वरूप जापान के न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी (NRA) के तहत सख्त सुरक्षा मानदंड बनाए गए।

रीस्टार्ट क्यों महत्वपूर्ण है
जापान ऊर्जा आयात पर निर्भर है, खासकर जीवाश्म ईंधन पर।
न्यूक्लियर ऊर्जा जापान की मदद करती है:
- ऊर्जा आयात बिल कम करने में
- स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में
- जलवायु परिवर्तन और डीकार्बनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा करने में

- रीस्टार्ट जापान की पावर मिक्स में न्यूक्लियर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना का समर्थन करता है।

सुरक्षा और नियामक पहलू

कड़ी सुरक्षा जांच के बाद रीस्टार्ट को मंजूरी दी गई।

नए सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:

- बढ़ी हुई भूकंप और सुनामी सुरक्षा
- बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली
- मंजूरी में स्थानीय अधिकारियों और नियामकों की सहमति शामिल थी।
- मंजूरी के बावजूद, रीस्टार्ट को स्थानीय विरोध और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं का सामना करना पड़ा है।

जापान की न्यूक्लियर ऊर्जा नीति

- जापान फुकुशिमा के बाद धीरे-धीरे न्यूक्लियर रीस्टार्ट नीति का पालन करता है।
- नए सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद जापान भर में कई रिएक्टरों को फिर से चालू किया गया है।
- न्यूक्लियर ऊर्जा को कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर एक पुल ईंधन के रूप में देखा जाता है। यह कार्बन न्यूट्रैलिटी के जापान के लॉन्ग-टर्म लक्ष्य के साथ मेल खाता है।

आर्टेमिस II मिशन

चर्चा में क्यों?

NASA के आर्टेमिस II मिशन के लिए मेगा मून रॉकेट को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से लगभग 12 घंटे और 4 मील की यात्रा के बाद फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च पैड 39B पर सफलतापूर्वक ले जाया गया है।

- ऐतिहासिक संदर्भ: आर्टेमिस II 50 से ज़्यादा सालों में पहला क्रू वाला चंद्र मिशन है, जो 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद कम पृथ्वी की कक्षा से परे इंसानों की वापसी का प्रतीक है।
- लॉन्च व्हीकल: यह मिशन NASA के स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) द्वारा संचालित है - जो अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से एक है - जिसके ऊपर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए ओरियन अंतरिक्ष यान लगा हुआ है।
- मिशन का प्रकार: आर्टेमिस II एक क्रू वाला चंद्र फ्लाई-अराउंड मिशन है (लैंडिंग नहीं), जिसे इंसानों के साथ जीवन समर्थन, नेविगेशन और गहरे अंतरिक्ष प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- क्रू: इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री होंगे - तीन NASA से और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री - जो अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उद्देश्य: मुख्य उद्देश्यों में गहरे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान प्रणालियों को मान्य करना, लंबे समय तक चलने वाले चंद्र मिशनों पर मानव प्रदर्शन का आकलन करना, और भविष्य में चंद्र सतह पर लैंडिंग और मंगल ग्रह के लिए अंतिम मिशनों का मार्ग प्रशस्त करना शामिल है।
- लॉन्च से पहले की तैयारी: पैड पर पहुंचने के बाद, NASA के इंजीनियर अंतिम लॉन्च अनुक्रम से पहले ईंधन भरने और काउंटडाउन प्रक्रियाओं का अनुकरण करने के लिए एक वेट ड्रेस रिहर्सल और अन्य परीक्षण करेंगे।
- लॉन्च विंडो: यह मिशन वर्तमान में 6 फरवरी, 2026 को लॉन्च के लिए लक्षित है, जिसमें तकनीकी तत्परता और कक्षीय स्थितियों के आधार पर मार्च और अप्रैल 2026 में अतिरिक्त विंडो हैं।

आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में

- आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य: चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना और मंगल ग्रह के मानव अन्वेषण के लिए एक कदम के रूप में काम करना।
- आर्टेमिस I: एक बिना क्रू वाली परीक्षण उड़ान जिसने आर्टेमिस II से पहले SLS और ओरियन प्रणालियों को मान्य किया।
- आर्टेमिस III: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की योजना है और इसमें चंद्रमा पर पहली महिला और अगला पुरुष शामिल होगा।

PARAM रुद्र सुपरकंप्यूटर

चर्चा में क्यों?

भारत में रिसर्च और स्वदेशी हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT बॉम्बे में PARAM रुद्र सुपरकंप्यूटिंग सुविधा (3 पेटाफ्लॉप्स) का उद्घाटन किया गया।

PARAM रुद्र क्या है?
- स्वदेशी हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटर
- 3 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग क्षमता
- प्रति सेकंड 3 क्वाड्रिलियन गणना कर सकता है
- एडवांस्ड वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग रिसर्च को सपोर्ट करता है

स्थान और उद्घाटन
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे में स्थापित
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा विकसित
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव द्वारा उद्घाटन

नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)
- MeitY और DST की संयुक्त पहल
- C-DAC और IISc बेंगलुरु द्वारा लागू
- उद्देश्य: स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग क्षमता विकसित करना
- भारत के हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना

स्वदेशी प्रौद्योगिकी और मेक इन इंडिया
- स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए रुद्र सर्वर का उपयोग करके बनाया गया
- भारतीय सॉफ्टवेयर स्टैक का उपयोग करता है
- आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है
- विदेशी सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम पर निर्भरता कम करता है

एडवांस्ड तकनीकी विशेषताएं
- डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग (DCLC) तकनीक का उपयोग करता है
- ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है
- लगातार हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में सुधार करता है

भारत की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता
- PARAM रुद्र NSM के तहत 38 सुपरकंप्यूटर का हिस्सा है
- NSM के तहत कुल स्थापित क्षमता: 44 पेटाफ्लॉप्स
- भारत की वैश्विक HPC उपस्थिति को मजबूत करता है

NSM के चार स्तंभ
1. सुपरकंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
2. एप्लीकेशन डेवलपमेंट
3. रिसर्च और डेवलपमेंट
4. मानव संसाधन विकास

अतिरिक्त तथ्य
- 1 पेटाफ्लॉप = 10^{15} गणना प्रति सेकंड
- सुपरकंप्यूटर का उपयोग इसके लिए किया जाता है:
- मौसम और जलवायु पूर्वानुमान
- दवा की खोज और जीनोमिक्स
- अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान
- भारत एक्सस्केल कंप्यूटिंग क्षमता की ओर बढ़ रहा है

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 2025 में बड़ी उपलब्धियों और 2026 के लिए प्लान किए गए एक ऐतिहासिक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है।

मानव अंतरिक्ष उड़ान में विकास

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) का दौरा करने वाले पहले भारतीय बने। यह राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की वापसी का प्रतीक है। इस मिशन ने लंबे समय तक चलने वाले मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए भारत की तैयारी को मजबूत किया। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने माइक्रोग्रैविटी प्रयोग किए, जिससे अंतरिक्ष चिकित्सा और सामग्री विज्ञान अनुसंधान में योगदान मिला।

2025 में प्रमुख अंतरिक्ष उपलब्धियाँ

भारत ने सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे यह इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया। ISRO ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से अपना 100वां लॉन्च पूरा किया। नई पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट के लॉन्च से भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम को बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार ने उच्च लॉन्च फ्रीक्वेंसी और भविष्य के मानव मिशनों को सपोर्ट करने के लिए श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी। भारत का प्राइवेट अंतरिक्ष क्षेत्र बढ़ा, जिसमें स्टार्टअप्स ने पृथ्वी-अवलोकन और अंतरिक्ष-स्थितिजन्य जागरूकता सैटेलाइट लॉन्च किए।

गगनयान मिशन – 2026 पर फोकस

गगनयान भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। पहला बिना क्रू वाला गगनयान मिशन (G1) क्रू वाले मिशनों के लिए एक तैयारी के तौर पर प्लान किया गया है।

मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- क्रू मॉड्यूल, री-एंट्री सिस्टम और पैराशूट-आधारित रिकवरी का परीक्षण।
- अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन-समर्थन और सुरक्षा प्रणालियों का सत्यापन
- गगनयान भारत को स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्षम देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल करेगा।

नीति और बजटीय सहायता

अंतरिक्ष क्षेत्र को R&D और स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट में बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन मिला। प्रमुख अंतरिक्ष घटकों पर सीमा शुल्क छूट का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। नीति सुधार निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे भारत एक वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।

रणनीतिक और वैज्ञानिक महत्व

मानव अंतरिक्ष उड़ान राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाती है। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है:

- स्पेस स्टेशन
- ऑन-ऑर्बिट सर्विसिंग
- डीप-स्पेस मिशन

भारत की स्पेस इकोनॉमी के तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें ग्लोबल मार्केट शेयर भी बढ़ेगा।
सोलर ऑब्ज़र्वेटरी जैसे मिशन से मिले डेटा से स्पेस-बेस्ड क्लाइमेट और स्पेस-वेदर रिसर्च में भारत की भूमिका मज़बूत होती है।

समाचार संक्षिप्त में

म्पेंबा इफ़ेक्ट

चर्चा में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने पहला सुपरकंप्यूटर-पावर्ड सिमुलेशन विकसित किया है जो म्पेंबा इफ़ेक्ट को सफलतापूर्वक समझने में मदद करता है — यह एक ऐसा अजीबोगरीब घटना है जिसमें कुछ खास परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जम सकता है। जर्नल ऑफ़ कम्युनिकेशन फिजिक्स में प्रकाशित यह शोध यह भी दिखाता है कि म्पेंबा इफ़ेक्ट पानी के अलावा अन्य सिस्टम में भी तरल से ठोस चरण परिवर्तन के दौरान हो सकता है। ये निष्कर्ष यह समझाने में मदद करते हैं कि जब कोई तरल ठंडा होता है, तो वह असल में जमने से पहले बीच की आणविक अवस्थाओं से गुज़र सकता है, और कुछ मामलों में, उच्च शुरुआती तापमान प्रमुख न्यूक्लिएशन चरणों तक जल्दी पहुँचकर तेज़ी से जमने का कारण बन सकते हैं।

म्पेंबा इफ़ेक्ट क्या है?

म्पेंबा इफ़ेक्ट उस अवलोकन को संदर्भित करता है कि गर्म तरल पदार्थ (पानी सहित) कभी-कभी समान परिस्थितियों में ठंडे तरल पदार्थों की तुलना में तेज़ी से जम सकते हैं — यह एक लंबे समय से चला आ रहा वैज्ञानिक विरोधाभास है जिसने शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। इसका नाम एरास्टो म्पेंबा के नाम पर रखा गया है, जो तंजानिया के एक छात्र थे जिन्होंने 1960 के दशक में आइसक्रीम बनाते समय इस प्रभाव को देखा था; उनके अवलोकन को बाद में डेनिस ओसबोर्न सहित वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगात्मक रूप से मान्य किया गया था। म्पेंबा इफ़ेक्ट पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक कार्य में गैर-संतुलन भौतिकी, द्रव गतिशीलता और चरण परिवर्तन घटनाएँ शामिल हैं, जिसका व्यापक रूप से थर्मल प्रक्रियाओं को समझने पर प्रभाव पड़ता है।

PathGennie सॉफ्टवेयर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने PathGennie नाम का एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो संभावित दवा मॉलिक्यूल्स के अपने प्रोटीन टारगेट से अलग होने का सटीक अनुमान लगाकर ड्रग डिस्कवरी में तेज़ी लाता है। PathGennie आर्टिफिशियल फोर्स से बचकर पारंपरिक कम्प्यूटेशनल तरीकों की सीमाओं को पार करता है, जिससे ड्रग-टारगेट इंटरैक्शन में दुर्लभ घटनाओं का ज़्यादा भरोसेमंद सिमुलेशन संभव होता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर-एडेड ड्रग डिस्कवरी को तेज़ कर सकता है और दवा के "रेजिडेंस टाइम" की समझ को बेहतर बना सकता है, जो थेराप्यूटिक प्रभावशीलता के लिए बहुत ज़रूरी है।

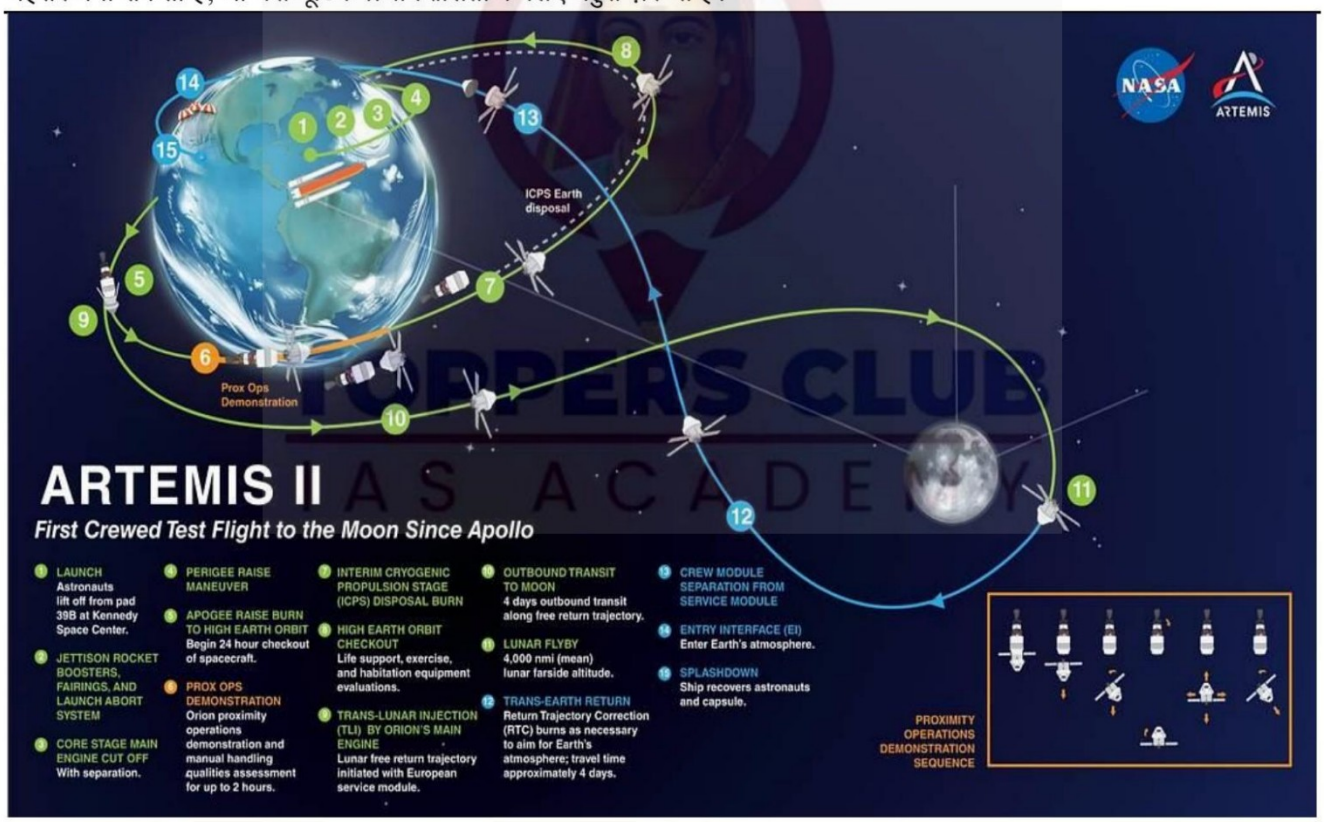

संस्कृति एवं इतिहास

महाराष्ट्र में पुरातात्विक खोज

चर्चा में क्यों?
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामणि घास के मैदानों में भारत का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूलभुलैया मिला है, जो दक्कन में शुरुआती ऐतिहासिक काल के दौरान उन्नत स्थानिक डिजाइन और संभावित सांस्कृतिक-व्यापार संबंधों को उजागर करता है।

स्थान और खोज
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक अर्ध-शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र, बोरामणि घास के मैदानों में खोजा गया। संरचना की पहचान पारिस्थितिक सर्वेक्षणों के दौरान की गई थी, जो पर्यावरण संरक्षण और पुरातात्विक खोजों के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। ये घास के मैदान समृद्ध जैव विविधता और पशुपालन गतिविधि के लिए जाने जाते हैं।

संरचनात्मक विशेषताएं
यह भूलभुलैया भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा है। इसका माप लगभग 50 फीट × 50 फीट है। यह 15 संकेंद्रित गोलाकार पत्थर के सर्किट से बना है जो एक केंद्रीय बिंदु की ओर ले जाते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है, जो स्वदेशी इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। गोलाकार और सर्पिल ज्यामिति उन्नत योजना और प्रतीकात्मक वास्तुकला को दर्शाती है।

ऐतिहासिक संदर्भ
इस संरचना की उम्र लगभग 2,000 साल पुरानी होने का अनुमान है। यह सातवाहन काल (पहली-तीसरी शताब्दी ईस्वी) से जुड़ा है, जो दक्कन का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। सातवाहनों ने आंतरिक भारत को पश्चिमी तटीय व्यापार मार्गों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व
भूलभुलैया के पैटर्न भूमध्यसागरीय दुनिया में पाए जाने वाले रूपांकनों से मिलते-जुलते हैं, जो भारत-रोमन सांस्कृतिक आदान-प्रदान का सुझाव देते हैं।

इसका कार्य हो सकता है:
- एक अनुष्ठान या औपचारिक संरचना के रूप में
- एक नेविगेशनल या रास्ता खोजने वाले मार्कर के रूप में
- प्राचीन व्यापार मार्गों के साथ एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर के रूप में
- यह केवल भौतिक व्यापार से परे विचारों के आदान-प्रदान को दर्शाता है।

पुरातात्विक महत्व
यह प्राचीन भारत की गैर-शहरी और गैर-धार्मिक स्थापत्य परंपराओं पर प्रकाश डालता है। यह दिखाता है कि शहरों और मंदिरों से परे भी जटिल प्रतीकात्मक संरचनाएं मौजूद थीं। यह दक्कन क्षेत्र में परिदृश्य-आधारित पुरातत्व की समझ को बढ़ाता है।

संरक्षण महत्व
यह एक घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्थित है, जो एकीकृत विरासत और पारिस्थितिक संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। यह संरक्षित स्मारकों के बाहर पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह दर्शाता है कि विकास, जैव विविधता और विरासत को एक साथ कैसे प्रबंधित किया जाना चाहिए।

सातवाहन राजवंश:
व्यापार, प्राकृत भाषा और शुरुआती बौद्ध प्रतिष्ठानों को बढ़ावा दिया। उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एक सेतु का काम किया।
भारत-रोमन व्यापार:
पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच फला-फूला। इसमें मसाले, वस्त्र, मोती और कीमती पत्थर शामिल थे।
भूलभुलैया प्रतीकवाद:

कई प्राचीन संस्कृतियों में यात्रा, सुरक्षा, ब्रह्मांड विज्ञान और अनुष्ठानिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय परंपरा में चक्रव्यूह जैसी अवधारणाओं के जैसा।

वंदे मातरम के 150 साल

चर्चा में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में, वह भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा और स्थायी महत्व को मनाने के लिए "वंदे मातरम के 150 साल" विषय पर एक झांकी प्रस्तुत करेगा। यह झांकी प्रतीकात्मक रूप से वंदे मातरम की ऐतिहासिक उत्पत्ति, सांस्कृतिक गूंज और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को दर्शाएगी, जिसमें गीत को भारत की सभ्यतागत स्मृति और सामूहिक चेतना की एक जीवित अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाएगा।

वंदे मातरम – ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंदमठ में की थी और यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे संक्षिप्त रूप में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम का विषय मातृभूमि के प्रति भक्ति की भावना जगाता है, जो भारत को एक दिव्य और पालन-पोषण करने वाली इकाई के रूप में व्यक्त करता है।

गणतंत्र दिवस 2026 का विषय

गणतंत्र दिवस परेड 2026 का मुख्य विषय "वंदे मातरम के 150 साल" है, जो इस कथा को कर्तव्य पथ पर झांकियों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों, बैंड मार्च और सजावटी तत्वों में एकीकृत करता है।

संस्कृति मंत्रालय की झांकी के साथ-साथ, अन्य झांकियां और प्रदर्शन "स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम" और "समृद्धि का मंत्र – आत्मनिर्भर भारत" जैसे उप-विषयों को उजागर करते हैं।

गणतंत्र दिवस परेड – अवलोकन

गणतंत्र दिवस परेड हर साल 26 जनवरी को नई दिल्ली में भारत के संविधान (1950) को अपनाने का जश्न मनाने के लिए आयोजित की जाती है। इस कार्यक्रम में सैन्य टुकड़ियां, सांस्कृतिक झांकियां, मार्चिंग बैंड, सम्मानित मुख्य अतिथि और पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार जैसे पुरस्कार वितरण शामिल होते हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और उपलब्धियों को प्रदर्शित करती हैं।

IGNCA और सांस्कृतिक प्रस्तुति की भूमिका

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) संस्कृति मंत्रालय को गणतंत्र दिवस की झांकियों की अवधारणा और निष्पादन में सहायता करता है जो दार्शनिक और ऐतिहासिक विषयों को दर्शाती हैं। झांकी की कहानी अक्सर इतिहास को आज की वैल्यूज़ से जोड़ती है, और विज़ुअल कहानी के ज़रिए राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करती है।

2026 परेड के लिए खास सांस्कृतिक तत्व

विज़ुअल्स के अलावा, वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के लिए नए म्यूज़िकल कंपोज़िशन जैसे खास एलिमेंट्स शामिल किए जा रहे हैं - उदाहरण के लिए, ऑस्कर विजेता कंपोज़र एम.एम. कीरावनी का एक नया वर्ज़न जिसे सेलिब्रेशन के दौरान दिखाया जाएगा। थीम से जुड़े परफॉर्मेंस में सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री यूनिट्स द्वारा पूरे भारत में बैंड मार्च शामिल हैं।

गणतंत्र दिवस पर SVAMITVA योजना

चर्चा में क्यों?

77वें गणतंत्र दिवस परेड में पंचायती राज मंत्रालय की झांकी में SVAMITVA योजना को दिखाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण संपत्ति के मालिकाना हक, बेहतर पंचायती राज संस्थाओं, क्रेडिट तक पहुंच और मजबूत विवाद समाधान पर जोर दिया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत में योगदान मिलेगा।

मुख्य बातें:

- योजना का नाम: SVAMITVA (गांवों का सर्वे और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ मैपिंग)।

- लॉन्च किया गया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2020 में।
- उद्देश्य: ड्रोन-आधारित सर्वे का उपयोग करके प्रॉपर्टी कार्ड जारी करके ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना।

दिखाया गया प्रभाव:
- सुरक्षित आवास और मालिकाना हक।
- संपत्ति को एक एसेट के रूप में उपयोग करके बैंक लोन/क्रेडिट तक आसान पहुंच।
- आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से संपत्ति विवादों में कमी।
- बेहतर शासन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना।
- गणतंत्र दिवस परेड से प्रासंगिकता: यह योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव को दिखाता है और आत्मनिर्भर भारत के बड़े विचार के तहत आत्मनिर्भर गांवों की थीम का समर्थन करता है।

अतिरिक्त तथ्य:
- SVAMITVA के तहत, ड्रोन सर्वे बसे हुए गांवों का डिजिटल नक्शा तैयार करने में मदद करते हैं।
- योजना के तहत जारी किए गए प्रॉपर्टी कार्ड बेहतर पारदर्शिता के लिए सरकार के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड हैं।

भारत की सांस्कृतिक भावना और WAVES विज़न

चर्चा में क्यों?
गणतंत्र दिवस परेड में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी में भारत की सांस्कृतिक भावना और WAVES के विज़न के अनुरूप "भारत गाथा: श्रुति, कृति, दृष्टि" थीम के तहत प्राचीन मौखिक कथाओं से लेकर आधुनिक मीडिया तक भारत की कहानी कहने की विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:
- झांकी का शीर्षक: "भारत गाथा: श्रुति, कृति, दृष्टि।"
- मंत्रालय: सूचना एवं प्रसारण (I&B)।
- थीम की व्याख्या:
- श्रुति: भारत की समृद्ध मौखिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है (जैसे, ऋषि और शिष्य, वैदिक मंत्रोच्चार)।
- कृति: लिखित अभिव्यक्ति के विकास को दर्शाती है (जैसे, पांडुलिपियां, प्रारंभिक साहित्य)।
- दृष्टि: दृश्य और जनसंचार माध्यमों की प्रगति को दिखाती है - प्रिंट, सिनेमा, टेलीविजन, डिजिटल युग।
- WAVES का विज़न: ऑडियो-विजुअल और मनोरंजन सामग्री के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने पर प्रकाश डालता है।

अतिरिक्त तथ्य:
- झांकी में विंटेज टीवी सेट (दूरदर्शन लोगो), फिल्म रील, फिल्म मार्की साइन और AI और आधुनिक मीडिया के संदर्भ जैसे तत्व शामिल हैं।
- वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) 2025 में मुंबई में आयोजित किया गया था, जो भारत की बढ़ती रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रतीक है।
- गणतंत्र दिवस की झांकियां अक्सर सांस्कृतिक विरासत, तकनीकी प्रगति और सरकार की नीतिगत उपलब्धियों को दर्शाती हैं।

गणतंत्र दिवस परेड पर प्रासंगिक तथ्य:
- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख (1950) का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है।
- परेड नई दिल्ली में कर्तव्य पथ (पहले राजपथ) पर आयोजित की जाती है।
- राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां भारत की विविधता, संस्कृति, नवाचार और विकासात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करती हैं।
- 2026 के लिए थीम: 'स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम' (राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष) और 'समृद्धि का मंत्र: आत्मनिर्भर भारत'।

समाचार संक्षिप्त में

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

मोज़ाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल को 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार क्या है?

- यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है।
- यह पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण, विकास और सामाजिक कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देता है।

ग्राका माचेल को क्यों चुना गया?

- ग्राका माचेल को उनके जीवन भर के योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला:
- शिक्षा और स्कूलों तक पहुंच में सुधार।
- स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम।
- महिलाओं और समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
- कठिन परिस्थितियों में मानवीय कार्य।

उनका काम और प्रभाव

- माचेल ने मानवाधिकारों की रक्षा करने और कमजोर समूहों की मदद करने में दशकों बिताए हैं।
- उन्होंने 2010 में महिलाओं के सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा और सुशासन का समर्थन करने के लिए ग्राका माचेल ट्रस्ट की स्थापना की।
- वह बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहलों की अध्यक्षता भी करती हैं।

11वां अजंता-एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

चर्चा में क्यों?

मशहूर भारतीय संगीतकार इलैयाराजा को 11वें अजंता-एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (AIFF) 2026 में प्रतिष्ठित पद्मपाणि पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार पांच दशकों से अधिक समय तक भारतीय सिनेमा संगीत में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है।

पद्मपाणि पुरस्कार के बारे में

पद्मपाणि पुरस्कार सिनेमा और संबंधित कलाओं में प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जाने वाला आजीवन उपलब्धि सम्मान है। पुरस्कार में एक पद्मपाणि स्मृति चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र और ₹2 लाख का नकद पुरस्कार शामिल है। चयन प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें फिल्म समीक्षक और फिल्म निर्माता शामिल हैं। पिछले प्राप्तकर्ताओं में गीतकार जावेद अख्तर, निर्देशक साई परांजपे और अभिनेता ओम पुरी जैसी प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं।

इलैयाराजा कौन हैं?

- पूरा नाम: इलैयाराजा भारत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक हैं, जिन्हें अक्सर "इसाईज्ञानी" (संगीत ऋषि) कहा जाता है।
- नागरिक सम्मान: उन्हें 2010 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण मिला, जो क्रमशः भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं।
- संसदीय भूमिका: 2022 में, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा (संसद के ऊपरी सदन) के लिए नामित किया गया था।
- राष्ट्रीय पुरस्कार: उन्होंने फिल्म संगीत में अपने योगदान के लिए पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (तीन सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए और दो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत के लिए) जीते हैं।
- संगीत रचनाएँ: इलैयाराजा ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और मराठी सहित कई भारतीय भाषाओं में 1,500 से अधिक फिल्मों और 7,000 से अधिक गानों के लिए संगीत तैयार किया है।

अजंता-एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (AIFF) के बारे में

AIFF एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है जो भारत और दुनिया भर से सिनेमाई उत्कृष्टता का जश्न मनाता है, जिसमें फिल्म स्क्रीनिंग, चर्चा और पुरस्कार शामिल हैं। महाराष्ट्र में UNESCO-वर्ल्ड हेरिटेज अजंता और एलोरा गुफाओं के नाम पर रखे गए इस फेस्टिवल में ग्लोबल सिनेमा कहानियों के ज़रिए संस्कृति, इतिहास और कला को दिखाया जाता है। इसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मामलों के विभाग का सपोर्ट मिला है, और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NFDC) जैसी संस्थाओं ने इसे मिलकर पेश किया है।

भारत में पद्म पुरस्कार

हर साल, भारत सरकार उन लोगों को पद्म पुरस्कार देती है जिनके काम ने समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला है। 1954 में शुरू किए गए ये नागरिक सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, समाज सेवा, खेल और अन्य कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को पहचान देते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के आसपास की जाती है और भारत के राष्ट्रपति एक समारोह में इन्हें प्रदान करते हैं, जो देश और मानवता की सेवा करने वालों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है।

पद्म पुरस्कार क्यों मायने रखते हैं

उत्कृष्टता की राष्ट्रीय पहचान

पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं, जो भारत रत्न के बाद आते हैं। ये उन असाधारण योगदानों की राष्ट्रीय पहचान हैं जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को समृद्ध किया है। पुरस्कार पाने वालों की प्रशंसा न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए की जाती है, बल्कि उस प्रेरणा के लिए भी की जाती है जो वे आने वाली पीढ़ियों को देते हैं।

विविध योगदानों को प्रोत्साहित करना

ये पुरस्कार भारत की विविधता को दर्शाते हैं, जिसमें सिनेमा के दिग्गजों और खेल हस्तियों से लेकर जमीनी स्तर के समाज सेवकों और वैज्ञानिकों तक, जिनके काम से लोगों का जीवन बदलता है, सभी को सम्मानित किया जाता है। इतने विविध क्षेत्रों में पहचान इस बात पर जोर देती है कि उत्कृष्टता किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है और हर योगदान मायने रखता है।

सेवा और नवाचार को बढ़ावा देना

पद्म पुरस्कार स्वार्थ से परे सेवा के महत्व को उजागर करते हैं और नागरिकों को ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे समाज को फायदा हो। चाहे स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना हो, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना हो, या वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना हो, पुरस्कार विजेता राष्ट्रीय प्रगति और वैश्विक भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं।

पद्म पुरस्कार 2026: उपलब्धियों का जश्न

गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर, भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री सम्मान शामिल हैं।

पद्म विभूषण (2026 की श्रेणी)

पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

- धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) – प्रतिष्ठित अभिनेता जिनकी विरासत ने भारतीय सिनेमा को आकार दिया।
- के टी थॉमस – प्रख्यात न्यायविद।
- एन राजम – प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार।
- पी नारायणन – साहित्य और शिक्षा के विद्वान।
- वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत) – अनुभवी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक।

पद्म भूषण सम्मान पाने वाले

उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित:

- अलका याग्निक (संगीत)
- भगत सिंह कोश्यारी (सार्वजनिक मामले)
- ममूटी (सिनेमा)
- उदय कोटक (व्यवसाय)
- विजय अमृतराज (खेल) और अन्य।

पद्म श्री सम्मान

पद्म श्री सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। इस साल की सूची में डॉक्टर, कलाकार, वैज्ञानिक, संस्कृति संरक्षक और "अनजाने नायक" शामिल हैं, जैसे:

- अंके गौड़ा – दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित की।
- अर्मिडा फर्नांडीज – बाल रोग विशेषज्ञ और नवजात शिशु देखभाल में इनोवेटर।
- नीलेश मंडलेवाला – अंग दान के समर्थक।
- भिकल्या लाडकिया धिंडा – पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित करने वाले आदिवासी संगीतकार।

निष्कर्ष

पद्म पुरस्कार उत्कृष्टता की एक मिसाल बने हुए हैं, जो भारत को उन व्यक्तियों के सम्मान में एकजुट करते हैं जिनका काम समुदायों को ऊपर उठाता है, संस्कृति को संरक्षित करता है, और मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है। 2026 की सूची में दिग्गज और जमीनी स्तर के बदलाव लाने वाले लोग एक साथ आए हैं, जो देश को याद दिलाते हैं कि सेवा और रचनात्मकता का हर कार्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को गहरा करता है।

चर्चित व्यक्तित्व

नियुक्तियाँ

क्र. नं.	व्यक्ति का नाम	के लिए नियुक्त/पद	विभाग/संगठन	संक्षिप्त विवरण
1	**प्रवीण वशिष्ठ**	सतर्कता आयुक्त	केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)	30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी; इससे पहले गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) के रूप में कार्य किया है।
2	**शाया मोहसिन जिंदानी**	प्रधानमंत्री	यमन की सरकार	सलेम बिन ब्रीक के इस्तीफे के बाद पूर्व विदेश मंत्री बने प्रधानमंत्री एक नया मंत्रिमंडल बनाने का काम सौंपा गया है।
3	**ए.के. बालासुब्रमण्यन**	अध्यक्ष	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी)	लगभग 40 वर्षों के अनुभव के साथ अनुभवी परमाणु इंजीनियर; उन्होंने डॉ. डी. के. शुक्ला का स्थान लिया।
4	**इडा लियू**	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	एचएसबीसी प्राइवेट बैंक	सिटी प्राइवेट बैंक के पूर्व वैश्विक प्रमुख; वैश्विक धन और निजी बैंकिंग विकास को चलाने के लिए नियुक्त किया गया।
5	**सदानंद वसंत दाते**	पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)	महाराष्ट्र पुलिस	1990 बैच के आईपीएस अधिकारी; रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में स्थान लिया।
6	**डेल्सी रोड्रिगेज**	अंतरिम राष्ट्रपति	वेनेजुएला की सरकार	राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जबरन अनुपस्थिति के बाद प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया।
7	**न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुश्ताक**	मुख्य न्यायाधीश	सिक्किम उच्च न्यायालय	केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्त किया गया।
8	**शोर्ड मारिन**	मुख्य कोच	भारतीय महिला हॉकी टीम	टीम के पूर्व कोच; टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को चौथे स्थान पर पहुंचाया।
9	**एयर मार्शल नागेश कपूर**	वायु सेना के उप प्रमुख	भारतीय वायु सेना	वरिष्ठ भारतीय वायुसेना अधिकारी; वायु सेना प्रमुख की सहायता करने वाला दूसरा सर्वोच्च पद।
10	**लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह**	प्रबंध निदेशक	सीमा सड़क संगठन (BRO)	रक्षा मंत्रालय के तहत रणनीतिक सीमा बुनियादी ढांचे के विकास का नेतृत्व करता है।
11	**न्यायमूर्ति सौमेन सेन**	मुख्य न्यायाधीश	केरल उच्च न्यायालय	कॉलेजियम की सिफारिश के बाद मेघालय उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया।
12	**न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू**	मुख्य न्यायाधीश	पटना उच्च न्यायालय	उड़ीसा उच्च न्यायालय के वरिष् ठ न् यायाधीश को पटना उच् च न् यायालय का मुख् य न् यायाधीश नियुक् त किया गया।
13	**न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहिते डेरे**	मुख्य न्यायाधीश	मेघालय उच्च न्यायालय	बॉम्बे हाईकोर्ट के जज को मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
14	**बी. साईराम**	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	कोल इंडिया लिमिटेड	कोल इंडिया के पहले सीईओ; अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

क्र. नं.	व्यक्ति का नाम	के लिए नियुक्त/पद	विभाग/संगठन	संक्षिप्त विवरण
15	**सलीम अहमद**	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न पीएसयू का कार्यभार संभाला; बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अनुभवी।
16	**अल्बिंदर ढींढसा**	समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अनन्त समूह	ब्लिंकिट के संस्थापक; दीपिंदर गोयल के इस्तीफे के बाद सीईओ नियुक्त किया गया।
17	**सुनीता विलियम्स**	सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री	नासा	नासा में 27 साल के साथ अनुभवी अंतरिक्ष यात्री; रिकॉर्ड स्पेसवॉक और आईएसएस मिशन के लिए जाना जाता है।

निधन

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र से संबंधित	संक्षिप्त विवरण
1	**वैलेंटिनो गारवानी**	फैशन और डिजाइन	प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिजाइनर जो लक्जरी कॉउचर और प्रतिष्ठित "वैलेंटिनो रेड" के लिए जाने जाते हैं; वैलेंटिनो फैशन हाउस के संस्थापक।
2	**प्रोले चाकी**	संगीत और राजनीति	अनुभवी बांग्लादेशी गायक और वरिष्ठ अवामी लीग नेता; बंगाली संगीत और सांस्कृतिक सक्रियता में योगदान के लिए जाना जाता है।
3	**दविंदर सिंह गरचा**	खेल (हॉकी)	पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी; 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य।
4	**माधव गाडगिल**	पर्यावरण और पारिस्थितिकी	प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिकीविद्; आईआईएससी के सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज के संस्थापक और वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष।
5	**कबिंदर पुरकायस्थ**	राजनीतिशास्त्र	पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता; असम और पूर्वोत्तर में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण व्यक्ति।
6	**सुरेश कलमाड़ी**	राजनीति एवं खेल प्रशासन	पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ के लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष; अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी में एक प्रमुख भूमिका निभाई।
7	**मनोज कोठारी**	खेल (बिलियर्ड्स)	पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन; आईबीएसएफ विश्व चैंपियन और भारत की राष्ट्रीय बिलियर्ड्स टीम के मुख्य कोच।
8	**खालिदा जिया**	राजनीतिशास्त्र	बांग्लादेश के पूर्व प्रधान मंत्री और बीएनपी अध्यक्ष; देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और प्रमुख लोकतांत्रिक नेता।
9	**ब्रिगिट बार्डोट**	सिनेमा और सक्रियता	प्रतिष्ठित फ्रांसीसी अभिनेता और गायक; बाद में एक वैश्विक पशु अधिकार कार्यकर्ता और ब्रिगिट बार्डोट फाउंडेशन के संस्थापक बन गए।
10	**ह्यूग मॉरिस**	खेल (क्रिकेट)	इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

खेल-कूद

स्कॉटलैंड ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह लेगा

स्कॉटलैंड T20 विश्व कप 2026 में खेलेगा

- स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आगामी ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह लेने वाली है।
- यह बदलाव टूर्नामेंट से ठीक पहले हुआ है, जो 7 फरवरी, 2026 को भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में शुरू होगा।

बांग्लादेश को क्यों बदला जा रहा है

- बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा चिंताओं के कारण विश्व कप मैचों के लिए भारत न जाने पर ज़ोर दिया।
- हालांकि बांग्लादेश ने अपने मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया था, लेकिन ICC ने पुष्टि की कि यह इवेंट योजना के अनुसार भारत में ही होगा।
- ICC ने बांग्लादेश को खेलने का फैसला करने के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी थी, लेकिन BCB अपने रुख पर अड़ा रहा।

स्कॉटलैंड को क्यों चुना गया

- स्कॉटलैंड टूर्नामेंट के लिए पहले से क्वालिफाई न करने वाली सबसे ज़्यादा रैंक वाली टीम है।
- इस वजह से और अचानक जगह खाली होने के कारण, ICC ने विश्व कप ग्रुप C में बांग्लादेश की जगह लेने के लिए स्कॉटलैंड को चुना है।

भारत की बैडमिंटन आइकन साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट की पुष्टि की

दिग्गज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने खेल में लगभग दो दशकों के बाद, घुटने की पुरानी चोट और शारीरिक सीमाओं का हवाला देते हुए, प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से आधिकारिक तौर पर रिटायरमेंट की पुष्टि की है।

करियर की उपलब्धियां

- भारत के लिए बैडमिंटन में पहली ओलंपिक मेडलिस्ट: साइना ने 2012 लंदन ओलंपिक में महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता, जो बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक पदक था।
- वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग: वह दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनीं, बैडमिंटन में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला।

अंतर्राष्ट्रीय पदक और खिताब:

- विश्व चैंपियनशिप: महिला सिंगल्स में रजत (2015) और कांस्य (2017)।
- राष्ट्रमंडल खेल: कई स्वर्ण पदक (2010 दिल्ली, 2018 गोल्ड कोस्ट)।
- उबर कप: भारत को ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाए।
- 10 BWF सुपर सीरीज खिताब सहित 24 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते।

अतिरिक्त तथ्य:

- जन्मस्थान और प्रारंभिक जीवन: 17 मार्च 1990 को हिसार, हरियाणा में जन्मी साइना ने कम उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और फिर हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षण लिया।
- पुरस्कार और सम्मान: साइना नेहवाल को भारतीय खेलों में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण (2016), पद्म श्री (2010), अर्जुन पुरस्कार (2009) और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (2010) जैसे शीर्ष राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है।
- अंतिम प्रतिस्पर्धी उपस्थिति: उनका अंतिम पेशेवर टूर्नामेंट 2023 सिंगापुर ओपन था, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट की सार्वजनिक पुष्टि से काफी पहले ही अनौपचारिक रूप से खेलना बंद कर दिया था।

BCCI ने IPL 2026 से पहले Google के Gemini के साथ ₹270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील पक्की की

बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न से पहले Google के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म Gemini के साथ ₹270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप की है। यह डील तीन साल के एग्रीमेंट के तौर पर की गई है, जिसमें IPL सीज़न 2026, 2027 और 2028 शामिल हैं। यह पार्टनरशिप भारतीय स्पोर्ट्स मार्केटिंग, खासकर क्रिकेट - जो भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है - में टेक्नोलॉजी और AI प्लेटफ़ॉर्म की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है। यह स्पॉन्सरशिप IPL के कमर्शियल माहौल में बदलाव के बड़े संदर्भ में आई है, जब सरकार ने रियल-मनी गेमिंग के विज्ञापनों पर बैन लगा दिया था, जिससे बड़े फ़ैंटेसी गेमिंग स्पॉन्सर बाहर हो गए और नई कैटेगरी के स्पॉन्सर को आने का मौका मिला।

रेगुलेटरी बैकग्राउंड

हाल के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत रियल-मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के विज्ञापनों पर सरकारी बैन ने भारतीय खेल में पारंपरिक स्पॉन्सरशिप को प्रभावित किया, जिससे टेक फ़र्म सहित नई स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों पैदा हुए। **BCCI और कमर्शियल रेवेन्यू**

- BCCI मीडिया राइट्स (ब्रॉडकास्ट और डिजिटल), टीम स्पॉन्सरशिप, फ्रेंचाइजी फीस, मर्चेंडाइजिंग और इवेंट होस्टिंग के ज़रिए रेवेन्यू कमाता है।
- जेमिनी डील जैसी स्ट्रेटेजिक कमर्शियल पार्टनरशिप स्पॉन्सरशिप डायनामिक्स में बदलाव के बावजूद IPL की फाइनेंशियल गति को बनाए रखने में मदद करती हैं।

आर्यन वार्ष्णेय फाइनल GM नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 92वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने

21 साल के आर्यन वार्ष्णेय आर्मेनिया में एंड्रेनिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट में अपना फाइनल नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 92वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। उन्होंने 8 में से 6.5 अंक हासिल करके यह खिताब जीता और इस उपलब्धि के साथ दिल्ली से आठवें ग्रैंडमास्टर बन गए।

ग्रैंडमास्टर खिताब के बारे में

ग्रैंडमास्टर (GM) खिताब FIDE (फेडरेशन इंटरनेशनेल डेस एचेक्स / इंटरनेशनल चेस फेडरेशन) द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खिताब है, और एक बार हासिल करने के बाद यह जीवन भर के लिए रहता है। GM बनने के लिए, एक खिलाड़ी को तीन GM नॉर्म हासिल करने होते हैं और अपने करियर में किसी भी समय FIDE एलो रेटिंग 2500 या उससे ज़्यादा तक पहुँचनी होती है। एक GM नॉर्म एक खिलाड़ी द्वारा FIDE-अनुमोदित शर्तों के तहत एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेटेड टूर्नामेंट में अपेक्षित स्तर पर प्रदर्शन करके अर्जित किया जाता है - जिसमें आमतौर पर मौजूदा GM सहित अन्य खिताब वाले खिलाड़ियों का सामना करना पड़ता है।

जैकुब मेन्सिक ने 2026 ASB क्लासिक (ऑकलैंड ATP 250) में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता

चेक टेनिस खिलाड़ी जैकुब मेन्सिक ने फाइनल में अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बाएज़ को 6-3, 7-6(7) से हराकर 2026 ASB क्लासिक (ऑकलैंड ATP 250) में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 20 साल के खिलाड़ी ने दूसरे सेट के टाईब्रेक में लगातार तीन सेट पॉइंट बचाकर न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड में हार्ड-कोर्ट टूर्नामेंट में जीत हासिल की। मेन्सिक की जीत ने 2026 सीज़न में बाएज़ की पिछली सात मैचों की जीत की लय को खत्म कर दिया, और उन्हें 2009 में जुआन मार्टिन डेल पोट्रो के बाद सबसे कम उम्र का ऑकलैंड चैंपियन बना दिया। इस जीत के बाद मेन्सिक ATP रैंकिंग में नंबर 17 पर पहुंच जाएंगे।

2026 ASB क्लासिक

- संस्करण: 39वां (महिला) और 48वां (पुरुष)
- स्थान: ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड

चैंपियन:

- पुरुष एकल: जैकब मेनसिक (चेक गणराज्य)
- महिला एकल: एलिना स्वितोलिना (यूक्रेन)
- पुरुष युगल: थियो अरिबेज / अल्बानो ओलिवेट्टी (फ्रांस)
- महिला युगल: गुओ हान्यू / क्रिस्टीना म्लाडेनोविक

वीनस विलियम्स 2026 में 45 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉ में सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनेंगी

वीनस विलियम्स को 18 जनवरी 2026 से मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड-कार्ड एंट्री दी गई है। 45 साल की उम्र में, वह टूर्नामेंट के मेन ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन जाएंगी।

रिकॉर्ड टूटा:

वह जापान की किमिको डेट का पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगी, जिन्होंने 2015 में 44 साल की उम्र में खेला था।

परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण दिन

दिवस	मनाया जाता है	थीम/उद्देश्य
01- फ़रवरी	भारतीय तटरक्षक दिवस	1 फरवरी 1977 को अंतरिम भारतीय तट रक्षक की स्थापना को चिह्नित करने हेतु
02- फ़रवरी	विश्व आर्द्रभूमि दिवस	वेटलैंड्स और पारंपरिक ज्ञान: सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना
04- फ़रवरी	विश्व कैंसर दिवस	अद्वितीय द्वारा संयुक्त
06- फ़रवरी	महिला जननांग विकृति के प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	गति बढ़ाएँ
10- फ़रवरी	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस	STH को खत्म करें: बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य में निवेश करें
11- फ़रवरी	विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने हेतु
13- फ़रवरी	राष्ट्रीय महिला दिवस	भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती को चिह्नित करने हेतु
13- फ़रवरी	विश्व रेडियो दिवस	रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
20- फ़रवरी	विश्व सामाजिक न्याय दिवस	गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु
21- फ़रवरी	अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस	दुनिया भर में भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु
24- फ़रवरी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस	वर्ष 1944 में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की स्थापना को चिह्नित करने हेतु
27- फ़रवरी	विश्व एनजीओ दिवस	दुनिया भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ जश्न मनाने और सहयोग करने हेतु
28- फ़रवरी	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	विकसित भारत के लिए विज्ञान और इनोवेशन में ग्लोबल लीडरशिप के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना।

पुस्तकें एवं लेखक

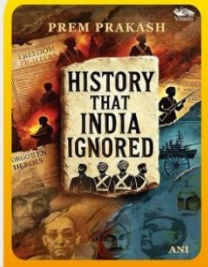

पुस्तक: हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरड
लेखक: प्रेम प्रकाश
बारे में: यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कम जाने-पहचाने नज़रियों से देखती है, और पारंपरिक ऐतिहासिक कहानियों को चुनौती देती है।

पुस्तक: सलमान खान: द सुल्तान ऑफ़ बॉलीवुड
लेखक: मोहर बसु
बारे में: यह पुस्तक एक्टर के आइकॉनिक स्क्रीन किरदारों, यादगार डायलॉग्स, चार्ट-टॉपिंग गानों और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली फिल्मों के ज़रिए उनके सफ़र को दिखाती है।

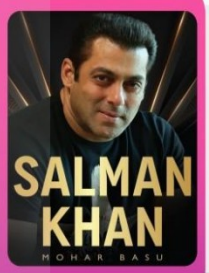

पुस्तक: वन्स एलिफेंट्स लिव्ड हियर
लेखक: गीतांजलि श्री
बारे में: लोगों और हाथियों की एक सरल, भावनात्मक कहानी, जो दिखाती है कि विकास कैसे जंगलों, यादों और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को नष्ट कर देता है।

पुस्तक: द घोस्ट्स ऑफ़ इंडियन स्मॉल टाउन्स: ए जर्नी थ्रू टाइम
लेखक: रस्किन बॉन्ड
बारे में: रस्किन बॉन्ड भारतीय छोटे शहरों की प्यारी यादें और कहानियाँ शेयर करते हैं, जिनमें उनके अतीत, लोगों और धीरे-धीरे खत्म हो रहे आकर्षण को दिखाया गया है।

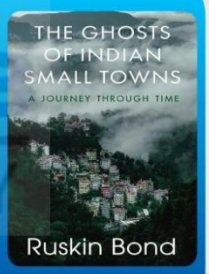

पुस्तक: मेक इट अप एज़ यू गो अलॉन्ग: ए सॉर्ट-ऑफ मेमोइर
लेखक: शेफाली शाह
बारे में: इस पुस्तक में शेफाली शाह अपने जीवन, करियर, संघर्षों और आत्मविकास पर विचार करती हैं, और अपनी व्यक्तिगत यात्रा से जुड़े सच्चे अनुभव, सीख और आत्म-खोज साझा करती हैं।

पुस्तकें एवं लेखक

पुस्तक: फील्डवर्क एज़ ए सेक्स ऑब्जेक्ट
लेखक: मीना कंदसामी
बारे में: मीना कंदसामी एक महिला रिसर्चर के तौर पर अपने अनुभव शेयर करती हैं, और एकेडमिक जगहों पर महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली सेक्सिज्म, पावर में असंतुलन और चुनौतियों को सामने लाती हैं।

पुस्तक: द फर्स्ट हाउस
लेखक: अवनी दोशी
बारे में: यादों, पारिवारिक रिश्तों, उम्र बढ़ने और इमोशनल बॉन्ड्स के बारे में एक सोचने वाली कहानी, जो यह बताती है कि कैसे बीता हुआ कल पहचान और पर्सनल कनेक्शन को आकार देता है।

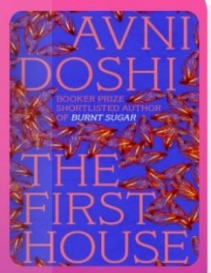

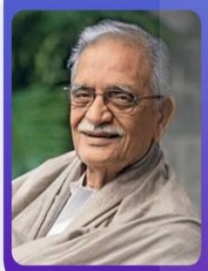

पुस्तक: आमची मुंबई: माई सिटी इन स्टोरीज एंड पोएम
लेखक: गुलज़ार
बारे में: गुलज़ार कविताओं और कहानियों के ज़रिए मुंबई को पेश करते हैं, जिसमें वे लोगों, भावनाओं, संघर्षों, सुंदरता और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गहरे प्यार से दिखाते हैं।

पुस्तक: बेगम समरू बायोग्राफी
लेखक: इरा मुखोटी
बारे में: बेगम समरू की एक दिलचस्प जीवनी, एक शक्तिशाली महिला जिन्होंने साधारण परिवार से उठकर मुगल-काल की राजनीति पर राज करा और उसे आकार दिया।

पुस्तक: रेड अलर्ट
लेखक: सुनील गुप्ता और समन्वय राउत्रे
बारे में: यह भारत में भ्रष्टाचार, अपराध और राजनीतिक संबंधों को उजागर करने वाली एक खोजी रिपोर्ट है, जो छिपे हुए पावर नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का खुलासा करती है।

TOPPERS CLUB
IAS ACADEMY

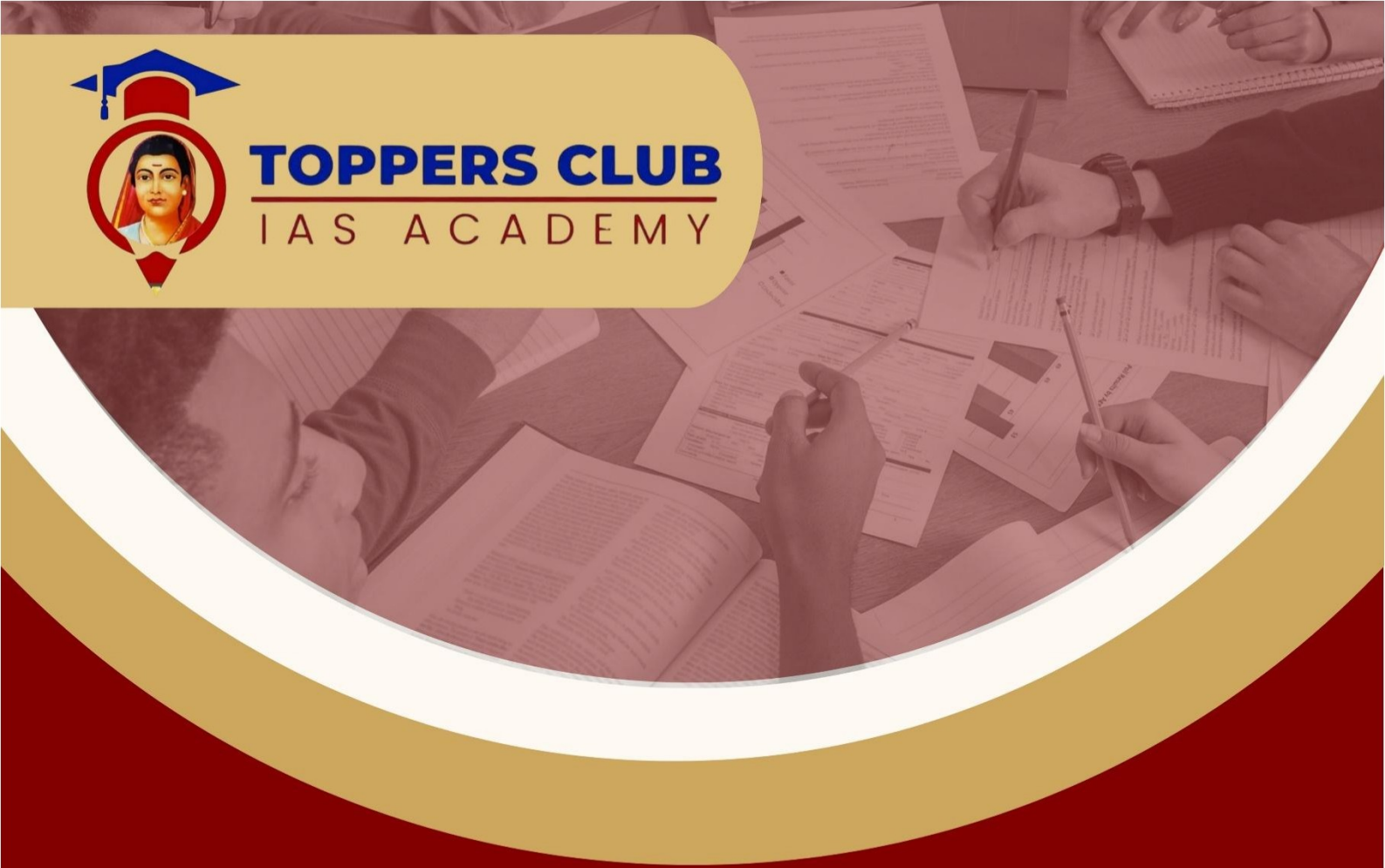

Monthly CURRENT AFFAIRS

By - Toppers Club

Staying updated with current affairs is crucial for academic and professional growth. It enhances knowledge, sharpens critical thinking, and improves decision-making. Awareness of global issues aids in competitive exams, essays, and interviews. Beyond academics, it reflects adaptability and curiosity—key traits in today's fast-changing world. Being informed broadens perspective, builds confidence, and opens up new opportunities.

+91 6388671098
dpsctc@gmail.com
Toppers CLUB IAS
www.topperclubiasacademy.in
Sec 12 HNO 687 MUNSHI PULIYA INDIRA NAGAR LUCKNOW 226016